R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 16
16 से 31 मई 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

मिशन 2024 का घमासान : गारंटी बनाम गारंटी

सूत न कपास...
जुलाहों में लट्ठम लट्ठ

वादों नहीं, गारंटियों पर लड़ा जा रहा लोकसभा का चुनाव

राजनीतिक पार्टियों की गारंटी पर हावी हो गए हैं पुराने मुद्दे

ANU SALES
CORPORATION
R1+S
R1+S
R2 Cycle 1
R2 Cycle 1
R1+S
R1+S
R2
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
1 2 3 • 17 18 19 20 • 33 34 35 36 37 • 45 46
R1+S L1 R2 L2
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest
Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

पहल

8 | फिर शुरू होगा सीपीए

करीब 2 साल पहले जिस सीपीए (राजधानी परियोजना प्रशासन) को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से बिना सलाह-मशविरा किए...

लालफीताशाही

15 | कैसे सुधरेगा रिजल्ट

मप्र में हर साल जब भी 10वीं, 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आता है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, सुविधाओं के अभाव की चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ दिन चर्चा के बाद मामला अधर में लटक जाता है।

लापरवाही

18 | बिना अमला आबकारी...

मप्र में सरकार की हर साल तकरीबन 15 हजार करोड़ रुपए की कमाई शराब की बिक्री से होती है। सरकार इस रकम को पाकर फूले नहीं समाती है। जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में हर साल हजारों करोड़ रुपए की अवैध शराब का गोरखधंधा...

विवाद

20 | वनों में आग और हाहाकार

ग्रीष्म ऋतु के अपने चरम की ओर तेजी से बढ़ते जाने के साथ ही जंगलों में भड़की आग भी अपना विकराल रूप लेती जा रही है। हालात यह हैं कि जंगल की आग से उत्पन्न धुएं के घटाटोप में पहाड़ भी डूबते नजर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को श्वांस जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

लोकसभा चुनाव का महासंग्राम आधा रास्ता पार कर गया है। मुद्दाविहीन इस चुनाव में गारंटियों की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं...तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं। किसकी गारंटी में कितना दम है? यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हर चुनावी सभा, रैली में पार्टियों के नेता अपनी-अपनी गारंटी को पूरा करने का दम भर रहे हैं।

32-33

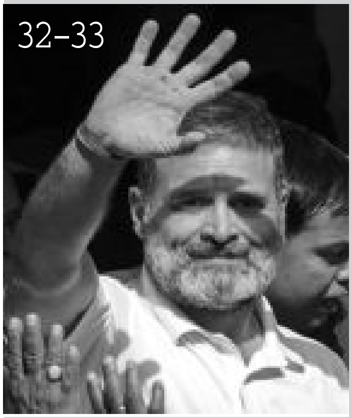

37

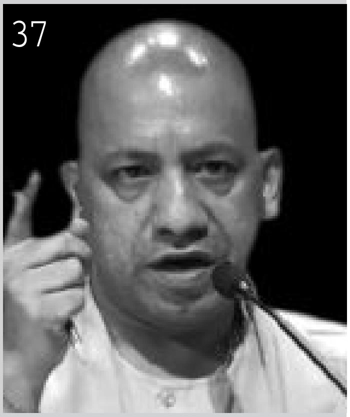

44

45

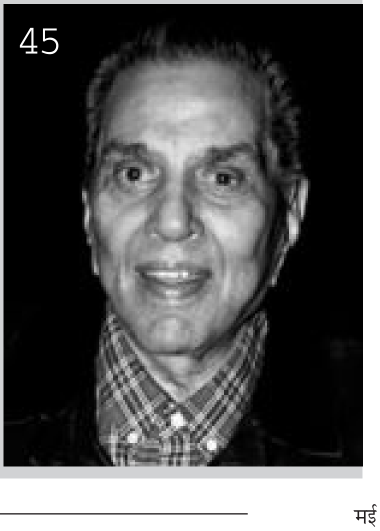

राजनीति

30-31 | इंडिया शाइनिंग बनाम 400 पार

उत्साह हमेशा अच्छा होता है लेकिन अति उत्साह अक्सर काम बिगाड़ देता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ताकतवर मंत्री और तब की भाजपा के रणनीतिकार प्रमोद महाजन को यही अति उत्साह भारी पड़ा था। 2004 के आम चुनाव में उन्होंने अटल सरकार की उपलब्धियां...

महाराष्ट्र

35 | मटका फोड़ राजनीति

राजनीति में यह कहना मुश्किल है कि किस पार्टी या नेता को किस चीज से फायदा होगा और उस पार्टी की जीत आसान होगी। सामने वाले उम्मीदवार को किसी वाक्य या घटना से अचानक सहानुभूति मिल जाती है और अंतिम समय में उसका पलड़ा भारी हो जाता है।

बिहार

38 | फिर जागी जाति की राजनीति

बिहार में लोकसभा का चुनावी परिदृश्य पिछले दो चुनावों की तरह साफ नहीं है। पहली बार परिवर्तन के लिए लोगों ने मोदी पर भरोसा किया तो दूसरी बार मोदी ने लोगों का खुद विश्वास जीता। दोनों बार जातीय किलेबंदी वैसी असरदार नहीं रही...

6-7	अंदर की बात
41	महिला जगत
42	अध्यात्म
43	कहानी
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

अपनी बात

4 जून के बाद... टॉप गियर में सरकार

शायर अहमद ज़फ़र का एक शेर है...

कौन डूबेगा किसे पार उतरना है 'ज़फ़र'
फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा

*कुछ इसी तरह मप्र में सरकार चुनावी चकल्लस खत्म होने के बाद काम में जुटेगी। सत्ता संभालते ही सुशासन पर जोर देने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने स्वच्छ शासन और प्रशासन की चुनौती रहेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले के करीब दो-तीन महीने के शासनकाल में मुख्यमंत्री ने सुशासन के लिए जो कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ तो कारगर सिद्ध हुए हैं, वहीं कुछ दाग लगा गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को स्वच्छ शासन और प्रशासन के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे। ऐसा करने के लिए 4 जून के बाद सरकार टॉप गियर में काम करती नजर आएगी। गौरतलब है कि डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही पूरे घर को बदलने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने तथाकथित तौर पर अफसरों की पूर्व की कार्यप्रणाली का भी आंकलन कराया था। उसके बाद उन्होंने नौकरशाही में बड़े बदलाव किए थे। वहीं सरकार ने ऐसे कई अफसरों पर गाज भी गिराई जिन्होंने जनता का अपमान किया या करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री के इस कदम को हर तरफ सराहा गया। लेकिन वहीं वल्लभ संप्रदाय में जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई उनमें से कईयों के कारण सरकार की छवि भी खराब हुई। खासकर पांचवी मंजिल की मनमानी सुर्खियों में रही है। ऐसे में सरकार फील्ड से लेकर वल्लभ संप्रदाय में पूरी तरह बदलाव करेगी। यह बदलाव स्वच्छ प्रशासन के लिए किया जाएगा। ऐसा करने के लिए मुख्यमंत्री को काफी मंथन करने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने जिन लोगों पर विश्वास किया और धारा-16 जैसी छूट प्रदान की, उस कारण जिस तरह की लूटपाट मची, उससे सरकार की छवि खराब हुई है। हालांकि सरकार ने समय रहते ही धारा-16 की छूट के बाद मची लूटपाट को खत्म करने के लिए फिर से धारा-16 को प्रतिबंधित कर दिया है। गौरतलब है कि **राष्ट्रीय पाक्षिक अक्स** ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और उचित कदम उठाया। आचार संहिता हटने के साथ ही मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता विभागों को दिए गए लक्ष्य का आंकलन करना है। इसलिए अब वे विभागों के कामकाज की समीक्षा शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री की समीक्षा के प्रमुख विषय- गेहूं खरीदी तथा भुगतान की स्थिति, खरीफ की बुबाई के लिए खाद-बीज की स्थिति, सिंहस्थ 2028 तथा शिप्रा नदी की सफाई के लिए अब तक किए गए कार्य आदि होंगे। मिशन 2047 के लिए मध्यप्रदेश में की गई तैयारियों की समीक्षा तथा केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। विभागों के एक साल, दो साल, तीन साल व पांच साल के कामकाज के रोडमैप पर चर्चा, भाजपा के संकल्प पत्र के कार्यों की समीक्षा और मुख्यमंत्री द्वारा संभागवार की गई समीक्षा में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, उसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत दागी अफसरों की सूची बनाने का काम भी तेजी से शुरू होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने दागदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफसरों की एक समिति भी बनाई है। मुख्यमंत्री जैसे ही काम में जुटेंगे, वे एक-एक बिंदु पर विस्तार से समीक्षा करेंगे और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी करेंगे।*

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स
वर्ष 22, अंक 16, पृष्ठ-48, 16 से 31 मई, 2024
प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल
सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाताः- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़ः**- संजय शुक्ला, मार्कण्डेय तिवारी,
जयपुरः- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

आदिवासी खुश...

जंगलों में रहने और रोजमर्रा की जरूरतों के चलते आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अपराध वन विभाग दर्ज करता है। इसमें लकड़ी चोरी, वनभूमि पर अतिक्रमण और शिकार के मामले होते हैं। सरकार ने आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण वापस लेने का निर्णय लिया है। जिससे वे खुश हैं।

● **अजय पाल,** इंदौर (म.प्र.)

पुलिस की छवि बदली

भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने का असर पूरे प्रदेश पर पड़ा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 27 महीने में अपराधों पर अंकुश लगा है। इससे जहां एक ओर आमजन को राहत मिली है, वहीं लोगों में पुलिस की छवि भी बदली है, जो कि अच्छी बात है।

● **राहुल सिंह,** भोपाल (म.प्र.)

मेट्रो का इंतजार

शहरवासियों से अब मेट्रो का इंतजार नहीं हो रहा है। शहर का मेट्रो प्रोजेक्ट 2018 में मंजूर हुआ था, और इसको 2022 में पूरा होना था। लेकिन अब अफसरों ने घोषणा की है कि यह मार्च 2027 तक पूरा होगा। सरकार को तेजी से इस काम को पूरा करना चाहिए।

● **प्रीतम साहू,** राजगढ़ (म.प्र.)

बुंदेलखंड में विकास कब?

बुंदेलखंड में पानी के साथ ही पलायन, भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा छाया हुआ है। पानी की किल्लत ऐसी कि लोग रात 10 बजे तक पानी के लिए दर-दर भटकते नजर आते हैं। भ्रष्टाचार ऐसा कि रेत, गिट्टी और डीजल को पीस यानी टुकड़े में मापकर न सिर्फ बिल लगाए गए हैं बल्कि उनका भुगतान भी हो चुका है। पन्ना जिले की सिमरिया तहसील में रात 10 बजे लोग साइकिल पर पानी ले जाते नजर आते हैं। हैंडपंप पर रात को भीड़ दिखने को मिलती है। यहां बोरवेल सूख गए हैं। बुंदेलखंड में दमोह, खजुराहो और पन्ना जिले में पलायन अब भी बड़ी समस्या है। कई क्षेत्रों में तो महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे कई किलोमीटर पानी ढोकर लाते हैं। सवाल यह है कि बुंदेलखंड में विकास कब देखने को मिलेगा।

● **मनीषा राजपूत,** रायसेन (म.प्र.)

कब तक शुद्ध होंगी नदियां

इंदौर में प्रवाहित होकर उज्जैन से पहले मोक्षदायिनी शिप्रा में मिलने वाली कान्ह और सरस्वती नदियों को शुद्ध करने की कवायद चार दशक से ज्यादा पुरानी है। कान्ह और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण पर 15 वर्षों में 1152 करोड़ खर्च हो चुके हैं। देश की पहली वाटर प्लस सिटी का तमगा हासिल करने के लिए दो वर्ष पहले 200 करोड़ खर्च कर नाला टैपिंग की गई थी। वर्ष 2028 में सिंहस्थ है इसलिए नदी को साफ करने की कोशिश फिर शुरू हो गई है।

● **महेंद्र सोलंकी,** सीहोर (म.प्र.)

किसानों की मुसीबत बढ़ी

प्रदेश में सहकारी समितियों के जरिए किसानों से खरीदे गए 4.80 लाख क्विंटल गेहूं की क्वालिटी पर दो संस्थानों में फंसे पेच ने हजारों किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। डब्ल्यूएलसी का दावा है कि उक्त गेहूं गुणवत्ता के निर्धारित मापदंड पर खरा नहीं है। यदि इसे लिया गया तो भविष्य में एफसीआई इसे फेल कर सकता है या फिर राशन की दुकानों से होते हुए गरीबों की थाली तक पहुंचा तो आफत आ सकती है। प्रदेश सरकार को किसानों की मुसीबत को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **विक्रांत सैनी,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

पीर पराई चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता ?

लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं राजनेताओं एवं उम्मीदवारों के दागदार चरित्र की परतें खुलती जा रही हैं। एक समय था कि जब लोग देश के नेताओं के सार्वजनिक जीवन में आचरण का अनुसरण करते थे। नेताओं को भी समाज में अपनी छवि व प्रतिष्ठा की फिक्र रहती थी। लेकिन हाल के वर्षों में राजनीति में कई क्षत्रप परिवारों के ऐसे नेता भी सामने आए हैं जिन्होंने सत्तामद में चूर होकर तमाम नैतिकताओं व मर्यादाओं को ताक पर रखा। यौन उत्पीड़न, दुराचार, भ्रष्टाचार एवं देशद्रोह पर सवार नेताओं एवं दागदार उम्मीदवारों से जुड़ा यह चुनाव लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न है। हमारी राजनीति एक त्रासदी बनती जा रही है। राजनेता सत्ता के लिए सबकुछ करने लगा और इसी होड़ में राजनीति के आदर्श ही भूल गया, यही कारण है देश की फिजाओं में विषमताओं और विसंगतियों का जहर घुला हुआ है और कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं देती। डर लगता है राजनीतिक भ्रष्टाचारियों से, अपराध को मंडित करने वालों से, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से, देश की एकता एवं अखंडता को दांव पर लगाने वालों से एवं यौन उत्पीड़न व दुराचार से नारी अस्मिता को नौंचने वालों से।

वरुण ने ठुकराया पार्टी का प्रपोजल

उप्र की रायबरेली सीट पर वरुण गांधी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। चर्चा थी कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद उन्हें भाजपा रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारने की योजना बना रही है। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वरुण गांधी ने पार्टी का यह ऑफर ठुकरा दिया है। वरुण के इस फैसले के बाद राजनीतिक पंडितों का कहना है कि गांधी बनाम गांधी के संघर्ष से वरुण दूर रहना चाहते थे। भाजपा की नजर अमेठी के बाद रायबरेली सीट पर है। यहां तक कि भाजपा कई सर्वे भी करवा चुकी है कि रायबरेली में कौन उम्मीदवार गांधी परिवार को कड़ी टक्कर दे सकता है। इससे पहले अमेठी सीट पिछली बार भाजपा ने राहुल गांधी से छीन ली थी। रायबरेली में समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे और कांग्रेस से अदिति सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी पहले ही अपने खेमे में कर चुकी है। पिछले कुछ चुनावों से लगातार वहां कांग्रेस का जनाधार भी घटा है, जिससे भाजपा के हौंसले बुलंद हुए हैं। असल में भाजपा ने अभी तक रायबरेली से उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और इसी वजह से यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह अमेठी की तरह इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस का गेम आसान नहीं रहने देना चाहती। इससे पहले भाजपा ने वरुण की पीलीभीत सीट से जितिन प्रसाद को टिकट दिया, जहां पहले ही चरण में चुनाव करवाए भी जा चुके हैं।

क्या दिखेगा बृजभूषण का दबदबा

कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें पयागपुर, कैसरगंज, कटरा बाजार, कर्नलगंज और तरबगंज सहित पांच विधानसभा सीटें शामिल हैं, में 20 मई को पांचवें चरण में मतदान होना है। महीनों की अटकलों के बाद भाजपा और (सपा ने आखिरकार कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों का खुलासा कर दिया है, जिससे उप्र में एक गर्म चुनावी लड़ाई का मंच तैयार हो गया है। मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच भाजपा ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज से अपना उम्मीदवार बनाया है। यह कदम अतीत से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है, जहां बृजभूषण शरण सिंह का निर्वाचन क्षेत्र पर प्रभाव था। समाजवादी पार्टी ने एक रणनीतिक कदम उठाते हुए कैसरगंज लोकसभा सीट से रामभगत मिश्रा को अपना उम्मीदवार चुना है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सदस्य मिश्रा, जो पहले भाजपा और बाद में सपा में शामिल हो गए, से भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश करने की उम्मीद है। विशेष रूप से, बसपा ने सबसे पहले कैसरगंज के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिसमें नरेंद्र पांडे का नाम था। यह कदम मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अपने पक्ष में करने के बसपा के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य आगामी चुनावों में अपनी छाप छोड़ना है।

सितंबर तक इंतजार क्यों... ?

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस दावे के बीच कि अगर एनडीए सत्ता में आता है तो नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो जाने के बाद अमित शाह को कमान सौंप देंगे, कांग्रेस ने कहा कि इंतजार इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि 4 जून को नई सरकार और प्रधानमंत्री का गठन हो जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि केजरीवाल का इस विरोधाभास को उजागर करना सही था। थरूर का कहना है कि अगर मोदी सितंबर 2025 में 75 वर्ष के हो जाते हैं, तो उनके आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सितंबर 2025 में क्या हम प्रधानमंत्री का परिवर्तन देखेंगे या एक व्यक्ति के लिए अपवाद होगा ? उन्होंने कहा कि दरअसल, हमने एक के बाद एक दो बयान देखे, एक तो शाह कह रहे हैं कि मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर किसी को 75 साल की उम्र में पद छोड़ देना चाहिए, फिर अगले दिन हमने शाह को यह कहते हुए देखा कि मोदी 2029 तक बने रहेंगे।

सियासी मायने

यदि पिछले तीनों लोकसभा चुनावों यानी 2014, 2019 और 2024 में कतिपय कांग्रेसी नेताओं के बयानों पर गौर किया जाए तो मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर से लेकर सैम पित्रोदा तक पार्टी नेताओं की ऐसी फेहरिस्त है, जिनके बयानों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को अकस्मात चुनावी संजीवनी मिली। दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल लोकतंत्र समझा जाने वाला भारतीय लोकतंत्र में कतिपय नेताओं द्वारा वक्त-वक्त पर किस प्रकार से जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पहाड़, मैदान, तुष्टीकरण और नस्लीय वैचारिक विकृति पिरोयी गई, यह राजनीतिक और सामाजिक शोध का विषय है। क्योंकि सिर्फ बहुमत प्राप्ति की गरज से नेताओं ने जिन नीतिगत उलटबांसियों को तवज्जो दी, उससे शांतिपूर्ण और सहिष्णु भारतीय समाज का बहुत बड़ा अहित हुआ है। वहीं, इन बातों का दुष्प्रभाव चुनावी राजनीति पर भी पड़ा है। सच कहूं तो ऐसे नेताओं की शतरंजी सियासी चालों से न केवल क्षेत्रीयता बल्कि राष्ट्रीयता का भाव भी प्रभावित हुआ है।

चंदे के लिए धंधा जरूरी...

चंदे का चलन केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि प्रशासन में भी है। खासकर मैदानी इलाकों में पदस्थ अफसर अपने मातहतों से हर महीने चंदा वसूलते हैं। ऐसी ही चंदा वसूली इन दिनों विंध्य क्षेत्र के दो जिलों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि दोनों जिलों के प्रशासनिक मुखिया की चंदाखोरी प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, इन दोनों जिलों में खनिज संपदा भरपूर है। वहीं यहां की नदियों में रेत का अवैध खनन भी खूब होता है। कहा जाता है कि अवैध खनन से यहां के अफसरों पर जमकर लक्ष्मी बरसती हैं। इसको देखते हुए एक जिले के कलेक्टर साहब ने खनिज अधिकारी को टारगेट थमा दिया है कि अगर वे जिले में जो कुछ भी करेंगे, उसमें से मेरा हिस्सा पूरी ईमानदारी से दे देंगे। वहीं एक जिले के कलेक्टर साहब तो इनसे भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने तो अपने जिले के खनिज अधिकारी को एकमुश्त 5 लाख रुपए का महीना बांध दिया है। सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक मुखिया से मिले फ्रीहैंड के बाद दोनों जिलों में जमकर अवैध खनन हो रहा है। आलम यह है कि विंध्य क्षेत्र के एक जिले में माफिया द्वारा एक एएसआई की हत्या के बाद भी इन जिलों में अवैध खनन पर कोई रोक नहीं लगी है। इन जिलों में हो रहे अवैध खनन पर वहां के जनप्रतिनिधि भी मौन साधे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि आपसी मिलीभगत से अवैध का धंधा वैध की तरह चल रहा है।

टारगेट पर तीन माननीय

मप्र में लोकसभा चुनाव का घमासान समाप्त हो गया है। अब सभी की 4 जून को आने वाले परिणाम पर नजर है। उधर, सत्ता और संगठन दोनों मिलकर अपने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस का आंकलन कर रहे हैं। इस बीच तीन राज्यमंत्रियों के लिए बुरी खबर भी आ रही है कि वे सत्ता और संगठन के टारगेट पर आ गए हैं। दरअसल, इन तीनों राज्यमंत्रियों ने अपने क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी के खिलाफ जमकर लॉबिंग की है। कहने को तो इन्होंने चोरी-छिपे सांसद प्रत्याशी के खिलाफ काम किया है, लेकिन सबकी गतिविधियों की खबर सत्ता संगठन के पास पहुंच गई है। इनमें से एक महिला राज्यमंत्री की रिकॉर्डिंग तो वायरल ही हो गई है। जिसमें वे कह रही हैं कि अगर सांसद जीता तो हमारी वखत खत्म हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अब जब सभी की कार्यप्रणाली और सक्रियता की समीक्षा हो रही है तो ये तीनों परेशान हो उठे हैं। उन्हें इस बात की खबर मिल गई है कि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों की खबर सत्ता संगठन तक पहुंच गई है। अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि 4 जून को मतगणना के बाद उन पर गाज न गिर जाए। अब देखना यह है कि इनका डर सटीक बैठता है या नहीं।

कलेक्टर-एसपी में ठनी

महाकौशल क्षेत्र के एक जिले में इन दिनों कलेक्टर और एसपी के बीच पटरी नहीं बैठ रही है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि अपनी लव लाइफ के लिए सुर्खियों में रहने वाले आईएएस अधिकारी को पुलिस कप्तान और माइक-3 की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है। सूत्रों का कहना है कि लव लाइफ के आदी हो चुके आईएएस अधिकारी को यह पसंद नहीं आ रहा है कि उनके कार्यक्षेत्र में पुलिस कप्तान इस तरह घूमें। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे असली वजह यह है कि साहब खुद माइक-3 का साथ चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि 2014 बैच के उक्त आईएएस अधिकारी ने महिला अधिकारी पर हाथ डालने की खूब कोशिश की है, लेकिन अभी तक वे उसमें असफल रहे हैं। दोनों की दोस्ती तुड़वाने के लिए उन्होंने एसपी के खिलाफ शासन को चिट्ठी-पत्री भी लिख डाली है। लेकिन उसके बाद भी उनकी दाल नहीं गल पाई है। गौरतलब है कि साहब की रंगीन मिजाजी की चर्चा हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। हालांकि साहब अपनी ही बिरादरी की महिलाओं के साथ दो बार परिणय सूत्र में बंध चुके हैं, लेकिन अपनी रंगीन मिजाजी के कारण अब वे अलग-थलग पड़ गए हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसे में साहब को किसी साथी की कमी सता रही है। इसलिए वे लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि माइक-3 का सानिध्य उन्हें मिल जाए। अब देखना यह है कि माइक-3 का साथ साहब को मिल पाता है या नहीं।

चिट्ठी न पड़ जाए भारी

दिल्ली में हुए शराब घोटाले के बाद अब ईडी ने मप्र में शराब ठेकों में हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बैंक गारंटी मामले को अपने रडार में लिया है। इसी के तहत 8 साल पहले प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में 42 करोड़ के आबकारी घोटाले में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे कई आईएएस अफसरों की पेशानी पर भी बल आ गया है। क्योंकि उस समय हुए घोटाले में शराब ठेकेदारों के साथ ही कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई थी और कई अधिकारी निलंबित भी हुए थे। हालांकि समय के साथ इस घोटाले पर पर्दा डलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही ईडी ने इस घोटाले की जांच अपने हाथ में ली है, प्रदेश के अधिकारियों के साथ ठेकेदारों में भी हड़कंप मच गया है। ईडी की टीम कुछ आईएएस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर सकती है। इससे एक प्रमोटी आईएएस अधिकारी सबसे अधिक परेशान हैं। क्योंकि जब यह घोटाला हुआ था तो वे वहां एडीएम थे। उन्होंने इस संदर्भ में एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्हें इस बात का डर है कि जांच में यह चिट्ठी उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।

बड़ी कुर्सियां भी खतरे में

4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आचार संहिता का बंधन भी खत्म हो जाएगा। यह बंधन खत्म होते ही सरकार भी दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगेगी। इस दौड़ में सरकार की पहली नजर प्रशासनिक बदलाव पर रहेगी। दरअसल, सरकार आगामी सालों के लिए अफसरों की नए सिरे से जमावट करेगी। सूत्रों का कहना है कि इस कड़ी में पुलिस और प्रशासन की बड़ी कुर्सियों पर भी नई जमावट होगी। वैसे तो प्रदेश की दोनों बड़ी कुर्सियां इस साल के अंत तक खाली होंगी, लेकिन उससे पहले सरकार की कोशिश होगी कि इन कुर्सियों के लिए योग्य अफसरों का चयन कर लिया जाए। उधर, सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी इन दोनों कुर्सियों को हासिल करने के लिए विधानसभा चुनाव के बाद से ही लॉबिंग में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के विजन और भावी रणनीति पर कौन अफसर फिट बैठता है। वहीं इन दोनों के अलावा कई अन्य बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों को भी बदला जाएगा, क्योंकि वे सीएम के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं।

फिर शुरू होगा सीपीए

करीब 2 साल पहले जिस सीपीए (राजधानी परियोजना प्रशासन) को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से बिना सलाह-मशविरा किए बंद कर दिया था, अब उसे वर्तमान की मोहन सरकार फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर चुकी है। गौरतलब है कि भोपाल को व्यवस्थित तरीके से डेवलप करने के लिए साल 1960 में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सीपीए का गठन किया गया था। इसका काम भोपाल शहर की सड़कों को बनाना और उनका मेंटेनेंस करना था। इसके अलावा, उसके जिम्मे पर उद्यान, बिल्डिंग निर्माण, पुल-पुलियाएं बनाने आदि के काम भी आ गए। इस विभाग की नए शहर को खूबसूरती देने में बड़ी भूमिका रही है। नए मंत्रालय एनेक्सी बनाने से लेकर वीआईपी रोड जैसे कई बड़े काम उसने ही किए हैं। भारत भवन, शौर्य स्मारक, ट्राइबल म्यूजियम, मानव संग्रहालय, टीटी नगर स्टेडियम, सतपुड़ा, विध्यांचल आदि इमारतें भी सीपीए ने बनाई हैं। वहीं 132 एकड़ में बने एकांत, प्रियदर्शनी, चिनार, मयूर, प्रकाश तरण पुष्कर समेत 7 बड़े पार्कों की भी सीपीए देखरेख करता था। लेकिन उसे एक झटके में बंद कर दिया गया था।

करीब दो साल बाद सीपीए को शुरू करने की कवायद राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर के प्रयास से शुरू की जा रही है। गौरतलब है कि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने सीपीए चालू करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि एक अधिकारी की जिद के कारण 17 मार्च, 2022 को कतिपय कारणों से सीपीए बंद कर दिया गया था। इसको लेकर न तो जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई और न ही उन्हें विश्वास में लिया गया। पत्र में आगे कहा था कि राजधानी के सुनियोजित विकास के लिए 1960 में सीपीए बनाया गया था। एजेंसी ने सतपुड़ा, विंध्याचल, मंत्रालय, वाल्मी जैसे बड़े-बड़े भवनों का निर्माण किया। शहर में हरियाली विकसित की। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के अलावा जब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय विधायकों के साथ भोपाल के मास्टर प्लान पर चर्चा कर रहे थे, तब भी कृष्णा गौर ने उनके सामने सीपीए को चालू कराने का मुद्दा उठाया था।

इस आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री से सीपीए को शुरू करने का आग्रह किया था। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीपीए को बंद करने के मामले को गंभीरता से लिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के एक और फैसले को डॉ. मोहन यादव सरकार बदलने जा रही है। इस संबंध में राज्य शासन स्तर पर विधिवत निर्णय ले लिया गया है और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसका पूरा प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर मप्र में लगी चुनाव आचार संहिता हटने के बाद होने वाली पहली ही कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद सीपीए फिर औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने सीपीए चालू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि एक अधिकारी की जिद के कारण 17 मार्च, 2022 को कतिपय कारणों से सीपीए बंद कर दिया गया था। इसको लेकर न तो जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई और न ही उन्हें विश्वास में लिया गया। पत्र में आगे कहा गया कि राजधानी के सुनियोजित विकास के लिए 1960 में सीपीए बनाया गया था। एजेंसी ने सतपुड़ा, विंध्याचल, मंत्रालय, वाल्मी जैसे बड़े-बड़े भवनों का निर्माण किया। शहर में हरियाली विकसित की। सीपीए बंद होने के बाद इसके अधिकांश कर्मचारियों को लोक निर्माण विभाग में भेज दिया गया था। वही विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेज दिया गया था। परियोजना की सिटी फॉरेस्ट शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को वन विभाग में भेजा गया था। अब इन्हें वापस बुलाया जाएगा और बंद पड़े कार्यालयों को उन्हीं स्थानों पर फिर से शुरू किया जाएगा।

गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले भोपाल की खूबसूरती में दाग लगा रही सड़कों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राजधानी परियोजना प्रशासन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। सीपीए को बंद करने के लिए अधिकारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। हैरानी की बात यह है कि राजधानी में विकास कार्य देखने वाले इस विभाग को बंद करने से पहले स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सलाह तक नहीं ली गई थी। सूत्रों का कहना है कि एक अधिकारी की जिद के कारण 6 दशक से अधिक पुराने सीपीए को बंद कर दिया गया था। खैर देर आए, दुरुस्त आए की तर्ज पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर एक बार फिर से सीपीए को शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है।

● सुनील सिंह

जिसने बंद किया वही शुरू करेंगे

यह भी संयोग है कि नीरज मंडलोई जब लोक निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव थे तब सरकार द्वारा बंद करने के निर्णय के आदेश उनके ही हस्ताक्षर से जारी हुए थे। अब जब सीपीए को शुरू करने का फैसला लिया गया है तो वे प्रमुख सचिव नगरीय विकास व आवास हैं। शुरू करने का आदेश भी उनके ही हस्ताक्षर से ही जारी होने की संभावना है। गौरतलब है कि शहर की बदहाल सड़कों को लेकर अगस्त, 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा था कि राजधानी की सड़कों की जिम्मेदारी एक या दो एजेंसी के पास होना चाहिए। ढेर सारी एजेंसियों की क्या जरूरत है। उन्होंने सीपीए की कोई जरूरत न बताते हुए इसे तत्काल बंद करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, कामों और अधिकारियों-कर्मचारियों के बंटवारे की वजह से इसमें काफी समय लग गया। सड़कें और इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को सौंप दिए। पार्क नगर निगम और फॉरेस्ट में बंट गए।

हाथ छोड़ थामा कमल...अब पद का इंतजार

पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है। इनमें से कुछ कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी थे, कुछ जिलाध्यक्ष तो कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता। जब ये कांग्रेस में थे तो इनकी वहां धाक थी। लेकिन अपनी उपेक्षा का आरोप लगाकर इन्होंने हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम लिया है। अब इन नेताओं को पद और प्रतिष्ठा का इंतजार है। गौरतलब है कि राजनीति में बिना पद के प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। इसलिए कांग्रेस से भाजपा में आए पदाधिकारी सियासी पुनर्वास की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर, भाजपा के मूल कार्यकर्ता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पहले हमें स्थान दिया जाए। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि असली और बाहरी भाजपाईयों में वर्चस्व की जंग छिड़ सकती है।

गौरतलब है कि नई सरकार के गठन के बाद से कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से थोक में भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं को अब लोकसभा चुनाव परिणाम आने का इंतजार है। 4 जून के बाद प्रदेश में सियासत के नए समीकरण बनना तय हैं। कांग्रेस में लंबा समय काटकर भाजपा में आए कई नेताओं को अब अपने राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार है। हालांकि इन नेताओं का कहना है कि वे किसी शर्त के साथ भाजपा में नहीं आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा है पर इसके इतर कुछ नेता अभी से अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए सक्रिय हो गए हैं।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के बाद से नेताओं का कांग्रेस छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह चुनाव के दौरान भी थम नहीं रहा है। प्रदेश में तीन चरणों का चुनाव हो चुका है। अब केवल 8 सीटों पर 13 मई को मतदान हुए। नतीजे 4 जून को आना है। इसके बाद चुनाव आचार सहिंता भी समाप्त हो जाएगी। चुनाव परिणामों के बाद की रणनीति संगठन ने अभी से बनाना शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेताओं के पुनर्वास को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता कांग्रेस से आने वाले नेताओं के एकदम से राजनीतिक पुनर्वास की बात को नकार चुके है। ग्वालियर अंचल में कार्यकर्ताओं की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि पहले ध्यान मूल कार्यकर्ता का ही रखा जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है। यह विचार परिवार है और यहां आने वाले को पार्टी के विचार के साथ चलना पड़ता है। हम सामूहिक नेतृत्व से आगे बढ़ते है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कह चुके है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को हमेशा से ही महत्व देती आई है।

इन नेताओं को ताजपोशी की आस

कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं से सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का है। पचौरी के साथ कई पूर्व विधायक भी भाजपा में आए हैं। इनमे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया जैसे नेता शामिल हैं। वहीं पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, छतर सिंह दरबार ने भी लंबे समय बाद कांग्रेस को अलविदा कहा है। इसके अलावा बसपा से रामलखन सिंह ने भी विदाई ले ली। पूर्व विधायकों में विदिशा के शशांक भार्गव, नीलेश अवस्थी, दीपक सक्सेना, शिवदयाल बागरी, दिनेश अहिरवार, अजय यादव, अरुणोदय चौबे, पारूल साहू, रामनिवास रावत जैसे नाम भी शामिल हैं। इन नेताओं में कुछ राज्यसभा में जाने की हसरत पाले हैं, तो कई खाली पड़े निगम मंडल, आयोग और बोर्ड में एडजस्ट होने की जुगत में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समक्ष भाजपा की सदस्यता लेने वाले रामनिवास रावत का नाम तो मंत्री बनने वाले नेताओं के रूप में लिया जा रहा है। वहीं सुरेश पचौरी को भी भाजपा किसी सम्मानजनक पद से नवाज सकती है। इसके अलावा जिन नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां मिल सकती हैं उनमे 40 सालों तक कमलनाथ के साथ रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का नाम भी शामिल है। इंदौर के संजय शुक्ला को भी संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है।

4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। उसके बाद सत्ता और संगठन में बदलाव और नेताओं के पुनर्वास का खाका तैयार किया जाएगा। संगठन सूत्रों की मानें तो पार्टी की बड़ी बैठक 6 जून को बुलाई गई है। इस बैठक में सभी सांसदों, विधायकों को भी बुलाया गया है। इसके बाद पार्टी अगले तीन महीने के नए कार्यक्रम भी तय करेगी। संगठन यह भी तय करेगा कि कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ सीनियर नेताओं को कहां और कैसे एडजस्ट किया जाए। वहीं इन नेताओं के भाजपा में आने से पार्टी का मूल कार्यकर्ता चिंता में है। उसे अपने सियासी भविष्य की चिंता हो रही है। राज्यसभा की तीन सीटें दो साल बाद खाली हो रही हैं पर इनके लिए अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। तीन में से दो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से भाजपा और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। ये दोनों नेता अगर चुनाव जीतते हैं तो उपचुनाव होना तय है। भाजपा में सिंधिया के लोकसभा में जाने पर पार्टी किस नेता को राज्यसभा भेजेगी इसे लेकर चर्चाओं का दौर अभी बागी से शुरू हो गया है। भाजपा सिंधिया की जीत तय मानकर चल रही है।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मप्र में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं के स्वागत की तस्वीरें इन दिनों बेहद आम हो गई हैं। पिछले 1-2 महीने से शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जब कांग्रेस छोड़कर कोई नेता भाजपा में ना जा रहा हो। कांग्रेस के नाराज नेताओं को भाजपा में लाने की जिम्मेदारी पार्टी आलकमान ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपी है। हाल ही में दतिया से विधानसभा चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा को भाजपा न्यू ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया गया है और वो लगातार अपने काम को अंजाम देते हुए हजारों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करवा चुके हैं। कांग्रेस के लिए चिंता की बात इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस से भाजपा की तरफ जाने वालों की इस दौड़ में पार्टी के बड़े नेता तो टूट ही रहे हैं, उनके साथ पार्टी संगठन की रीढ़ कहे जाने वाले ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और विधानसभा स्तर तक के कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी अपने दर्जनभर समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए तो वहीं 19 मार्च को ही कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सैयद जाफर ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली।

● **कुमार विनोद**

मप्र में भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। भाजपा के सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले प्रदेश के 30 मंत्रियों की बैचेनी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि मिशन 2024 का रिजल्ट मंत्रियों की कुर्सी का भविष्य तय करेगा।

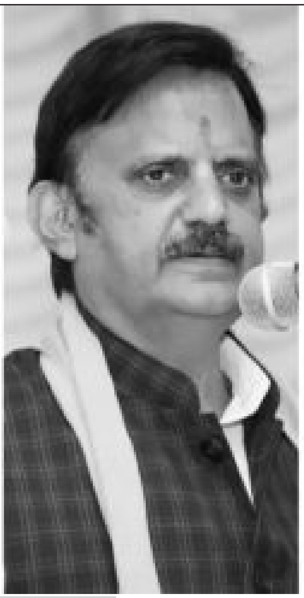

मंत्रियों की असली परीक्षा

आम चुनाव 2024 के मतों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव परिणाम से सिर्फ मप्र की 29 सीटों पर सांसदों का भविष्य ही तय नहीं होगा बल्कि डॉ. मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल पर भी असर पड़ेगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि मोहन सरकार में कौन मंत्री बना रहेगा और किसकी विदाई होगी? शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव परिणाम अभी से कई नेताओं की बेचैनी बढ़ा रहा है। दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया था कि मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार के मंत्रियों को अपनी सीट पर विधानसभा चुनाव 2023 के मुकाबले ज्यादा अंतर से भाजपा उम्मीदवार को जिताना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आलाकमान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जरिए दोनों उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला व जगदीश देवड़ा और 28 कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्रियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी की जीत का अंतर बड़ा होना चाहिए। पार्टी उम्मीद कर रही है कि 30 विधायकों को मंत्री बनाए जाने से इनके विधानसभा क्षेत्र में तो भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी।

भाजपा सूत्रों की मानें तो जिन बूथों पर वोट डाला गया है। उन बूथों पर क्या स्थिति रही? इसकी भी पार्टी जांच करेगी। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि नेता जीत तो जाते हैं, लेकिन उनके खुद के बूथ पर वे हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा, उसका असर मंत्रियों को मंत्रिमंडल फेरबदल में दिखेगा। जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और जिनके परिणाम खराब आएंगे, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भी कहा गया कि भाजपा आलाकमान ने मप्र के कुछ विधायकों को इशारों-इशारों में यह भी कह दिया कि यदि उनके क्षेत्र से बड़ी जीत मिलती है और पार्टी प्रत्याशी जीत जाता है तो मंत्रिमंडल फेरबदल में उनका कद जुलाई-अगस्त में बढ़ना तय है। मोहन सरकार के कई मंत्रियों के बारे में खुलकर कहा जा रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ औपचारिकता पूरी की है। उनकी बातों में अहंकार और काम में बेफिक्री सब दिखाई देती थी। कुछ तो ऐसे हैं जिनका मंत्री पद मिलते ही फोकस ही बदल गया है। अब वह केवल पार्टी के कार्यक्रमों में या सरकारी कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनका पूरा समय दूसरे कामों में खर्च हो रहा है।

भाजपा आलाकमान ने तय कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर ही मंत्री, विधायक और संगठन पदाधिकारियों को तरक्की मिलेगी। लोकसभा चुनाव में हार या जीत नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी असर डालेगी। चुनाव के नतीजों के अनुसार मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा। लोकसभा सीट जिताने वाले मंत्री को बड़े विभाग और पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार मंत्री के पर कतरे जाएंगे। विधायकों के लिए मंत्रिमंडल में शामिल होने का भी ये बड़ा मौका माना जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में बेहतर प्रदर्शन वाले नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है। चुनाव परिणाम के आधार पर संगठन के पदाधिकारियों समेत अन्य नेताओं का पद भी बड़ा किया जाएगा। निगम-मंडल में नियुक्ति के साथ ही उनको संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद निगम-मंडल, आयोग और सरकारी समितियों में कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की जाएंगी, इन नियुक्तियों का आधार अपनी सीट पर पार्टी के

चुनावी परफॉर्मेंस बनेगा आधार

मप्र में लोकसभा चुनाव के इस दौर में भी मोहन कैबिनेट में बदलाव की चर्चा है। नए चेहरे कौन होंगे, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कई सीनियर विधायकों ने मंत्री बनने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विधायकों की परफॉर्मेंस मंत्री पद का आधार बनेगी। इसे देखते हुए विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार को अच्छी लीड दिलाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद कुछ विधायकों की एंट्री कैबिनेट में हो सकती है। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि, केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी के कुछ विधायक सक्रिय नहीं हैं। हर विधायक को बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा। उसके आधार पर उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। पार्टी की तरफ से केवल चेतावनी ही नहीं दी गई है। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व हर लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर नजर रखे हुए हैं। हर विधायक के बारे में यह जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वह अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है? इनकी इस सक्रियता की तुलना 2023 के विधानसभा चुनाव के आधार पर की जा रही है।

प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

मप्र की सभी 29 सीटों पर मतदान होने के बाद उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इससे भी ज्यादा मप्र के कैबिनेट मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्र के लोकसभा सीट पर रिजल्ट का इंतजार है। दरअसल, लोकसभा चुनाव के बाद मप्र की मंत्रिमंडल की तस्वीर बदल जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन किया जा सकता है। वहीं कई दिग्गजों का मंत्री पद छिन भी सकता है। बताया जाता है कि जिस वक्त मप्र में कैबिनेट का गठन किया जा रहा था। उस वक्त कई बार मुख्यमंत्री ने दिल्ली का दौरा किया था। इसी दौरान साफ किया गया था कि मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की जीत बड़े अंतर से होनी चाहिए। भाजपा ने शायद इसी तर्ज पर 31 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। जिससे की अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्र कवर हो, जिससे जनता भी खुश हो सके और विधायक भी लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने में पूरी ताकत लगाएं। ऐसे में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट मप्र के साथ-साथ कैबिनेट मंत्रियों के लिए काफी अहम होगा। क्योंकि अगर जिस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की हार होगी उन मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है।

मप्र में चार चरणों में 29 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 197 सभाएं, 56 से अधिक रोड शो, 185 से अधिक विधानसभाओं में दस्तक और 13 जिलों में रात्रि विश्राम कर सबसे आगे रहे। लेकिन प्रदेश सरकार के दो उप मुख्यमंत्रियों समेत 30 मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय सबसे आगे रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए सबसे अधिक मेहनत की है। वे लगातार संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहे। वहीं मालवा-निमाड़ के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जमकर चुनाव प्रचार किया।

गौरतलब है कि इस बार भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए भाजपा ने पूरा दमखम भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताओं और मप्र के मंत्रियों ने रात दिन एक किया है। चुनाव प्रचार में प्रदेश में सबसे अधिक सभा और रोड शो करने में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले नंबर पर रहे हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को पीछे छोड़ दिया है। वैसे विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया था। इस कारण वहां उन्होंने ज्यादा समय दिया। लोकसभा चुनाव में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने 62, राजेंद्र शुक्ल ने 61, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 64 जबकि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने 60 जनसभाएं कीं और कार्यकर्ता बैठक तथा सम्मेलनों को संबोधित किया। इसके अलावा अन्य मंत्रियों और सीनियर विधायकों ने चुनाव प्रचार में भाग लिया, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्री से ज्यादा सभाओं में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए। वे कांग्रेस नेताओं को भाजपा में लाने के साथ ही चुनाव प्रचार में जुटे रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से लगातार प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 185 विधानसभाओं को कवर किया। डॉ. मोहन यादव ने 142 जनसभा और 55 रथ सभा, कुल 197 जनसभाएं कीं। वहीं 56 से अधिक रोड शो भी किए। वे 22 प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए। उन्होंने 13 अलग-अलग जिलों में रात्रि विश्राम भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने 13 जिलों में रात्रि विश्राम किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 72 जनसभा, 18 रोड शो, 16 रथ सभाएं और 65 सम्मेलन, बैठक और संवाद किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सहित 21 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर 66 जनसभाएं कीं। 16 रोड शो सहित कुल 3 लोकसभा क्षेत्रों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। 5 स्थानों पर रात्रि विश्राम किया।

मप्र में भाजपा के केंद्रीय संगठन ने इस पूरे चुनाव को सर्विलांस पर रखा था। इस बार मतदान में किस नेता ने कितना प्रचार किया? मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस रणनीति के तहत चुनाव प्रचार संचालित किया? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा को कितना सहयोग किया? नवनियुक्ति मंत्रियों ने अपने क्षेत्रों में कितना मतदान करवाया और मोदी की गारंटी पर लोगों को कितना आश्वस्त किया? इन सभी बिंदुओं पर भाजपा संगठन ने अलग-अलग निजी एजेंसियों और मप्र भाजपा के संगठन से रिपोर्ट तैयार करवाई है। मप्र में मतदान की समाप्ति के बाद दिल्ली में इन रिपोर्ट पर मंथन होगा। भाजपा मीडिया सेल से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

● कुमार राजेन्द्र

बिना मुद्दे का चुनाव, सिर्फ मोदी फेस

पिछले चुनावों के विपरीत इस बार का चुनाव मुद्दाविहीन हो रहा है। 2009 और 2014 में यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा जबरदस्त उछला था। इस दौरान 2-जी स्पेक्ट्रम, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला समेत कई घोटालों की चर्चा होती थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो 2019 में 5 साल पूरे करने के बाद राफेल का मुद्दा पूरे देश में छाया। लेकिन पुलवामा की आतंकी घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उस पर कांग्रेस की बयानबाजियों ने चुनाव का रुख मोड़ दिया। 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव बना, जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ मोदी का चेहरा है और अगर मुद्दे हैं, तो कांग्रेस उसे अब तक लोगों के बीच पहुंचा नहीं पाई। कांग्रेस हर मंच से महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी, दलित, सांप्रदायिकता पर बात करती रही, लेकिन ये बातें घरों तक नहीं पहुंच पाई। इन सबके जवाब में भाजपा मोदी का चेहरा सामने ले आई। मप्र की बात करें, तो जो हाल देश के बाकी हिस्सों का है, कमोबेश वही हाल मप्र का है। भाजपा को मोदी के चेहरे पर इतना भरोसा था कि टिकट मिलेगा, तो संगठन जिताकर ले आएगा। दिग्गजों को उतारने के बाद भी आखिरी तक कांग्रेस में इस आत्मविश्वास की कमी दिखती रही।

फिर तैनात होंगे संभागीय संगठन मंत्री

अब संघ पैटर्न पर बनेगी व्यवस्था

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भाजपा की रीढ़ कहा जाता है। आज भाजपा संगठन जिस मजबूती से खड़ा और बढ़ा है उसके पीछे संघ की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए भाजपा में बंद हुई संभागीय संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा एक बार फिर से शुरू करने पर उच्च स्तर पर विचार शुरू हो गया है, पर इस बार व्यवस्था को बदलाव के साथ लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका खाका तैयार कर रहा है। लोकसभा चुनाव निपटने के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में माना जाता है। संघ की तर्ज पर यह पार्टी कैडरबेस है और संगठन सर्वोच्च की तर्ज पर चलती है। भाजपा संगठन पर पूरी तरह नियंत्रण आरएसएस का होता है। पार्टी में पूरे देश में परंपरा है कि संगठन महामंत्री चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आता है और यह पद बेहद असरदार माना जाता है। पार्टी के कार्यक्रम जिलों में बेहतर तरीके से चलें, जनप्रतिनिधि अपने काम को ठीक तरीके से करें। इसके लिए पूर्व में हर संभाग में संगठन मंत्रियों की व्यवस्था होती थी।

मप्र में एक बार फिर से प्रदेश भाजपा में पुरानी संभागीय संगठन मंत्रियों की तैनाती की व्यवस्था बहाल हो सकती है। इसी के साथ पार्टी तीन प्रदेश सह संगठन मंत्रियों की भी तैनाती कर सकती है। इसके लिए संघ के अंदर भी मंथन का दौर जारी है। दरअसल संघ की दृष्टि से मप्र में तीन प्रांत हैं। इन प्रांतों के हिसाब से भाजपा में यह नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिससे कि संगठन का काम और अधिक बेहतर किया जा सके। इसी तरह से माना जा रहा है कि प्रदेश के सभी 10 संभागों में इस बार नए सिरे से संगठन मंत्रियों की व्यवस्था बहाल की जा सकती है। गौरतलब है कि पुरानी व्यवस्था में कुल आधा दर्जन संभागीय संगठन मंत्रियों से काम चलाया जा रहा था। इस मामले में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि संघ बेहद सोच विचार कर ही फैसला करता है। हमारी विचार धारा में व्यक्ति व पार्टी से सर्वोपरि राष्ट्र होता है।

दरअसल तीन साल पहले अगस्त 2021 में प्रदेश संगठन में संगठन मंत्रियों की चली आ रही पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। जिसके बाद से न केवल संगठन में बिखराव होने लगा, बल्कि कई बड़े नेताओं द्वारा अपने इलाकों में मनमानी भी की जाने लगी है। यही नहीं कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात रखने के लिए इसके बाद से भोपाल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यह संगठन मंत्री भाजपा व संघ के बीच न केवल जमीनी स्तर पर सेतु का काम करते थे, बल्कि आपसी तालमेल का काम भी देखते थे, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में मतभेद और मनभेद होते ही उसे तत्काल शांत करा दिया जाता था, जिसकी वजह से इस तरह के मामले तूल नहीं पकड़ पाते थे। पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने के पीछे की उस समय जो वजह बताई गई थी, उसके मुताबिक संभागीय कार्यालय सत्ता और संगठन के नए केंद्र के रूप में काम करने लगे थे। विधायकों से लेकर जिलों में काम करने वाले पदाधिकारियों में भी संगठन मंत्रियों के प्रभाव में आकर फैसले लेने का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी इनके हस्तक्षेप से प्रभावित हो रही थी।

लोकसभा चुनाव बाद आगामी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन और उनकी मॉनीटरिंग के लिए भाजपा में एक बार फिर से संभागीय संगठन मंत्रियों की नियुक्ति होगी। हालांकि इस बार संगठन मंत्रियों के कार्य करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किए जाने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए उच्चस्तर पर विचार शुरू हो गया है पर इस बार व्यवस्था को बदलाव के साथ लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका खाका तैयार कर रहा है। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में राजगढ़ में प्रदेश पदाधिकारी बैठक के दौरान संभागीय संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा पर रोक की अंतिम मुहर लगी थी, जिसके बाद संभागीय संगठन मंत्रियों को हटाने का प्रदेश संगठन की ओर से फैसला लिया गया। भाजपा प्रदेश संगठन में हुए इस बदलाव के बाद कई तरह की अटकलें शुरू हो गई थी। कहा यह भी जा रहा था कि हो सकता है संगठन स्तर पर कोई नई व्यवस्था बनाई जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बदली व्यवस्था के तहत संघ के पैटर्न पर अब संभागीय संगठन मंत्रियों की नई नियुक्ति की जाएगी, जिसमें संघ के प्रचारकों को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। गौरतलब है कि करीब दो साल पहले जब संभागीय संगठन मंत्रियों को हटाया गया था तब शैलेंद्र बरुआ-ग्वालियर, जितेंद्र लिटोरिया-उज्जैन, आशुतोष तिवारी-भोपाल, श्याम महाजन-रीवा व शहडोल, जयपाल चावड़ा-इंदौर और केशव सिंह भदौरिया-सागर संभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

गौरतलब है कि भाजपा में कुछ समय पहले तक हर संभाग और जिलों तक में संगठन मंत्री होते थे जो पार्टी के संगठन के काम को विस्तार देने के साथ विचारधारा को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का काम करते थे। इन संगठन मंत्रियों की भूमिका संगठन में बेहद महत्वपूर्ण होती थी। इनकी रिपोर्ट पर ही विधानसभा से लेकर स्थानीय चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय किए जाते थे। एक समय था जब पार्टी में 32 संगठन मंत्री हुआ करते थे। इनमें कई संगठन मंत्रियों को एक या दो जिलों का प्रभार दिया जाता था। उसके बाद संभागीय संगठन मंत्री होते थे। यह सभी संगठन मंत्री संघ की पृष्ठभूमि से आते थे। इनमें कई प्रचारक भी शामिल होते थे। इसके बाद इनकी संख्या में कमी आती चली गई और जिलों से इनकी विदाई कर दी गई। एक संभाग में सिर्फ एक संगठन मंत्री की तैनाती की व्यवस्था लागू कर दी गई। तीन साल पहले इसमें भी कटौती शुरू हो गई और एक संगठन मंत्री के पास दो-दो संभागों का प्रभार आ गया। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसकी वजह शिकायतें थीं। हालांकि प्रदेश में भाजपा ने हटाए गए सभी संभागीय संगठन मंत्रियों को निगम मंडलों में अध्यक्ष की ताजपोशी से नवाजा था। डॉ. मोहन यादव सरकार में इन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है।

● अरविंद नारद

माफिया ने मोड़ दी नदी की धारा

4 और 5 मई की रात 12 बजे शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना इलाके में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने एएसआई को कुचल दिया। ट्रैक्टर की ट्रॉली में अवैध रेत भरी हुई थी। जैसे ही पुलिसकर्मी उस ट्रैक्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ा, ड्राइवर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को एएसआई के ऊपर चढ़ा दिया। पिछले 5 महीने में किसी सरकारी कर्मचारी को कुचलने की ये दूसरी घटना है। नवंबर 2023 में इसी इलाके में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने चेकिंग में लगे पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी थी। शहडोल की सबसे बड़ी खदान ब्यौहारी से मानपुर रोड पर लगभग 20 किमी दूर पोड़ी कला गांव में है। इस खदान का ठेका सहकार ग्लोबल कंपनी के पास है। अवैध खनन की वजह से सोन नदी की धारा की दिशा ही बदल चुकी है। एनजीटी का नियम है कि नदी के भीतर से रेत खनन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां इस नियम की धज्जियां उड़ती नजर आई। पोड़ी के अलावा दूसरी खदानों में भी नदी के भीतर से ही रेत निकाली जा रही है। इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि जहां अवैध खनन की सूचना मिलती है वहां कार्रवाई की जाती है।

शहडोल से ब्यौहारी की दूरी 90 किमी है। इसके बाद पौड़ी गांव आता है। यहां सोन नदी पर एक पुल बना है। पुल से रेत खनन नजर नहीं आता। पुल के नीचे से नदी की तरफ आगे जाने के बाद खदान के पास पहुंचते ही बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें ठेकेदार की कंपनी, रकबा, खसरा नंबर और अवधि लिखी हुई है। गूगल अर्थ ऐप के जरिए पूरी खदान की सीमा लगभग 36 हैक्टेयर का बताई जा रही है, जबकि वहां लगे बोर्ड के मुताबिक खदान का खनन क्षेत्र सिर्फ 3.900 हैक्टेयर का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के मुताबिक रेत खदान से गीली रेत नहीं निकाली जा सकती। यानी नदी के भीतर खनन की इजाजत नहीं है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के मुताबिक, नदी की बीच धार से रेत निकालना प्रतिबंधित है। रेत निकालने के लिए ठेका कंपनी को जिन शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है, उनमें पहली शर्त यही है कि रेत का खनन पानी के अंदर से नहीं होगा। पानी वाले क्षेत्र में अधिकतम 3 मीटर की गहराई तक ही खनन किया जा सकता है। यदि ठेका कंपनी इसका उल्लंघन करती है तो उसका ठेका निरस्त कर एनजीटी में केस दायर किया जाता है।

ब्यौहारी में 4 मुख्य नदियां हैं- सोन, बनास, समधिन और झांपर। इन चारों नदियों में 35 मुख्य जगहों पर रेत का खनन होता है। हालांकि, स्थानीय लोगों की मानें तो इन नदियों पर वैध और अवैध मिलाकर करीब 80 खदानें हैं। यहां से हर दिन 500 गाड़ियां निकलती हैं। एक भी ऐसी गाड़ी नहीं होती जो ओवरलोड न हो। सोन नदी की बात करें तो यहां 7 प्रमुख जगह हैं, जहां से रेत का खनन होता है उनमें गोपालपुर, झिरिया, पोड़ी जैसे प्रमुख स्थान हैं। वहीं, बनास नदी में 8 तो झांपर नदी में 6 और समधिन नदी में 10 प्रमुख घाट हैं, जहां से रेत का खनन किया जाता है। ब्यौहारी की रेत खदानों से दो तरह के हाईवा लोड होकर दूसरे जिलों या राज्यों तक पहुंचते हैं। इनमें एक 10 टायर और दूसरा 12 टायर वाला हाईवा होता है। 10 टायर वाले हाईवा में 16 घनमीटर और 12 टायर वाले हाईवा में 20 घनमीटर रेत की रॉयल्टी काटकर रेत ले जाने का नियम है।

ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए रेत ठेकेदार 10 टायर वाले हाईवा में 18 या 19 घनमीटर रेत लोड करते हैं। वहीं, 12 टायर वाले हाईवा में 20 घनमीटर की बजाय 25 से 27 घनमीटर रेत लोड की जाती है। इस तरह से 2 से 8 घनमीटर ज्यादा रेत भरी जा रही है। इससे दो नुकसान हैं- एक तरफ सरकार को रॉयल्टी कम मिल रही है तो दूसरी तरफ रेत की खुलेआम चोरी की जा रही है। एक 10 टायर वाले हाईवा में 16 घनमीटर रेत भरने की अनुमति है। खनिज विभाग 200 रुपए प्रति घनमीटर के हिसाब से रॉयल्टी वसूल करता है। इस तरह से एक हाईवा के लिए 3200 रुपए रॉयल्टी सरकार को दी जाती है। हाईवा में 16 की बजाय 19 घनमीटर यानी 3 घनमीटर रेत ज्यादा भरी जाती है। इसके बदले खदान संचालक को 1100 रुपए प्रति घनमीटर के हिसाब से करीब 20 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब हाईवा संचालक इसमें अपना 10 हजार का मुनाफा जोड़ता है। इस तरह से 19 घनमीटर रेत से भरा एक हाईवा बाजार में करीब 30 हजार रुपए में बिकता है। यानी एक हाईवा में 1100 रुपए प्रति घनमीटर के हिसाब से 3300 से 4000 रुपए की अतिरिक्त रेत होती है। अब खनिज विभाग के मुताबिक रोजाना 100 हाईवा खदानों से निकलते हैं इस तरह से 4 लाख रुपए दिन का और महीने में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेत चोरी होती है।

मप्र खनिज नीति के अनुसार ठेकेदार द्वारा उनकी खदानों में नियमानुसार सीमांकन कराया जाएगा। इसके बाद चिन्हित स्थानों पर पिलर खड़े किए जाएंगे। जिला खनिज कार्यालय से जीपीएस के माध्यम से अक्षांश और देशांतर लिखा जाए। इससे संबंधित दस्तावेज भी तैयार करने के आदेश रेत खनन नीति 2015 में दिए गए हैं। लेकिन शहडोल में इस नियम का भी पालन किसी भी खदान में दिखाई नहीं देता।

● विकास दुबे

अवैध खनन में होता है ट्रांजिट पास का इस्तेमाल

मप्र में वैध रेत खदान के लिए ईटीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास जनरेट होता है। जिस वाहन से रेत का परिवहन होता है उसकी पूरी डिटेल इसमें दर्ज होती है। इसमें वाहन का रूट और जिस जगह रेत ले जानी है उसकी दूरी और समय भी लिखा होता है। इस तय समय के भीतर वाहन चालक को रेत पहुंचाना होती है। यदि तय समय में वह रेत नहीं पहुंचा सका तो रेत को अवैध माना जाता है। विशेष परिस्थितियों यानी गाड़ी खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक को इसकी सूचना खनिज विभाग को देनी होती है। पड़ताल में ये भी सामने आया कि एक ही ईटीपी का इस्तेमाल कर इस पर दो से तीन वाहनों की रेत को बेच दिया जाता है। मान लीजिए रेत से भरे हाईवा को ब्यौहारी से कटनी भेजना है, तो ईटीपी कटनी की बनाई जाती है। इतनी दूर जाने के बजाय एक हाईवा आसपास के इलाकों में कई चक्कर लगाकर रेत बेच देता है। यदि कोई अधिकारी गाड़ी रोकता है या पर्ची चेक करता है या हाईवा ड्राइवर से देरी की बात पूछता है, तो ड्राइवर ब्रेकडाउन का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। ऐसे में खनन माफिया ओवरलोड रेत परिवहन करके राजस्व के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी सड़कों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

अब मप्र में देना होगा फायर टैक्स

मप्र में अब हाउस, वॉटर टैक्स की तरह ही फायर टैक्स भी देना होगा और इसका प्रावधान बिल में किया गया है। फायर टैक्स से फायर डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा, जो राहत एवं बचाव कार्य के दौरान घायल या दुर्घटना का शिकार होंगे। प्रदेश में आगजनी की घटनाओं से निपटने और इन पर नियंत्रण के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसके तहत अलग से फायर डायरेक्ट्रेट खोला जाएगा। इसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही फायर टैक्स अधिरोपित किया जा सकता है। शुरुआत में अग्नि दुर्घटना व आपदा की स्थिति से निपटने के लिए संसाधन जुटाने पर 397.54 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बिल की खास बात यह होगी कि इमारतों के लिए फायर सर्टिफिकेट लेने के प्रावधान किए जाएंगे। नियमों का पालन न करने वालों से पेनाल्टी की वसूली की जाएगी। आग से निपटने का प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। इसके साथ ही सेफ्टी फंड भी रखा जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम में एकरूपता लाने के मद्देनजर मॉडल फायर एक्ट तैयार कराया है। इसमें जरूरी संशोधन कर लागू करने की तैयारी मप्र में 5 साल पहले से चल रही है। तब भी इसका प्रारूप तैयार कराया गया था। दावे-आपत्ति भी बुलाए गए थे। हालांकि, अमल अब तक नहीं हो पाया। अभी तक केवल राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवाओं का जिम्मा पुलिस फायर सर्विस से लेकर नगरीय निकायों को सौप दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए 397.54 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग से ग्रांट के तौर पर हासिल करने का प्रस्ताव बनाया है। इसमें 25 फीसदी हिस्सेदारी राज्य शासन की होगी। यह प्रस्ताव सैद्धांतिक सहमति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए बढ़ाया जाएगा।

मप्र में फायर एक्ट जल्द लागू होने वाला है। ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस एक्ट में खासतौर पर फायर टैक्स को शामिल किया गया है जो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ सेस के रूप में वसूल किया जाएगा। सरकारी इमारतों पर यह टैक्स नहीं लगेगा। नगरीय विकास संचालनालय ने इसका नाम मप्र अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम- 2022 तय किया है। इस एक्ट के बाद अग्निशमन सेवा का अलग सेटअप होगा। डायरेक्टर मुखिया होंगे। हर निकायों में फायर ऑफिसर होगा। नए अग्निशमन सेवा केंद्र भी खोले जाएंगे। एक फंड बनेगा, ताकि सेवा का संचालन जारी रहे।

कई राज्यों ने कर दिया अमल

मॉडल फायर मेंटेनेंस व इमरजेंसी सर्विस एक्ट, 2019 के मॉडल ड्राफ्ट में जरूरी बदलाव कर कई राज्य लागू भी कर चुके हैं। ऐसे में मप्र के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कुछ महीने पहले नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र लिखा था। इसमें प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2019 और फायर व इमरजेंसी एक्ट को जल्द लागू कराने का आग्रह किया था। कहा था कि इससे आम जनता का फायदा होगा। प्रदेश में फायर सेफ्टी के लिए अभी जो व्यवस्था है उसके अनुसार 15 मीटर से ऊंचे भवन, एक फ्लोर पर 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण, 50 से अधिक पलंग-बिस्तर वाले होटल व अस्पताल का उपयोग करने के पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। फायर सर्टिफिकेट तीन साल के लिए रहेगा, इस दौरान प्रत्येक वितीय वर्ष में 30 जून तक फायर ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी होगी। फायर ऑफिसर को 10 फीसदी रिपोर्ट का रैंडम चयन कर औचक निरीक्षण करना होगा। सर्टिफिकेट रीन्यू कराने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। नई बिल्डिंग के लिए निर्माण की अनुमति के साथ ही फायर सेफ्टी प्लान का अनुमोदन अग्निशमन प्राधिकारी करेगा।

आग की घटना के बाद यदि डायरेक्टर को लगता है कि लापरवाही बरती गई है तो बिल्डिंग सील करने का अधिकार उन्हें होगा। यदि कोई उद्योग या मनोरंजन का स्थल है जो किसी बड़े भवन के एक हिस्से में चल रहा है तो फायर डायरेक्टर किसी भी समय वहां निरीक्षण के लिए पहुंच सकता है। फायर एक्ट में दंड देने के भी अधिकार होंगे। किसी भवन या संपत्ति मालिक को बार-बार चेतावनी देने के बाद भी यही वह व्यवस्था में सुधार करता है तो उसे 6 महीने की सजा और 50 हजार का जुर्माना हो सकता है। कोई सेवा में बाधा डालेगा तो भी तीन महीने की सजा और 10 हजार का जुर्माना होगा। यदि फायर एक्ट के तहत नोटिस मिलता है तो संपत्ति मालिक 30 दिन के भीतर उसकी अपील कर सकेगा। इसी तरह फायर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए कोई आवेदन करता है तो 30 दिन के अंदर उसे वह मिलेगा। एक्ट का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी के साथ कड़े नियम भी होंगे।

प्रदेश में तैयार किए गए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल के ड्राफ्ट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके लागू होने के बाद फायर ब्रिगेड आपातकालीन सेवाओं में शामिल हो जाएगा। अभी तक यह एक बचाव दल की हैसियत से काम कर रहा था। इस बिल के लागू होने से आग लगने के कारणों की बेहतर ढंग से जांच होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ फायर सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अगर आग लगने का कारण भवन मालिक की लापरवाही है और उससे जानमाल का नुकसान हुआ है तो मुआवजा भी उसी से वसूला जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी भवन में आग से बचाव के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस स्थिति में विभाग के पास पूरा नोटिस देकर जांच करने का पूरा और भवन को खाली करवाकर उसे सील करने का भी अधिकार होगा। आपातकालीन स्थिति में जिम्मेदार कर्मचारियों के भाग जाने पर उसके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की जा सकेगी। बिल के अनुसार किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, उद्योग व अग्नि हादसों की संभावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार फायर स्टेशन स्थापित करेगी। हर फायर स्टेशन में एक फायर ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। जो इस क्षेत्र के अंतर्गत अग्नि हादसों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

● रजनीकांत पारे

कैसे सुधरेगा रिजल्ट

शिक्षकों के 98470 पद खाली पड़े

मप्र में सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के नवाचार कर रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी को दूर नहीं किया जा रहा है। इस कारण उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग में विषयवार शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली हैं। ऐसे में प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना मुश्किल है। बता दें, कि 10वीं में 8.21 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 58.10 प्रतिशत परिणाम रहा। वहीं 12वीं में 6.24 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनका परिणाम 64.49 प्रतिशत रहा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी दोनों कक्षाओं के विषयवार परिणामों की समीक्षा करने में जुटे हैं। वहीं शिक्षाविद् का कहना है कि जब शिक्षकों के पद आधे से अधिक खाली होंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। विभाग को पहले खाली पदों को भरना होगा।

मप्र में हर साल जब भी 10वीं, 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आता है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, सुविधाओं के अभाव की चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ दिन चर्चा के बाद मामला अधर में लटक जाता है। एक बार फिर परीक्षा परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जिम्मदार भी भलीभांति जानते हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विषय विशेषज्ञों की कमी है। खासकर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अर्थशास्त्र के शिक्षकों की कमी के कारण इन विषयों में प्रदेश के विद्यार्थी सबसे अधिक कमजोर हैं। वित्त विभाग के आंकड़े कहते हैं कि 2022-23 सत्र में 23127, 2023-24 सत्र में 6144, 2024-25 सत्र में 942 पदों को स्वीकृति दी गई है। यानी 2022 से 2025 तक के लिए वित्त विभाग ने कुल 30213 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। सरकारी दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि वर्तमान में कई विषयों में पात्रताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की वजह से सीमित संख्या में ही भर्ती की जाएगी। इसलिए 2022-23 में 15 हजार 252, 2023-24 में 13 हजार 963 और 2024-25 में 942 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। शिक्षाविद् सुनीता सक्सेना का कहना है कि उच्च माध्यमिक वर्ग में विषयवार शिक्षकों के खाली पदों को भरना होगा। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी देना होगा। तभी सुधार संभव है।

देश में नई शिक्षा नीति के बारे में भले ही बढ़-चढ़कर बातें हो रही हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई खास बदलाव नजर नहीं दिख रहा है। कम से कम मप्र में तो कोई असर नहीं दिख रहा है। हाल ही में एमपी बोर्ड हायर सेकंडरी एग्जाम के नतीजों ने भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की पोल खोलकर रख दी है। हाल ही में मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व अर्थशास्त्र में सबसे अधिक कमजोर विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों का सबसे खराब प्रदर्शन अंग्रेजी में है। जहां 10वीं में करीब तीन लाख तो 12वीं में करीब डेढ़ लाख विद्यार्थी फेल हुए हैं। वहीं 10वीं में गणित में 2.91 लाख, विज्ञान में 2.41 लाख, सामाजिक विज्ञान में 2.27 लाख फेल हुए हैं। इसी तरह 12वीं में अर्थशास्त्र में 53 हजार, भौतिकी में 60 हजार फेल हुए हैं। यहां तक कि हिंदी में भी दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन खराब है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्कूलों में शिक्षकों की कमी। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त शिल्पा गुप्ता का कहना है कि 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणामों का विषयवार विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें विषयवार सामने आने वाली कमजोरियों को चिन्हित कर शिक्षक प्रशिक्षण में और क्लासरूम टीचिंग में इन बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 को जारी मप्र सरकार राजपत्र के मुताबिक प्रदेश के हाईस्कूलों में प्राचार्य और उप-प्राचार्य के 1114, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 34789, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक के 250, माध्यमिक शिक्षकों के 60686, माध्यमिक शिक्षक खेल के 931 और माध्यमिक शिक्षक संगीत के 700 पद खाली हैं... यानी राजपत्र कहता है कि प्रदेश में कुल मिलाकर 98470 पद खाली पड़े हैं। अब इनमें से प्राचार्य, उप-प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों के कुछ पद समय-समय पर भरे जाते रहे हैं लेकिन चिंता की बात ये है कि बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 34789 और माध्यमिक शिक्षकों के 60686 पद खाली हैं। यानी सिर्फ इन्हीं दोनों कैटेगरी के कुल 95475 पद खाली हैं। इनमें से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 34789 पदों में से सरकार सिर्फ 8720 पदों पर भर्ती कर रही है। इनमें भी नए पद सिर्फ 5052 हैं। और इनमें भी 45 फीसदी पद बैकलॉग के हैं। इन पदों को भरने के लिए सरकार ने 2023 में वर्ग-1 की चयन और पात्रता परीक्षा ली थी।

हैरानी की बात ये है कि इससे पहले प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा साल 2018 में हुई थी तब 22 हजार नए पद थे, लेकिन इस बार नए पद सिर्फ 5052 हैं। दूसरी तरफ जितने पदों पर भर्तियों के लिए सरकार ने परीक्षा ली थी उन पर भी भर्तियां नहीं दी जा रही हैं। सरकार की ओर से कभी ओबीसी आरक्षण का हवाला दिया जाता है तो कभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने की बात कही जाती है। इधर, वर्ग-1 की उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के चयनित उम्मीदवार लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। चयनित उम्मीदवार नियुक्तियों और पदवृद्धि की मांग लेकर प्रदर्शन और आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार के उदासीन रवैये की वजह से अब उनकी नाराजगी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उच्च माध्यमिक वर्ग में अंग्रेजी व हिंदी में शिक्षकों के आधे पद खाली हैं। जहां अंग्रेजी में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 5900 में से 2910 पद खाली हैं। वहीं गणित विषय में से स्वीकृत पद 3700 में से 1823 पद खाली हैं। इसी तरह हिंदी में 6040 स्वीकृत पदों में से 3029 पद खाली हैं।

स्कूलों के खराब रिजल्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह है शिक्षकों की कमी। प्रदेश में करीब 6 हजार सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है... कहीं-कहीं महज एक या दो टीचर्स से ही काम चलाया जा रहा है... हर साल सरकारी स्कूलों में 6 से 7 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं लेकिन गणित, विज्ञान और कॉमर्स पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी के कारण हर साल रिजल्ट खराब ही आता है। सरकारी आंकड़े देखें तो प्रदेश में 4765 सरकारी हायर सेकंडरी और 3851 हाई स्कूल हैं, जिनमें करीब 35 हजार पद खाली हैं। इनमें से 17 हजार पदों पर पुराने शिक्षकों को प्रभार सौंपा गया है, जबकि बाकी पद अभी भी खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग ने अगस्त 2023 में 8720 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था।

● जितेंद्र तिवारी

नक्सल मुक्त होगा दंडकारण्य...!

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देश और मप्र के बालाघाट से मिले फीडबैक के बाद 6 राज्यों की सरकारों ने दंडकारण्य को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी का परिणाम है कि मप्र में 43 लाख रुपए के दो नक्सलियों के साथ ही छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 80 नक्सली मारे गए हैं। वहीं 6 राज्यों ने हार्डकोर नक्सलियों की सूची बनाई है। जिसमें मप्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला खूंखार नक्सली मांडवी हिडमा सहित 17 नक्सली सुरक्षा बलों के टारगेट पर हैं।

2 अप्रैल को बालाघाट के जंगल में मप्र पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च अभियान के दौरान एक महिला नक्सली सहित 43 लाख रुपए के दो नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों से एक एके-47 एवं एक 12 बोर राइफल बरामद की गई। वहीं बालाघाट में नक्सल गतिविधियों की शुरुआत से आज तक के इतिहास में पहली बार नक्सलियों से बीजीएल शेल बरामद किए गए। इनसे दो बीजीएल शेल, वायरलेस सेट, दो रेडियो भी बरामद किए गए।

नक्सलियों से यह मुठभेड़ लांजी थाना क्षेत्र के पितकोना-केरझरी के जंगल में हुई। एनकाउंटर में मारी गई महिला नक्सली कान्हा-भोरमदेव डिवीजन के विस्तार प्लाटून-02 की डिविजनल कमेटी की सदस्य थी। वहीं दूसरा नक्सली मलाजखंड एरिया कमेटी का सदस्य था। दोनों ही नक्सली मप्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई नक्सली वारदातों को अंजाम दे चुके थे। दरअसल, मप्र ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है उसमें दंडकारण्य वह क्षेत्र है जहां नक्सलवाद की जड़ें गहरी हैं। अत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का सबसे पहला फोकस है कि दंडकारण्य को नक्सल मुक्त किया जाए।

दंडक वन अथवा दंडकारण्य रामायण में वर्णित एक वन का नाम है। कथा के अनुसार दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध वन है और यहां वनवास के समय श्रीरामचंद्र बहुत दिनों तक रहे थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का एक भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल हैं। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मप्र राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किमी तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। वर्तमान समय में यह क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ बन गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि नक्सली टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैम्पेन इन महीनों (अप्रैल से जून) में चला रहे हैं। जिसमें उनका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों पर हमला कर इस दौरान नुकसान पहुंचाए। सूत्रों ने ये बताया है कि नक्सलियों केवल छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर में ही टीसीओसी चलाने का प्लान नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने काफी सालों बाद

हिडमा के लिए बिछाया जाल, मारे गए 29 नक्सली

मप्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला खूंखार नक्सली मांडवी हिडमा सुरक्षा बलों के टारगेट पर है। 5 राज्यों के सुरक्षा बलों के बीच खतरे का पर्याय बने मांडवी हिडमा का सफाया करने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। इसी के तहत सुरक्षा बलों ने जाल बिछाया था, जिसमें 29 नक्सली फंस गए, जिन्हें सुरक्षाबलों ने घेरकर मार गिराया। इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया। 2024 की शुरुआत के बाद से, माओवादियों के गढ़ बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ में 79 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के सूत्रों ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में मांडवी हिडमा के गांव के नजदीक सुरक्षा बलों ने अपना बड़ा कैंप बना लिया है। यह कैंप गृह मंत्रालय के आदेश पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस योजना के तहत बनाया गया है। वहीं मप्र के बालाघाट, मंडला आदि क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले के माड़ इलाके में मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा का गांव है। यहां पर सुरक्षाबलों का जाना एक तरीके से अबूझ पहेली जैसा है। लेकिन एरिया डोमिनेशन की रणनीति पर काम करते हुए सुरक्षाबलों ने हिडमा के गांव पुरवर्ती में जाकर कैंप बना दिया है।

नए ट्राई जंक्शन के नजदीक सुरक्षा बलों पर हमला करने का प्लान तैयार किया है।

केंद्र सरकार से मिली हर झंडी के बाद मप्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पिछले 4 महीने के दौरान नक्सल विरोधी अभियान चर रहा है। इस अभियान के तहत 2 अप्रैल को बालाघाट में तीन राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रहने वाले दो हार्डकोर वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों के पास से एक एके-47 और 12 बोर की राइफल के साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली सजंती उर्फ क्रांति पति सुरेंदर (38) निवासी ग्राम रेगाड़म थाना भेज्जी जिला सुकमा (छत्तीसगढ़) पर मप्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 29 लाख रुपए और रघु उर्फ शेर सिंह उर्फ सोमजी पंद्रे निवासी दडेकसा जिला बालाघाट पर मप्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 14 लाख रुपए का ईनाम घोषित था। मारे गए नक्सली महाराष्ट्र, मप्र और छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। इससे पहले 14 दिसंबर को 14 लाख का ईनामी हार्डकोर नक्सली मड़काम हिडमा उर्फ चैतु निवासी ग्राम पोमरा, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़) को मार गिराया गया था। मप्र में पिछले 5 वर्षों में 17 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिनमें 2 डीवीसीएम नक्सल कमांडर और 15 एसीएम रैंक के नक्सली शामिल थे, जिन पर कुल 2.62 करोड़ रुपए का ईनाम घोषित था। वर्ष 2022 में कुल 6 ईनामी नक्सली मारे गए हैं तथा एक वर्ष में सर्वाधिक नक्सली मारे जाने का रिकार्ड है। 2023 में कुल 4 ईनामी नक्सली मारे गए। दरअसल, जब-जब छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलियों पर सख्ती होती है तो वे मप्र के बालाघाट के जंगलों में अपना कैंप लगा लेते हैं। पुलिस को पिछले एक साल से सूचना मिल रही है कि नक्सली मप्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। मप्र में नक्सली घटनाओं, गतिविधियों और भौगोलिक दृष्टि से शासन ने 8 जिलों को नक्सल प्रभावित माना है। इनमें बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया शामिल हैं। इनमें बालाघाट के बाद सिंगरौली ही सर्वाधिक नक्सल प्रभावित माना गया है।

वहीं छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 80 नक्सली मारे गए हैं। 125 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 150 ने सरेंडर किया है। दो दिन पहले ही सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2004-14 की तुलना में 2014-23 में देश में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52 फीसदी की गिरावट आई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 6035 से 1868 यानी 69 फीसदी हो गई है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही नक्सलियों के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाए गए हैं। पिछले साल नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने माओवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाने का निर्देश दिया था। एक विशेष समिति का गठन भी किया गया था। इसमें पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बीएसफ, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक आदि शामिल किए गए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षाकर्मियों ने राज्य में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें शंकर राव जैसा कुख्यात नक्सल कमांडर भी शामिल था। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के इतिहास में उनके मारे जाने की ये सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। इस मुठभेड़ में तीन सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए थे। सुरक्षा बलों ने यहां से एके-47, इंसास रायफल और एलएमजी के साथ बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए थे। सुरक्षा बलों ने साल 2014 से माओवादी बहुल इलाकों में शिविर लगाना शुरू किया था। साल 2019 के बाद 250 से अधिक शिविर स्थापित किए गए हैं।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014-23 की तुलना में साल 2004-14 में नक्सली हिंसा की घटनाएं 14862 से घटकर 7128 हो गई हैं। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों की मौत की संख्या साल 2004-14 के मुकाबले 2014-23 में 72 फीसदी कम हो गया है। ये संख्या 1750 से घटकर 485 हो गई है। वहीं आम लोगों के मौतों की संख्या 68 फीसदी से घटकर 4285 से 1383 हो गई है। साल 2010 में हिंसा वाले जिलों की संख्या 96 थी। साल 2022 में यह 53 फीसदी घटकर 45 हो गई। इसके साथ ही हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या साल 2010 में 465 से घटकर साल 2022 में 176 हो गई। पिछले पांच वर्षों में उन 90 जिलों में 5000 से अधिक डाकघर स्थापित किए गए, जहां माओवादी की सक्रियता है। वहां पर अक्सर उनका मूवमेंट देखा जाता है।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

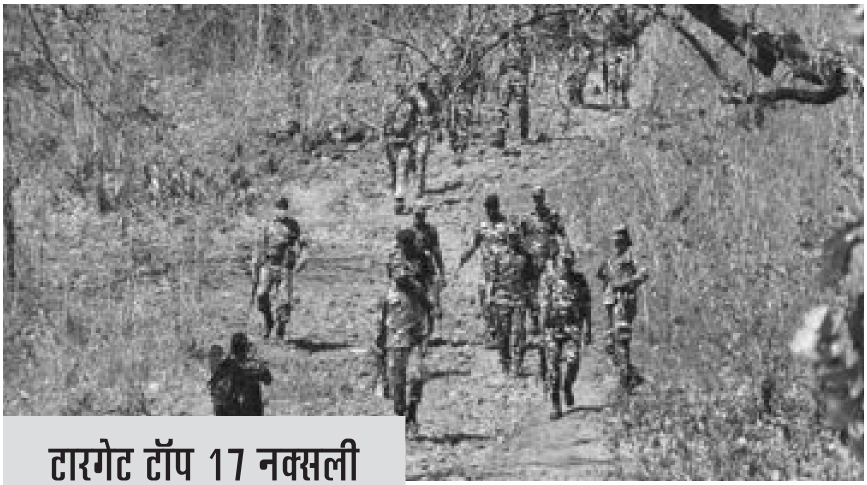

टारगेट टॉप 17 नक्सली

सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में सिर्फ हिडमा ही नहीं कई दूसरे नक्सली लीडर भी शामिल हैं। लिस्ट में मुप्पला लक्मना राव को सुरक्षा बलों ने टॉप लिस्ट में शामिल किया है। टॉप 17 में जो नक्सली शामिल किए गए हैं उनमें हिडमा ने 90 के दशक में नक्सली हिंसा का रास्ता चुना और तबसे कई निर्दोष लोगों की जान ले चुका है। वह माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीजीएलए) बटालियन-1 का हेड है और ऐसे घातक हमले करता रहता है। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के इलाके में जो भी बड़े नक्सली हमले हुए हैं उसमें ज्यादातर जगहों पर एनआईए और दूसरी एजेंसियों का 25 लाख का वांछित हिडमा का ही नाम सामने आता रहा है। साउथ सुकमा के पुरवर्ती गांव में जन्में हिडमा को हिडमालू उर्फ संतोष के नाम से भी जाना जाता है। साल 2001 में वो नक्सलियों से जुड़ा था। हिडमा को ऐसा नक्सल कमांडर मानते हैं जिसने पूरे क्षेत्र में अपना सूचना तंत्र फैला रखा है। हिडमा, बस्तर क्षेत्र के मुरिया जनजाति से आता है। उसके गांव में आज तक पुलिस का पहुंचना नामुमकिन माना जाता था, पर अब सुरक्षा बलों ने हिडमा के गांव में अपना कैंप खोल लिया है। हिडमा के बारे में जानकर ये भी कहते है कि हिडमा को गोरिल्ला युद्ध में ट्रेनिंग विदेश में मिली है और वो एके-47 चलाने का सबसे पुराना विशेषज्ञ है जो इसके कुछ ही मिनटों में फायरिंग कर सकता है। हिडमा ने पहले ही खुद को एक ऐसे कमांडर के तौर पर कायम कर लिया है जिसके पास रणनीति की कमी नहीं है। एनआईए के दस्तावेजों के मुताबिक हिडमा की उम्र इस समय 51 साल की है। सुरक्षा एजेंसियां इस समय इसकी गहन तलाश कर रही हैं।

बिना अमला आबकारी विभाग?

विभाग के पास उपायुक्त भी नहीं

मप्र में शराब बंदी की पैरवी करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के प्रयासों के बावजूद इस पर रोक नहीं लग सकी। वहीं, अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने और जहरीली शराब बेचने वालों के लिए कड़ा कानून लागू करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आबकारी अमले में भर्ती नहीं करवा सके। स्थिति यह है कि आज अमले में 50 फीसदी से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। ग्वालियर मुख्यालय में उपायुक्त के तीन पद स्वीकृत हैं और तीनों खाली हैं। इधर, भोपाल उड़नदस्ते में एक पद स्वीकृत है, लेकिन दो अधिकारी काम कर रहे हैं। आबकारी विभाग में नया सेटअप 2017 में लागू किया गया था, इसके तहत आयुक्त और अपर आयुक्त आबकारी का पद आईएएस तथा आईपीएस से भरा जाता है। संभागीय मुख्यालयों पर उपायुक्त आबकारी का एक-एक पद स्वीकृत है। इनमें ग्वालियर, भोपाल, सागर, रीवा, जबलपुर, इंदौर तथा उज्जैन शामिल हैं। संभागीय उपायुक्त का पद केवल इंदौर और उज्जैन में भरा हुआ है। भोपाल स्थित राज्य स्तरीय उड़नदस्ते में उपायुक्त का एक पद स्वीकृत है, लेकिन यहां दो उपायुक्त काम कर रहे हैं। विभाग में सहायक जिला आबकारी अधिकारी के 262 पद स्वीकृत हैं, इसके विपरीत 157 अधिकारी कार्यरत हैं और 105 पद खाली हैं। आबकारी उपनिरीक्षक के अमले में 531 पद स्वीकृत हैं, इनमें 289 कार्यरत हैं और 233 पद खाली हैं। आबकारी मुख्य आरक्षक के 316 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 117 मुख्य आरक्षक कार्यरत हैं और 199 पद खाली हैं। आरक्षक के 1023 पद मंजूर हैं और 540 आरक्षक कार्यरत हैं, जबकि 483 पद खाली है।

मप्र में सरकार की हर साल तकरीबन 15 हजार करोड़ रुपए की कमाई शराब की बिक्री से होती है। सरकार इस रकम को पाकर फूले नहीं समाती है। जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में हर साल हजारों करोड़ रुपए की अवैध शराब का गोरखधंधा होता है। आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है कि पर्याप्त अमला नहीं होने के कारण वे शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। मप्र में अवैध शराब के कारोबार की स्थिति क्या है, इसका आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में हर साल तकरीबन 10 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की जाती है। जानकारों का कहना है कि यह तो अवैध कारोबार का एक छोटा सा आंकड़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशी और विदेशी शराब 4102.53 लाख लीटर सरकारी ठेकों पर बेची गई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मप्र में अवैध शराब का गोरखधंधा किस तरह चरम पर है।

आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह प्रदेश में साल दर साल सरकारी शराब की बिक्री बढ़ रही है, उसी तरह अवैध शराब का गोरखधंधा भी बढ़ रहा है। हालांकि आबकारी विभाग रोजाना हजारों लीटर अवैध शराब जब्त कर रहा है। उसके बावजूद प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार दिन दोगुना, रात चौगुना हो रहा है। मप्र के सबसे कमाऊ विभागों में शामिल आबकारी विभाग को अमले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर यह हो रहा है अवैध शराब के गोरखधंधे पर विभाग नकेल नहीं कस पा रहा है। हालांकि गत वर्ष सरकार ने आबकारी विभाग में 200 कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी। उसके बाद भी विभाग में आधे पद खाली पड़े हैं। इसका असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ रहा है। मप्र में देशी और विदेशी शराब दुकानों की नीलामी के जरिए सरकार को हर साल 12 से 13 हजार करोड़ का टैक्स मिलता है। इसके बावजूद प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर आबकारी अमला रोक लगा पाने में नाकामयाब है। खासकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान तो करोड़ों लीटर अवैध शराब पकड़ी जाती है, लेकिन सरकार को आबकारी अमले में भर्ती करने की कतई चिंता नहीं रहती। विगत वर्ष हुए विधानसभा और वर्तमान में चल रहे लोकसभा चुनाव में पकड़ी गई शराब इस बात का संकेत हैं कि मप्र में अवैध शराब का कारोबार किस तरह बेखौफ चल रहा है। वहीं होटलों-ढाबों में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है। अगर आबकारी विभाग के पास पूरा अमला होता तो ऐसी स्थिति निर्मित ही नहीं होती। करीब 12-13 हजार करोड़ की राजस्व कमाई करने वाले आबकारी विभाग में अमले का टोटा बना हुआ है। ऐसे में विभाग के सामने अवैध शराब के धंधे को रोकने की चुनौती है। वहीं राजस्व आय को बरकरार रखना भी टेढ़ी खीर लग रही है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग में करीब 50 फीसदी अमला नहीं होने की वजह से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगा पाना मुश्किल लग रहा है।

अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जिलों में एक व्यक्ति के पास दो से तीन प्रभार हैं। वर्तमान में 157 जिला आबकारी अधिकारी, 289 उपनिरीक्षक, 117 मुख्य आरक्षक सहित अन्य संवर्ग के भी ढेरों पद खाली पड़े हुए हैं। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि फील्ड और दफ्तरों में खाली पदों के कारण विभाग में कुछ दिक्कतें हैं। अभी भर्ती के लिए भी कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। आरक्षकों की कमी को दूर करने होमगार्ड जवानों की सेवाएं ली गई हैं। जल्द विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो अमला कार्य कर रहा है, उसके पास भी एक से अधिक प्रभार हैं। उपनिरीक्षक नहीं होने से फील्ड में प्रकरण भी दर्ज होने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यालय में भी कर्मचारियों की कमी है। प्रदेश सरकार ने 3 अगस्त 2021 में जहरीली शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने और इस अपराध के लिए व्यक्ति के दोषी पाए जाने वा आजीवन कारावास या मृत्युदंड सहित न्यूनतम 20 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया था। हालांकि इसके बाद से अब तक इस मामले के किसी आरोपी को मृत्युदंड की सजा नहीं सुनाई गई है।

● प्रवीण सक्सेना

अरबों खर्च फिर भी शिप्रा मैली

धर्मधानी उज्जैन में प्रवाहित मां शिप्रा की महिमा पुराण गाते हैं। यह वही सरिता है, जिसमें अमृत गिरा था। यही मोक्षदायिनी का तट हर 12 वर्षों में सिंहस्थ का साक्षी बनता है। इसी में स्नान करने के लिए अपार आस्था लालायित रहती हैं। मान्यता है कि मां शिप्रा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। शिप्रा का महात्मय साधु-संत बताते रहते हैं, मगर इन दिनों उज्जैन की सियासत में मोक्षदायिनी का नाम लगातार गूंज रहा है। कारण है- लगातार मैली और सिकुड़ती जा रही शिप्रा। हालात यह हैं शिप्रा का आंचल चहुंओर से अशुद्ध हो गया है। ऑक्सीजन के अभाव में जलीय जीव जैसे मछलियां आदि मर रही हैं। इस सबके बीच राजनीतिक किरदार इसके शुद्धीकरण का मुद्दा फिर उठा रहे हैं।

बीते दिनों कांग्रेस प्रत्याशी ने शिप्रा में गंदा पानी मिलने के बीच डुबकी लगाकर इसके शुद्धि का संकल्प लिया। वहीं कुछ दिनों बाद ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नदी में डुबकी लगा और तैराकी कर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब चाहे तब यहां नर्मदा का पानी आ जाता है। हमारी सरकार ने काफी काम किया है। वादों और दावों के बीच हकीकत यह है कि मां शिप्रा अशुद्धि के बोझ के साथ-साथ अब सियासी स्वार्थ का भार भी उठा रही है। शिप्रा नदी इंदौर जिले के जानापावा की पहाड़ियों से निकल देवास-उज्जैन में 196 किलोमीटर बहने के बाद मंदसौर में चंबल नदी में मिलती है। नदी 80 के दशक से लगातार प्रदूषित, अतिक्रमित हो रही है। शिप्रा के प्रदूषित होने का मुख्य कारण इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम के नालों का गंदा पानी नदी में मिलना है। विशेषकरण इंदौर का सीवेज युक्त 30 क्यूमेक नालों का गंदा पानी, जो उज्जैन आकर कान्ह नदी के रूप में त्रिवेणी घाट पर मिलता है। महाकुंभ सिंहस्थ-2016 के बाद तो शिप्रा ओर अधिक प्रदूषित हुई है।

बीते दो दशक में शिप्रा की शुद्धि के लिए सरकार ने हजार करोड़ से अधिक रुपया खर्चा है। 402 करोड़ रुपए 2014 में प्राकृतिक प्रवाह से नर्मदा का शिप्रा से मिलन कराने पर खर्चे थे। इसके बाद 2016 में 99 करोड़ रुपए कान्ह डायवर्जन योजना पर खर्चे थे। इस योजना का उद्देश्य कान्ह का गंदा पानी शिप्रा के नहान क्षेत्र (त्रिवेणी घाट से कालियादेह महल तक) में मिलने से रोकना था। उद्देश्यपूर्ति के लिए राघोपिपल्या गांव से कालियादेह महल के आगे गांव के रास्ते भूमिगत पाइपलाइन बिछाई थी। हालांकि ये योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई। इसके बाद 2017 में उज्जैन शहर में 436 करोड़ रुपए की भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का काम शुरू कराया जो अब तक अधूरी है। 2019 में 139 करोड़ रुपए की पाइपलाइन योजना धरातल पर उतारी, जिसके तहत इंदौर के गांव मुंडला दोस्तदार स्थित पंपिंग स्टेशन से उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र तक (1325 मिलीमीटर व्यास की 66.17 किमी लंबी) पाइपलाइन बिछाकर शिप्रा में पानी छोड़ने का बंदोबस्त किया।

अब शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 598 करोड़ रुपए की कान्ह डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत त्रिवेणी घाट के समीप गोठड़ा गांव में कान्ह पर 5 मीटर ऊंचा स्टापडेम बनाने, यहां से कालियादेह महल के आगे तक 16.5 किलोमीटर लंबा एवं 4.5 बाय 4.5 मीटर चौड़ा पाइपलाइन नुमा आरसीसी बॉक्स बनाकर जमीन पर बिछाने को आमंत्रित निविदा सरकार के पास स्वीकृति की प्रत्याक्षा में सालभर से पड़ी है। दावा है कि इस चोकोर बाक्सनुमा पाइपलाइन से कान्ह का 40 क्यूमेक पानी डायवर्ट किया जा सकेगा। अंतिम 100 मीटर लंबाई में ओपन चैनल का निर्माण किया जाएगा। वहीं कान्ह पर एसटीपी योजना बनाई गई है। स्वच्छ गंगा मिशन अंतर्गत इंदौर में 34, 40, 120 एमएलडी (मिलियन लीटर्स पर-डे) के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को सालभर पहले सरकार ने 511 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसके महीनों बाद योजना को क्रियान्वित कराने को 427 करोड़ रुपए का टेंडर आमंत्रित किया। टेंडर खुले कई सप्ताह गुजर गए हैं पर टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि योजना केंद्र की है, इसलिए कुछ वक्त लगेगा।

शिप्रा पर एसटीपी की भी योजना बनाई गई है। स्वच्छ गंगा मिशन अंतर्गत सालभर पहले केंद्र सरकार ने उज्जैन नगर निगम को 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। विधानसभा चुनाव से पहले पीलियाखाल में 22 एमएलडी एवम भैरवगढ़ में 2.4 एमएलडी कंट्रिटमेंट प्लांट लगाने संबंधी निविदा प्रक्रिया की। ये अब तक स्वीकृत नहीं हुई है। विक्रम विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन शाला के विभागाध्यक्ष डॉ. डीएम कुमावत का कहना है कि शिप्रा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दो ठोस उपाय करने होंगे। पहला, कान्ह सहित समस्त नालों का गंदा पानी मिलने से रोका जाए। दूसरा, त्रिवेणी पर स्थायी बांध बनाकर, इंदौर, सांवरे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाकर गंदे पानी का उपचार किया जाए और उस पानी को छोटे-छोटे तालाबों की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

भूमिगत सीवेज पाइपलाइन परियोजना

अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत इस साल नगर निगम परिषद ने 473 करोड़ रुपए की भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन परियोजना 2.0 स्वीकृत की है। फिलहाल प्रोजेक्ट कागजों पर ही सिमटा है। अगर इच्छाशिक्त से काम हुआ तो भी प्रोजेक्ट 2025 में शुरू हो पाएगा। क्योंकि ये वर्ष तो डीपीआर की तीन स्तर पर स्वीकृति मिलने और फिर निविदा प्रक्रिया करने में ही गुजर जाएगा। सीवरेज प्रोजेक्ट के दूसरे चरण अंतर्गत शहर के 54 में से शेष 21 वार्डों में 103 किलोमीटर लंबी 200 से 600 मिलीमीटर व्यास की भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी है। प्रदूषित कान्ह नदी के पानी के उपचार के लिए पिपल्याराघौ गांव और उन्हेल चौराहा स्थित साडू माता की बावड़ी के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। उज्जैन-आलोट लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और सांसद अनिल फिरोजिया का कहना है कि मां शिप्रा के शुद्धीकरण को लेकर मैंने लोकसभा में अपनी बात रखी थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत से समय-समय पर आग्रह किया। इसी का परिणाम है कि नमामी गंगे की तर्ज पर नमामी शिप्रा अभियान के तहत इसे अमृत-2 योजना में शामिल कर लिया गया है। शुद्धीकरण के लिए 598 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे।

वनों में आग और हाहाकार

ग्रीष्म ऋतु के अपने चरम की ओर तेजी से बढ़ते जाने के साथ ही जंगलों में भड़की आग भी अपना विकराल रूप लेती जा रही है। हालात यह हैं कि जंगल की आग से उत्पन्न धुएं के घटाटोप में पहाड़ भी डूबते नजर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को श्वांस जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड इस दावानल से सर्वाधिक प्रभावित है जिसका सीधा असर उस हिमालय पर पड़ रहा है जिसे एशिया की जलवायु का नियंत्रक और महाद्वीप का जलस्तंभ या वाटर टावर कहा जाता है। इस समय आग जंगलों को निगल रही है और जंगल ब्लैक कार्बन उगल रहे हैं। अगर आप भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के वनाग्नि पोर्टल का अवलाकन करें तो उसमें पिछले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड का वनाग्नि के सर्वाधिक लगभग 4500 अलर्ट उत्तराखंड को भेजे गए हैं। इस अवधि में सर्वाधिक 350 वनाग्नि की बड़ी या गंभीर घटनाएं उत्तराखंड में दर्ज हुई है और उसके बाद उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई है, उसमें 5 मई को प्रदर्शित देशभर में भड़की कुल बड़ी वनाग्नियों में से अकेले उत्तराखंड के जंगलों की 110 घटनाएं दर्शायी गई थी। अब तक देश में वनाग्नि की 22 बड़ी घटनाएं दर्ज हुईं जिनमें सर्वाधिक 15 भीषण वनाग्नियां उत्तराखंड की थीं, जबकि डैशबोर्ड पड़ोसी हिमाचल में केवल 2 घटनाएं दिखा रहा था। इस वनाग्नि आपदा में वन सम्पदा के स्वाहा होने के साथ ही वन्यजीवन तो तबाह हो ही रहा है। लेकिन इससे वे अदृश्य संकट भी प्रकट होने लगे हैं जिनमें सांस लेने में परेशानी भी शामिल है। इन अदृश्य संकटों में जलवायु परिवर्तन भी है।

यह वैज्ञानिक सत्य है कि जंगल की आग ब्लैक कार्बन के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब जंगल जलते हैं तो वे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन सहित अन्य प्रदूषक भी उत्सर्जित करते हैं। जंगल की आग से उत्पन्न ब्लैक कार्बन की मात्रा वनस्पति जलने के प्रकार, आग की तीव्रता और मौसम की स्थिति जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है और उन क्षेत्रों में जहां जंगल की आग अक्सर या तीव्र होती है वहां ब्लैक कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। चूंकि हरी वनस्पति ज्यादा कार्बन धारण करती है इसलिए जब वह जलती है तो उस कार्बन को वातावरण में उत्सर्जित कर देती है। इन उत्सर्जनों का वायु गुणवत्ता और जलवायु पर स्थानीय और वैश्विक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। यह अधजला कार्बन ही ब्लैक कार्बन होता है।

ब्लैक कार्बन मुख्य रूप से कार्बन-आधारित ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2016 में गंगोत्री ग्लेशियर के पास चीड़बासा स्टेशन में किए गए एक अध्ययन में इस क्षेत्र में वानाग्नि के कारण ब्लैक कार्बन (बीसी) की अधिकता की पुष्टि की गई है। ब्लैक कार्बन उत्सर्जन वृद्धि में डीजल और पेट्रोल चालित वाहनों का भी काफी योगदान माना गया है। विशेष रूप से पुराने डीजल इंजन, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें ट्रक, बस, कार और ट्रेन शामिल हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के डॉ. पीएस नेगी के नेतृत्व में किए गए इस अनुसंधान को वैज्ञानिक पत्रिका एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में प्रकाशित किया गया था। चूंकि अब गर्मियों में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के साथ ही हिमालयी धर्मस्थलों पर भीड़ भी बढ़ने वाली है। पिछले साल अकेले उत्तराखंड के चार धामों में लगभग 6 लाख वाहन पहुंचे थे। लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक सुरबी मेनन और उनके सहयोगियों ने पाया कि ग्लेशियरों पर बर्फ और बर्फ के आवरण में गिरावट के लिए भारत से वायुजनित ब्लैक कार्बन एरोसोल एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन और बायोमास को जलाने के परिणामस्वरूप उत्सर्जित होने वाले ब्लैक कार्बन का वास्तविक योगदान 30 प्रतिशत से भी अधिक माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जंगलों की यह आग वातावरण में पर्याप्त मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों और सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन कर रही है। वनाग्नि के कारण ब्लैक कार्बन जैसे तत्व झाड़ियों, घास के मैदानों और जंगलों से उत्सर्जित होकर वातावरण में फैल जाते हैं। जैसे ही वनस्पति जलती है, उनके भीतर जमा कार्बन उत्सर्जित हो जाता है। यही मुख्य कारण है कि बड़े पैमाने पर जंगल की आग वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) छोड़ती है और इसलिए, जलवायु परिवर्तन की दर को काफी हद तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ब्लैक कार्बन एक जलवायु को सीधे प्रभावित करता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर वातावरण को गर्म करता है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग में सीधा योगदान होता है।

● लोकेश शर्मा

बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते

उत्तराखंड के जंगलों में आग को रोकने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। सरकार को कारगर रूप से कुछ करना होगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इन पर शीघ्र लगाम लगाने के लिए सरकार को आदेश देने की गुहार लगाई। वकील ने कहा कि दो साल पहले भी एनजीटी में याचिका लगाई थी। अब तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। ये मामला अखिल भारतीय है। उत्तराखंड इससे अधिक पीड़ित है। सरकार की ओर से दावाग्नि की घटनाओं और उसे काबू करने के उपायों की तफसील बताई। सरकार ने कहा कि अब तक जंगलों में आग की 398 घटनाएं रजिस्टर की गई हैं। 350 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें 62 लोगों को नामजद किया गया है। 298 अज्ञात लोगों की पहचान की कोशिश जारी है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार जितने आराम से ब्यौरा दे रही है हालात उससे ज्यादा गंभीर हैं।

फूंक डाला 642 करोड़ का कोयला

अगले दो साल कोयले की हो सकती है किल्लत

दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया को आने वाले समय में मांग की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, एसेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले दो साल में कोयले की मांग में 58 पर्सेंट की गिरावट हो सकती है। कैप्टिव कोल ब्लॉक के खरीदारों द्वारा प्रोडक्शन शुरु करने से ऐसा हो सकता है। कोल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोल इंडिया के टॉप 50 पावर और नॉन-पावर बायर्स अगले दो साल में माइनिंग कंपनियों से कोयले की खरीदारी 20-58 पर्सेंट कम कर सकते हैं। हालांकि, कोयले की कुल मांग और खपत पहले जैसी बनी रहने की संभावना है या इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।

कोयला आधारित बिजली उत्पादन इकाई में बिजली उत्पादन व उसके रखरखाव को लेकर परफार्मेंस खराब है। परियोजना की सभी यूनिटों से बिजली उत्पादन करने के लिए सहायक कोयला की खपत तय-सीमा से ज्यादा लग रहा है। ये खुलासा मप्र विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कोयला का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किए जाने से मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी को करीब 642 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मप्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व की मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी ने 2022-23 में मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित कोयला खपत से सात लाख टन कोयला ज्यादा फूंका है। इस कारण कंपनी को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उधर, तेल की खपत भी अन्य कोल आधारित बिजली परियोजनाओं की तुलना में दो गुना ज्यादा रही है। करीब 5200 किलो तेल ज्यादा फूंका है। फलस्वरूप 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान हुआ है। मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) व अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की आयोग में वास्तविक संचालन मानकों के आधार पर दायर सत्यापन याचिका में स्वयं स्वीकार किया है।

प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पॉवर प्लांट बिजली उत्पादन में पिछड़ रहा है। निर्धारित मात्रा में इस पॉवर प्रोजेक्ट से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सुपर पॉवर प्लांट कोयला भी ज्यादा खा रहा है। इससे मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके चलते अब इस पॉवर प्लांट की जांच कराए जाने की मांग उठने लगी है। मप्र के खंडवा जिले में स्थित श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट है। इस सुपर थर्मल पॉवर प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 2520 मेगावॉट की है। खंडवा में इस थर्मल पॉवर प्लांट की दो इकाइयां हैं। एक नंबर की इकाई से 1200 मेगावॉट और दूसरी इकाई से 1320 मेगावॉट बिजली उत्पादन होता है। इन दोनों इकाइयों से 85 फीसदी बिजली का उत्पादन होना चाहिए। विद्युत विनियामक आयोग ने यह मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन थर्मल पॉवर प्लांट की इन दोनों इकाइयों से निर्धारित मानक अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सिंगाजी थर्मल पॉवर प्लांट घाटे में जा रहा है। कम बिजली उत्पादन और कोयले की ज्यादा खपत की वजह से 642 करोड़ का घाटा इस थर्मल प्लांट से वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुआ है।

दावा किया जा रहा है कि सिंगाजी थर्मल पॉवर प्लांट बिजली उत्पादन में ज्यादा कोयला खा रहा है। प्रति यूनिट बिजली के उत्पादन में लगने वाले कोयले की मात्रा वास्तविक मात्रा से 100 से 150 ग्राम ज्यादा रही। यानी बिजली उत्पादन में सिंगाजी थर्मल पॉवर प्लांट में करीब 300 करोड़ की लागत का 7 लाख मीट्रिक टन कोयला ज्यादा जल गया। श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर प्लांट हर साल घाटे में जाता है। इसको देखते हुए बिजली मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने इस थर्मल पॉवर प्लांट की जांच कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से की है। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट कराए जाने के लिए भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। थर्मल पॉवर प्लांट से होने वाले नुकसान के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है।

पिछले 4 साल में मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी के घटिया परफार्मेंस के कारण आयोग ने वार्षिक प्रभार लगाया है। वहीं, प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों से बिजली खरीदनी पड़ी। मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) व अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि 2020-21 में 1026 करोड़, 2021-22 में 1540 करोड़ व 2022-23 में 1209 करोड़ रुपए लगे हैं। कोयला व तेल की ज्यादा खपत, निर्धारित वार्षिक प्रभार से प्रतिवर्ष अरबों रुपए का नुकसान हुआ है।

इन गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट पर पहुंच जाने के अनुमान के बीच कोयले से पैदा होने वाली बिजली पर भारत की अत्यधिक निर्भरता बने रहने के आसार हैं। बिजली मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि देश के कुछ हिस्सों में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है। इस दौरान बिजली की मांग भी काफी बढ़ गई और मंत्रालय इसे ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि नवीकरणीय क्षमताओं में वृद्धि जारी होने के बीच चरम मांग को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार किया जा रहा है। इसके अलावा सौर ऊर्जा भी मांग को पूरा करने में काफी मदद करेगी। मंत्रालय ने सभी बिजली उत्पादक कंपनियों, खासकर कोयले से चलने वाले ताप-विद्युत संयंत्रों को अपनी रखरखाव योजनाओं को टालने का निर्देश दिया है। इसके अलावा गैस-आधारित बिजली संयंत्रों को बिजली पैदा करने के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया कि भारत में अप्रैल-जून की अवधि में भीषण गर्मी का सामना करना होगा। इसकी सबसे ज्यादा मार देश के मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों पर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा, अधिकांश मैदानी इलाकों में सामान्य से अधिक लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्यत: चार से आठ दिन की तुलना में 10-20 दिन तक लू चल सकती है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

कम हो रहा औषधीय पौधों का उत्पादन

जंगल से वनोपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों और वैद्यों को महसूस हो रहा है कि मप्र के जंगलों में वनोपज की कमी हो रही है। इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। कई शोध के शुरुआती नतीजे बता रहे हैं कि मप्र के कुछ इलाकों में वनों में जड़ी-बूटी समेत वनोपज के उत्पादन में 80 फीसदी तक की कमी आई है। वैज्ञानिक पेड़ पौधों, वनस्पतियों में जलवायु परिवर्तन प्रभाव के आंकलन के लिए फिनोलॉजिक अध्ययन पर जोर देने की बात करते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापा जा सके। वनों में पेड़-पौधों, वनस्पतियों के जीवनचक्रण में परिवर्तन तो आया है पर वैज्ञानिकों के अनुसार अभी इस पर अध्ययन, ऑब्जरवेशन और आंकड़ों की कमी है।

कूनो नेशनल पार्क के आसपास के खोहरी, मढखेड़ा, ककरा, टिकटोली, करई सहित एक दर्जन आदिवासी गांवों में वनोपज संग्रह करने वालों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ककरा गांव के राजकिशोर बताते हैं कि पहले के मुकाबले अब वनोपज से रुपया में चवन्नी की कमाई भी नहीं हो पा रही है। हमारे पास खेती के लिए कोई जमीन तो है नहीं इसलिए साल के तीन चार महीने जंगलों से जड़ी-बूटियां इकट्ठी कर बेचकर जीवन-यापन करते थे इसी से हमारा जीवन चलता था। बाकी महीने मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। राजकिशोर के अनुसार सहरिया आदिवासियों की आजीविका वनोपज पर निर्भर है। एक सहरिया परिवार सालभर में बीस से तीस हजार नगद रुपए वनोपज से कमाता था। कूनो के करीब पोहरी कस्बे में करीब 50 वर्षों से जडीबूटियों और अन्य वनोपज का व्यापार करने वाले ब्रजेश गुप्ता को लगता है कि अगले तीन-चार साल में उन्हें अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। गुप्ता के अनुसार, पोहरी, कराहल, शिवपुरी क्षेत्र में औषधियों के व्यापार में 90 प्रतिशत तक की कमी आई है।

व्यापारी और आम लोग जिन इलाकों में वनोपज में कमी की शिकायत कर रहे हैं, उन इलाकों में वनोपज कम होने की बात एक रिपोर्ट में भी सामने आई है। मप्र सरकार के पर्यावरण विभाग की एक रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज वनरबिलिटी असेसमेंट फॉर मप्र में सामने आया है कि मप्र में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी (एनपीपी) के मामले में पूर्वी, मध्य और पश्चिमी जिले पीछे हैं। इन जिलों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी जैसे इलाके शामिल हैं। मप्र के जंगलों में एनपीपी को बायोमास उत्पादकता का एक मानक माना जाता है। बायोमास उत्पादकता में बढ़ोतरी से लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और अन्य गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी) सहित वन उत्पादों की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि आने वाले समय में जंगलों में वनस्पति वितरण, उनके जीवन चक्र और वन प्रकार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने मिलेगा।

ग्रीन इंडिया मिशन की सस्टेनबल हार्वेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर एनटीएफपी प्लांट्स नाम की एक रिपोर्ट भी वनोपज में कमी का इशारा करती है। इसके मुताबिक देश की फार्मा कंपनियों की कच्चे माल की 85 प्रतिशत मांग की पूर्ति जंगलों से होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों में ये मांग बढ़ी है जिससे जंगलों पर दबाव भी बढ़ा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गैर टिकाऊ तरीके से औषधियों और वनोपज के निकालने से वनों पर दबाव बढ़ा है। इस रिपोर्ट में सलाहकार के तौर पर जुड़े राष्ट्रीय पादप और औषधि बोर्ड के पूर्व सदस्य सुशील उपाध्याय का कहना है कि भारी मांग की वजह से जंगलों से प्राप्त होने वाली औषधियों में 70 से 80 प्रतिशत तक कमी आई है। इससे अजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासी परिवारों पर संकट खड़ा हो गया है। पहले ही इन्हें बाजार से न के बराबर दाम मिलता था अब उस पर भी संकट है। उपाध्याय आगे कहते हैं, पिछले 20 वर्षों में वनों से वन संसाधनों का काफी दोहन हुआ है। इससे वनों के स्वरूप में और उसकी पारिस्थितिकी में बहुत परिवर्तन हुआ है। इसका सीधा प्रभाव वनों से जुड़े उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आजीविका वनों पर निर्भर है।

मप्र में क्लाइमेट, औषधीय पौधों के व्यापार और आजीविका नाम के शोध पर काम कर चुके बाइफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े इकोलॉजिस्ट उत्कर्ष घाटे कहते हैं कि वनवासियों की आय में तेंदूपत्ता, महुआ, आंवला जैसी वृक्ष आधारित वनोपज का हिस्सा तो होता ही है पर उस आय में औषधि पौधों का भी इसमें अहम हिस्सा होता है। ये वनोपज इन वनवासियों की आय का तब जरिया बनती है जब साल के तीन चार महीने इनके पास कोई काम नहीं होता। इस समय पानी की कमी की वजह से इनके खेत खाली होते हैं। घाटे ने अपने शोध में पाया कि आदिवासी औषधि पौधों के व्यापार में सीधे शामिल नहीं होते हैं। वे अपने संग्रहण को छोटे व्यापारियों को बेचते हैं जो न के बराबर कीमत पर इनसे खरीदते हैं और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की दवा निर्माता कंपनियों को बड़े ऊंचे दामों पर बेचते हैं।

● बृजेश साहू

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सिमट रहा जंगल

डिंडोरी जिले में बैगा चक्क इलाके के शिल्पीड़ी गांव के एक सीलन भरे कच्चे मकान की रसोई में बैठी 43 वर्षीय दसमीबाई बैगा वैद्य हैं। दसमी ने औषधियों का ज्ञान अपने पिता और ससुर से लिया है। दसमी बाई का कहना है कि हम जंगली औषधियों को बाजार में बेचते नहीं हैं, पर इससे इलाज करते हैं। रोगी दूर-दूर से इलाज के लिए हमारे पास आते हैं और बदले में पैसे, धान, गेहूं देकर जाते हैं। दसमी कहती हैं, अब वनों में उतनी जड़ी-बूटियां नहीं हैं जितनी उनके पिता और ससुर के समय पर थीं। पहले उन्हें अपने गांव से सटे जंगल में आसानी से मिल जाती थीं पर अब उन्हें तलाशना मुश्किल हो गया है। दसमी इसके पीछे वनों का सिमटना, जंगल की आग और मौसम को कारण मानती हैं। पास के ही तांतर गांव के वैद्य अर्जुन बोरकर दसमी की बात से सहमति जताते हुए कहते हैं, पहले वन सघन और घने थे तो उन्हें अपने गांव के पास ही वनों में जरूरत की सभी जड़ी-बूटीयां मिल जाती थीं, अब उन्हें उनकी तलाश में 30 से 40 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। वहीं पातालकोट इलाके में रहने वाले भरिया आदिवासी भी मौसम में परिवर्तन से जड़ी-बूटी और अन्य वनोपज में कमी से परेशान हैं।

कब पूरे होंगे चुनावी वादे

राजा-महाराजाओं की ऐतिहासिक विरासत से ताल्लुक रखने वाले बुंदेलखंड के दिन कब बदलेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। साल दर साल लोगों को यही उम्मीद रहती है कि अब कुछ बेहतर होगा, कुछ ऐसा होगा कि किसानों के टूटते मनोबल को संबल मिलेगा, सूखते खेतों की दरारों में जल्द पानी दौड़ेगा और युवाओं के हाथों में रोजगार होगा। लेकिन, बुंदेलखंड के लोगों की यह उम्मीद अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। महंगाई की मार और हाथों में बेरोजगारी होने के कारण किसान अपनी जमीन बेचकर जा रहे हैं। जमीनों से दूर होते किसान के पीछे का सच बुंदेलखंड में जलसंकट ही है। बंजर जमीन और सूखते कंठ इस हकीकत की गवाही दे रहे हैं।

पन्ना जैसी डायमंड नगरी के लोगों को दो जून की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बीते बीस वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिससे स्थानीय लोगों को काम-धंधा मिलता या किसानों के खेतों में हरियाली बिखरती हुई दिखाई दे। जबकि चुनावी मंचों पर दावे और वादे करने वाले नेता हमेशा बुंदेलखंड के विकास की बातें कहते रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तब हर वर्ग के विकास की बात कही जाती है। इसी विश्वास के चलते लोगों ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में हर सांसद को भरपूर प्यार दिया। लेकिन, सांसदों ने चुनाव के बाद फिर क्षेत्र के लोगों को पलटकर नहीं देखा। पूरे बुंदेलखंड में गर्मियों के समय पानी की किल्लत रहती है। खासकर के अप्रैल-मई महीने से पीने के पानी का सबसे बड़ा संकट यहां देखने को मिलता है। यहां हर साल सूखे के हालात बनते हैं और फिर लोग कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाकर अपना गुजारा करते हैं। वहीं कुछ जगहों पर टैंकर से भी पानी पहुंचाया जाता है। बुंदेलखंड की ऐसी तस्वीरें सिर्फ सूखे के समय ही नहीं, हर साल देखने को मिलती है। चाहे बुंदेलखंड के मप्र क्षेत्र की बात हो या उप्र की, हर जगह पानी के लिए लोग भटकते हैं।

केन-बेतवा प्रोजेक्ट शुरू होने से मप्र के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन जिले को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। वहीं उप्र के महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर जिले लाभांवित होंगे। इतनी बड़ी आबादी को फायदा होने के बावजूद अब तक यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका है। 1999 के बाद से बुंदेलखंड की खजुराहो सीट पर भाजपा का राज चला आ रहा है। इससे पहले कांग्रेस का दबदबा था। इस बार फिर मंचों से दावे और वादों का दौर शुरू हो गया है। 44 हजार करोड़ के केन-बेतवा प्रोजेक्ट की अभी तक ईंट नहीं रखी जा सकी है। बुंदेलखंड के मुद्दों पर

शौचालय बना स्टोररूम

यहां के कौड़िया गांव की आदिवासी बस्ती की महिलाएं भी मटके और बाल्टी लेकर 1 किलोमीटर दूर हैंडपंप से पानी भरने जाती हैं। इनमें से कई महिलाएं तो काफी वृद्ध भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में कुछ आधे बने पक्के मकान नजर आते हैं, लेकिन उन पर भी ताला लगा है। लोग ईंट की दीवार खड़ी करके कामकाज के लिए बाहर चले गए। महिलाओं ने बताया कि यहां सिर्फ एक हैंडपंप है, जिस पर कभी-कभी ही पानी आता है। गर्मियों में हैंडपंप भी सूख जाता है। गांव में पानी पीने के लिए नहीं है, शौचालय में कहां से आएगा। यही वजह है कि बीएन लौंगसोर शौचालय को स्टोर रूम बना लिया है। बुंदेलखंड की बदहाली के लिए जिम्मेदार ढूंढने निकलेंगे तो न जाने कितने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। वादे तमाम होते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करने की इच्छाशक्ति कहीं नजर नहीं आती। अब तो लगता है बुंदेलखंड के लोगों ने भी शायद बादलों की ही तरह नेताओं से भी उम्मीद छोड़ दी है।

छतरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह का कहना है कि हमारी सरकार ने बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम किया है। हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में कई बड़े काम हुए हैं। खजुराहो का आधुनिक रेलवे स्टेशन, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर सहित कई बड़े काम हुए हैं। गांवों से लेकर शहरों तक विकास का खाका खींचा गया है। विकास की यह रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। वहीं खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आरबी प्रजापति का कहना है कि भाजपा के राज में हमेशा झूठे वादे होते रहे हैं। आज खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में लोग परेशान हैं। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। लोगों के पास काम धंधा नहीं है, फिर कैसा विकास है। लंबे समय से यहां भाजपा काबिज रही है, लेकिन कितना ध्यान दिया गया है यह बुंदेलखंड की तस्वीर खुद बयां कर रही है।

बुंदेलखंड को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार से बुंदेलखंड पैकेज जैसे भारी भरकम पैकेज मिला। लेकिन, उसका बंदरबांट ऐसा हुआ कि किसान पैकेज की ओर ताकते ही रह गए। बाद में पता चला कि बुंदेलखंड पैकेज की फाइलों में आग लग गई। जो बची वह दूसरी बार लगी आग में जल गई। इसी तरह नल जल योजना में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच सका है। जहां पाइपलाइन बिछाई गई, वहां पानी नहीं पहुंचा। इसके अलावा एनटीपीसी प्रोजेक्ट भी अब तक आकार नहीं ले सका है। बुंदेलखंड का नाम जैसे ही आता है, वैसे ही सूखे की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। बुंदेलखंड का नाम कानों में पड़ते ही धूप में मीलों-मील पानी की तलाश में भटकती महिलाओं की तस्वीरें मन-मस्तिष्क में घूमने लगती हैं। प्यास और पलायन यहां की नियति बन गए हैं। चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं, सरकारें बनती और गिरती हैं, लेकिन बुंदेलखंड की न तस्वीर बदलती है और न यहां रहने वालों की किस्मत। इन दिनों देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मप्र के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, सागर, दमोह और निवाड़ी जिले बुंदेलखंड का हिस्सा हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन जैसे ही आप टीकमगढ़ जिले के गांवों में पहुंचते हैं तो यह 18वीं-19वीं की याद दिलाते हैं। गांवों में ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ही दिखाई देते हैं। यहां के पुरुष मजदूरी करने या जॉब की तलाश में ग्वालियर, झांसी और दिल्ली जैसे शहरों में चले गए हैं। महिलाओं ने बताया कि यहां न तो पानी है न एक साल से बिजली ही आई है। पीने के पानी के लिए जो जद्दोजहद यहां की महिलाओं को करनी पड़ती है, वह एवरेस्ट चढ़ने जैसी है। उन्हें सुबह-सुबह 3-4 किलोमीटर चलकर या साइकिल से पीने का पानी लेने जाना पड़ता है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

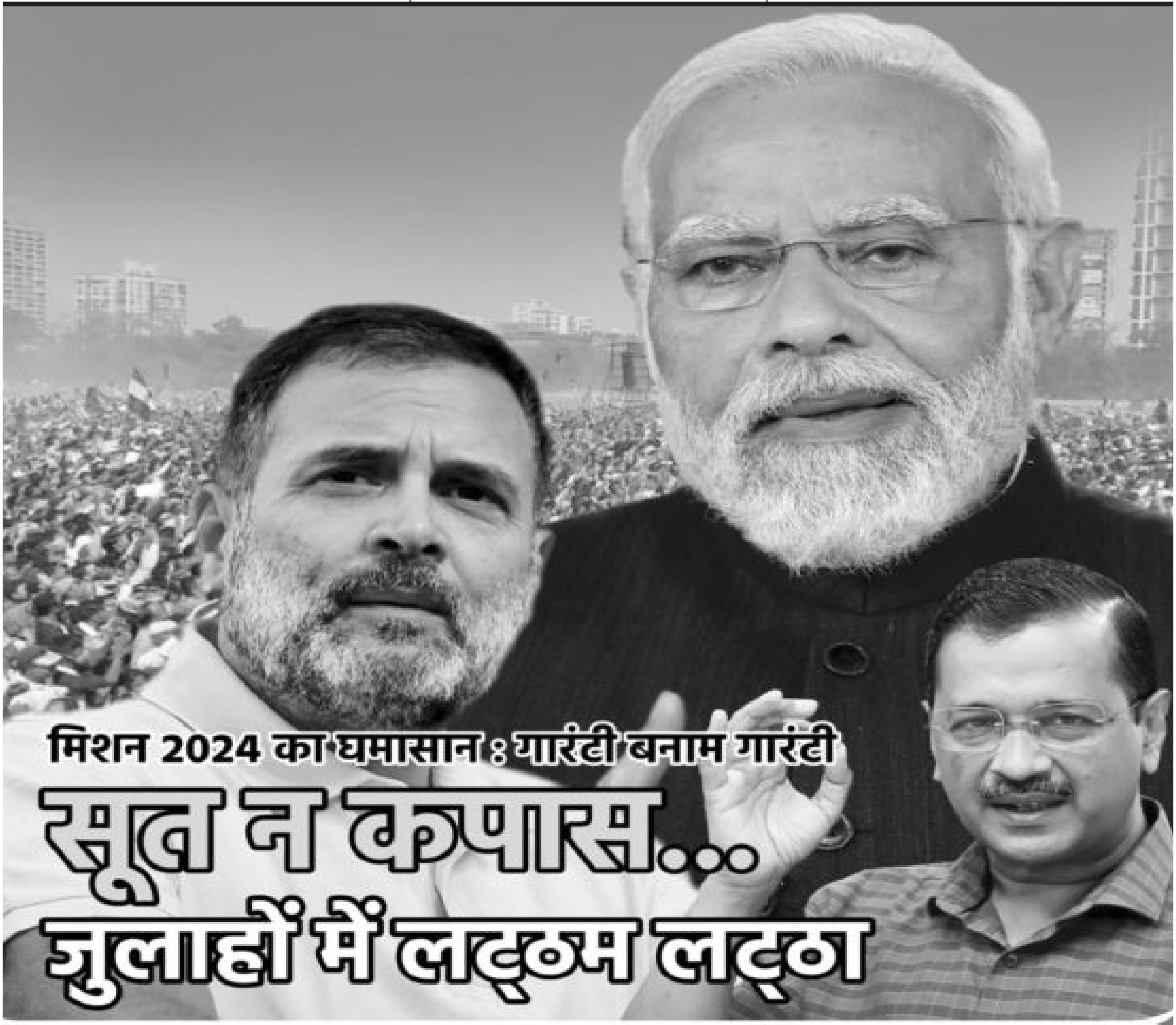

वादों नहीं, गारंटियों पर लड़ा जा रहा लोकसभा का चुनाव | राजनीतिक पार्टियों की गारंटी पर हावी हो गए हैं पुराने मुद्दे

लोकसभा चुनाव का महासंग्राम आधा रास्ता पार कर गया है। मुद्दाविहीन इस चुनाव में गारंटियों की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं...तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं। किसकी गारंटी में कितना दम है? यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हर चुनावी सभा, रैली में पार्टियों के नेता अपनी-अपनी गारंटी को पूरा करने का दम भर रहे हैं।

● राजेंद्र आगाल

लोकसभा चुनाव के चार चरणों में 379 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। शेष सीटों पर तीन चरणों में मतदान होने हैं। उसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। लेकिन अब तक चार चरणों में जिस तरह देशभर में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उससे भाजपा और इंडिया गठबंधन के दावों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि भाजपा 400 पार का दम भर रही है तो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां सत्ता परिवर्तन की बात कह रही हैं। लेकिन मतदाताओं के मौन और कम मतदान ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पार्टियों ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। देश की दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों ने भी इस बार चुनावी घोषणाओं को गारंटी के रूप में पेश किया है। जिससे यह चुनाव गारंटी बनाम गारंटी हो गया है। गारंटियों के इस मायाजाल ने भी मतदाताओं को इस तरह उलझाया है कि वे पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए।

लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे अब आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। मोदी गारंटी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी भाजपा का सियासी एजेंडा पहले चरण के मतदान के बाद से ही बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल हुए दस साल हो गए और मोदी सरकार का दूसरा टर्म भी पूरा हो रहा, लेकिन चुनाव प्रचार में पुरानी बातें फिर से गूंजने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व की पिच पर बिसात बिछानी शुरू कर दी और वे कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी बताने में जुटे हैं। इसके चलते एक बार फिर से हिंदू-मुसलमान, पाकिस्तान, हनुमान, घुसपैठिया जैसे नैरेटिव सेट किए जाने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी की गारंटी पर क्या भाजपा के पुराने मुद्दे हावी हो रहे हैं? उधर, कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में अपनी गारंटियों की चर्चा न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए अडानी, इलेक्टोरल बॉन्ड आदि की बातें कर रही है।

मोदी की गारंटी

भाजपा ने संकल्प पत्र में सरकार बनने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। इसी के साथ भाजपा ने कुल 24 मोदी की गारंटियां दी हैं। भगवा दल ने देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाने की बात की है। एक स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। इन गारंटियों में अगले पांच सालों तक मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पानी और पीएम सूर्य घर से जीरो बिजली बिल देने का वादा किया गय है। आयुष्मान भारत के तहत आगे भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। पेपर लीक पर बने कानून को भी लागू किया जाएगा। सभी नागरिकों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप, टूरिज्म आदि से युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर देने की गारंटी। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए लोन की गारंटी। आयुष्मान योजना में 70 साल की उम्र से ज्यादा के बुजुर्गों को भी शामिल करने की गारंटी। भाजपा ने करप्शन पर सख्त एक्शन लेने की गारंटी दी है। मोदी सरकार के दौरान 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम लौटे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन पूरी दुनिया ने इसे सेलिब्रेट किया। मोदी सरकार में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया गया और आतंकी हमले के खिलाफ 2016 और 2019 में देश की सीमा से बाहर जाकर भारतीय सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे वीरता पूर्ण कारनामे किए। भाजपा दावा करती रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का यह नतीजा रहा है।

मोदी सरकार की तरफ से देशभर में कोविड के काल से ही 80 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जा रहा है। साल 2020 से ही सरकार ने सबके लिए अन्न की सोच के साथ इसे शुरू किया था। वहीं, घोषणा पत्र में भाजपा का वादा है कि गरीब की थाली में अनाज हो इसके लिए अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का और विस्तार किया जाएगा। मोदी सरकार के 10 सालों में देश के 20 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी और इसका विस्तार किया गया। सरकार की योजना है कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और ज्यादा तेजी से किया जाएगा। मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 15 एम्स की स्थापना की और अब इसके और विस्तार के साथ इसके मजबूत ढांचे की रूपरेखा आगे के लिए तैयार की गई है। पिछले 10 सालों में भारत मोबाइल के उत्पादन में दुनिया के दूसरे नंबर के देश में शुमार हो गया है। अब भाजपा के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि भारत को 2030 तक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है। देशभर में मोटे अनाज को लेकर एक तरह की क्रांति का संचार मोदी सरकार में किया गया और 2023 में भारत ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्लेट्स समारोह का प्रतिनिधित्व किया। अब सरकार का अगले पांच साल में भारत को विश्व के न्यूट्री हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार ने नवंबर के महीने को जनजातीय गर्व दिवस के रूप में घोषित किया। वहीं, 2025 को जनजातीय गर्व वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। जब भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। देशभर में पिछले 10

मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी

अप्रैल में जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प पत्र जारी किया तब उसे मोदी की गारंटी नाम दिया। इसके बाद गारंटी शब्द को लेकर खूब सियासी बयानबाजियां हुईं। दरअसल, भाजपा ने गरीबों को फ्री राशन, लखपति दीदी योजना, सस्ते रसोई गैस, मिडिल क्लास को फ्री बिजली, जैसे कुल 24 गारंटी देने की बात की है। वहीं अब चुनाव के बीच एक बार फिर गारंटी सुर्खियों में है। कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में 50 दिन से बंद अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर जेल से निकलने के बाद अब कुल दस गारंटी दी हैं। उन्होंने इसे केजरीवाल की गारंटी बताते हुए दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 10 गारंटियों को लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की गारंटी के बारे में देश की जनता को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी मंचों से कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो काम हुए वह तो केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। ऐसे में भाजपा ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में जो वादा किया है, उससे मोदी सरकार के अगले 5 साल के पिक्चर का विजन क्लियर दिखता है। भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार में दावा किया जाता है कि पिछले 10 सालों में 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। भाजपा के घोषणापत्र में अब लोगों से वादा किया गया है कि अगर मोदी सरकार को जनता तीसरे कार्यकाल के लिए चुनती है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर मिलेगा।

5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे...

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 48 पन्नों का अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। नाम दिया गया है न्याय पत्र। नौकरी देने, किसानों की कर्जमाफी, खाली पद भरने, महिलाओं को भत्ता देने, एमएसपी की गारंटी देने जैसे तमाम वादे तो कांग्रेस पहले से करती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस के घोषणापत्र में संवैधानिक न्याय का पन्ना भी जोड़ा गया है। 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित हैं। गारंटी के इस सीजन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे किए हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र के 21वें पन्ने से असली खबर शुरू होती है, जहां नाम आता है संवैधानिक न्याय। जहां संविधान की प्रस्तावना के रूप को सामने रखकर कांग्रेस संसद, चुनाव आयोग, जांच एजेंसी, अदालत, मीडिया, चुनावी लोकतंत्र समेत हर उस जगह बदलाव के साथ न्याय की बात कह रही है। कांग्रेस कहती है कि सत्ता मिली तो मानहानि के जुर्म को अपराधमुक्त कर देगी। राहुल गांधी मानहानि के मामले में ही दो साल की सजा मिलने पर कुछ दिन संसद सदस्यता से अयोग्य रहे। कांग्रेस का वादा है कि इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुन सस्पेंशन को खत्म करेगी। क्योंकि देश में कई आंदोलनों के दौरान लंबे वक्त तक कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इंटरनेट बंद किया जाता रहा है। कांग्रेस ने वादा किया है कि शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार को बनाए रखेगी। किसान आंदोलन के दौरान उन्हें दिल्ली तक जाने की इजाजत भी नहीं मिली थी।

सालों में 31,000 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगले पांच साल में हर वर्ष 5,000 किमी प्रतिवर्ष के हिसाब से रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे।

कांग्रेस की गारंटी

जहां भाजपा कह रही है कि एक देश एक चुनाव कराएंगे तो वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का विरोध करती है। भाजपा जीएसटी कानून लेकर आई। कांग्रेस कहती है कि जीएसटी में बदलाव करेंगे। भाजपा कांग्रेसराज के योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाई। कांग्रेस कहती है कि हम वापस योजना आयोग को बहाल करेंगे। इन सबके बीच कांग्रेस एक वादा अपने उन नेताओं के खिलाफ लेकर आई है, जिन पर ईडी-सीबीआई के डर से ही भाजपा में चले जाने का आरोप कांग्रेस ही लगाती है। कांग्रेस ने ये वादा भी किया है कि भोजन, पहनावे, प्यार, शादी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कांग्रेस का निशाना लव जेहाद कानून और हिजाब पहनने से रोकने के नियम पर लगता है।

अब जरा 17वीं लोकसभा को याद करिए। जहां देश के इतिहास में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली लोकसभाओं में सबसे कम दिन की बैठक इन्हीं पांच सालों में हो पाई थी। तब दोनों सदनों से 206 बार सांसदों को निलंबित किया गया। अब कांग्रेस देश से ये वादा भी कर रही है कि अगर सत्ता में आए तो संसद की सदन साल में 100 दिन चलेगी। क्योंकि इस लोकसभा में औसत हर साल 55 दिन ही संसद चली। हफ्ते में एक दिन हर सदन में विपक्ष के बताए मुद्दे पर चर्चा होगी। ये वादा इसलिए क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दों पर चर्चा ना होने का आरोप लगाकर हंगामा ही करता रह गया कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को राजनीतिक दल से संबंध तोड़ना होगा। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से कांग्रेस सांसदों की नोकझोंक होती रही। बता दें कि कांग्रेस के इस चुनावी सीजन में करीब 48 नेता दल छोड़कर या तो भाजपा में जा चुके हैं या फिर दूसरे दलों में जा चुके हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि जिन्हें भाजपा भ्रष्टाचारी कहती थी, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर क्लीन हो गए क्या? अब कांग्रेस के घोषणा पत्र के 25 नंबर पन्ने पर गौर करें तो यहां लिखा है कि भाजपा एक विशाल वॉशिंग मशीन बन गई है। भाजपा में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को कानून से बचने की अनुमति दी गई। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों को फिर से प्रवर्तन करके जांच कराई जाएगी।

महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की सत्ता चली गई। मप्र में पिछली बार सिंधिया कांग्रेस की सत्ता भाजपा के पास लेकर चले गए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में कई बार सत्ता के अलट-पलट की विधायकों की अदला-बदली से आशंका जगी। कांग्रेस इसे ऑपरेशन लोटस कहती है। दल-बदल की जली कांग्रेस अब चुनाव में वादे फूंक-फूंककर कर रही है। दरअसल, भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि अगर सत्ता मिली तो कांग्रेस संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदलने वाले को विधानसभा या संसद की सदस्यता से सीधे अयोग्य करेगी। ईवीएम को लेकर कई चुनावों में सवाल विपक्ष उठाता रहा है। कांग्रेस भी उनमें से एक है। जैसे ईवीएम से चुनाव को लेकर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोले थे। राहुल गांधी ने कहा था कि ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम चुनाव आयोग के पास गए, वो सुनने को तैयार नहीं हैं। चुनाव से कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर गया। कोई न कोई कारण तो होगा।

अबकी बार कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो वोटिंग तो ईवीएम के जरिए होगी। लेकिन मतदान के दौरान जो पर्ची अलग से मशीन में आती है। उस वीवीपैट पर्ची का मिलान ईवीएम के वोटों से कराया जाएगा। भाजपा इस वादे पर पूछती है कि ईवीएम पर कांग्रेस कब तक मीठा-मीठा गप-गप करेगी। भाजपा पूछने लगी है कि कांग्रेस घोषणा पत्र जनता के लिए लाई है या सिर्फ मोदी विरोध का पत्र लेकर राजनीति करने आई है? सवाल की वजह है, सत्ता में आने की स्थिति में उन मामलों की जांच का वादा करना, जहां कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती है।

5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे। 48 पन्नों के घोषणापत्र के साथ क्या कांग्रेस को चुनाव जीतने की गारंटी मिल सकती है? जहां राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने का चुनाव बताते आ रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र बचाने का है या अपना-अपना पार्टी तंत्र बचाने का चुनाव है? क्योंकि घोषणा पत्र में तो हर दल सुंदर सुनहरे वादे करते हैं, लेकिन घोषणा पत्र के वादों पर जनता कितना वोट देती है? रिसर्च कहती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 37 फीसदी वोटर ने प्रधानमंत्री दावेदार को देखकर वोट दिया। 22 फीसदी ने पार्टी देखकर वोट दिया। 25 फीसदी ने उम्मीदवार को देखकर वोट दिया। 13 फीसदी ने अन्य वजह वोट देने की बताई। 3 फीसदी ने कहा कि वोट घोषणापत्र देखकर दिया।

प्रचार की बदल गई रणनीति

गारंटी पर शुरू हुई चुनाव प्रचार की रणनीति अब बदल गई है। पहले चरण में अपनी गारंटियों को गिनाने वाली भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप लगाने के लिए हदें पार करने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल नहीं होने पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया और सनातन को लेकर भी विपक्ष को घेरा। हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने हनुमान चालीसा का जिक्र कर विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस पर करारा अटैक किया। इतना ही नहीं कर्नाटक में कथित तौर पर हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार के ऊपर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में हनुमान चालीसा सुनना अपराध हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को मजहब के आधार पर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिसके बाद से भाजपा के तमाम छोटे-बड़े नेता अपने चुनाव प्रचार में इन्हीं सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, मोदी सरकार के पास देश के वोटर को बताने के लिए तमाम उपलब्धियां हैं। भाजपा मोदी की गारंटी पर चुनावी एजेंडा सेट कर रही है, लेकिन पहले फेज के बाद से ही उसको आखिर पुराने मुद्दों पर क्यों लौटना पड़ा?

प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह हिंदुत्व, मुसलमान, घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके जरिए अपने कोर वोटबैंक को सीधा सियासी संदेश देने के साथ-साथ लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को भी बदलने की कोशिश की है। विपक्ष इस बार बहुत बड़ी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। मुस्लिम मतदाता पूरी तरह खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, जिसके चलते धार्मिक ध्रुवीकरण होता नहीं दिख रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अब पुराने एजेंडे पर लौटने पर सियासी हलचल होती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि उनके बयान को विपक्ष काउंटर करे और सियासी केंद्र में उनकी बातें गूंजें। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के कोर एजेंडे पर नहीं लौटे हैं बल्कि यह उनके चुनाव प्रचार का पुराना अंदाज है। चुनाव के शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही आगाज करते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ता तो फिर अपने रंग में नजर आने लगते हैं। प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि मोदी की गारंटी और भारत को विकसित बनाने के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, बल्कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मोदी के मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार का यही स्टाइल है और हर चुनाव में यही करते हैं।

केजरीवाल ने दीं 10 गारंटी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी गिनाई हैं, जिनके जरिए वे लोकसभा चुनाव में आमजन से वोट देने की अपील कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, गरीब शिक्षा नीति है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश की जनता स्वस्थ होगी तो देश तरक्की करेगा। एक प्रधानमंत्री देश को आगे नहीं ले जा सकता है। देश की जनता ले जाती है। आज देश में सरकारी अस्पतालों का गंदा हाल है। देश के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लीनिक होगा। देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम और गरीबों को फ्री बिजली मिलेगी। हर गांव और मोहल्ले में शानदार स्कूल बनाए जाएंगे। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे की अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है- सेना को इजाजत तो दीजिए। चीन ने जो जमीन कब्जा की है उसको छुड़ाना है। अग्निवीर योजना सेना के लिए हानिकारक है। इसको बंद किया जाएगा, जो अग्निवीर में बहाल हुए हैं उनको पक्का किया जाएगा। कच्ची नौकरी को हटाकर इनको पक्का किया जाएगा। देश की सेना पर जितना खर्च किया जाना चाहिए, करेंगे। किसानों के सभी फसलों पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार दाम मिलेगा। एक साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार की गारंटी है। भ्रष्टाचार भाजपा की वॉशिंग मशीन है। देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सोर्स है। इस मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर भ्रष्टाचार की मुक्ति होगी। व्यापारियों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा।

ठंडे चुनाव में मोदी ने भरा उत्साह!

राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि पहले चरण का चुनाव जिस तरह का है, उसके बाद भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता थी कि लोकसभा चुनाव कैसे गरमाया जाए और क्या किया जाए कि लोग सड़कों पर उतरकर मोदी-मोदी के नारे पहले की तरह लगाने लगें। मोदी गारंटी, विकसित भारत का संकल्प और आर्थिक मुद्दों से राजनीतिक धरातल पर बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा, क्योंकि इससे मतदाताओं का सीधा सरोकार नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को पहले चरण की वोटिंग के बाद अपने पुराने मुद्दे पर लौटना पड़ा है। भाजपा के मतदाताओं को बातें भी वैसी ही पसंद हैं, जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी अब कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बांसवाड़ा की रैली से ठंडे पड़े लोकसभा चुनाव में भी तपिश आई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। वह बताते हैं कि भाजपा के तीन तरह के वोटर हैं, जिसमें पहले पक्के वोटर, दूसरे जो पहले दूसरी पार्टियों को वोट देते थे और अब भाजपा को वोट देते हैं और तीसरे फ्लोटिंग वोटर जो किसी को भी वोट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से अपनी बात रखते हैं ताकि उनकी बात हर तरह के वोटरों तक पहुंचे। ऐसे में पहले चरण की वोटिंग में प्रतिशत गिरने के बाद मोदी का यह बयान आया है। उनका भाषण दर्शाता है कि पार्टी अपनी मूल राजनीति की ओर लौटती नजर आ रही है।

उप्र के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कब्रिस्तान बनाम श्मशान का मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था अगर रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। कपड़ों से

पहचान सकते हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हनुमान चालीसा और बजरंगबली का मुद्दा उठाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी की गारंटी पर भले ही चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मालूम है कि इससे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राजनीति में चुनाव जीतना ही असल मकसद है, जिसके चलते भाजपा उन्हीं मुद्दों को उठा रही है, जिससे वोट हासिल किए जा सकें। भाजपा की चिंता घरों में बैठे हिंदू मतदाताओं को बाहर निकालने की है और वो हिंदू की तरह वोट करें, क्योंकि 2014 के बाद से देश की सियासत अल्पसंख्यकों के बजाय बहुसंख्यकों पर केंद्रित हो गई है। अब जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे हिंदुत्व के मुद्दे को धार मिलेगी। प्रधानमंत्री के बाद भाजपा के दूसरे नेता भी हिंदू-मुस्लिम के मुद्दों पर अपनी बात रखने लगे हैं। अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यही बातें कर रहे हैं, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। यही भाजपा के जीत का मंत्र है।

बदला प्रचार का पैटर्न

पहले चरण में सिर्फ मतदान कम होना भाजपा के लिए चिंता की बात नहीं थी बल्कि जाति के आधार पर लोगों का वोट डालना ज्यादा चिंता में डाल देना था। हिंदी पट्टी के राज्यों में खासकर बिहार, उप्र, राजस्थान आदि राज्यों में मोदी नाम पर वोट डालने की बजाय उम्मीदवारों के नाम पर वोट पड़े हैं। मोदी सरकार के अब 10 साल हो गए हैं, लेकिन 2014 में किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में मोदी की गारंटी का लोकसभा चुनाव में कोई भरोसा नहीं कर रहा है, जिसका आभास पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा को हो गया है। पहले चरण में कम मतदान और जमीनी स्तर से आ रहे फीडबैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटने के लिए मजबूर किया है।

पहले चरण में 102 सीटों यानी करीब 20 फीसदी सीटों पर मतदान हो गया है। मतदाताओं के रुख ने भाजपा की चिंता बढ़ाई है, तब प्रधानमंत्री को समझ में आया कि भाजपा के पुराने मुद्दे पर लौटे बिना चुनाव के रुख को नहीं बदला जा सकता है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने सीधे यह भय दिखाया कि कांग्रेस आई तो आम लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दलित, आदिवासी के आरक्षण को मुसलमानों को देना चाहती है। इस तरह से कांग्रेस का भय दिखाना नरेंद्र मोदी की चिंता को जाहिर करता है। इसीलिए अब भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व के पिच पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं ताकि धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सके।

क्या घोषणापत्रों से चुनाव जीते जाते हैं?

घोषणापत्र के वादों से क्या माहौल बनता है? क्या घोषणापत्रों से चुनाव जीते जाते हैं? 2019 में एक्सिस माय इंडिया का पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है, इस चेहरे को देखकर सबसे ज्यादा वोट जनता ने दिया। फिर लोकल कैंडिडेट और फिर पार्टी के नाम पर वोट जनता ने डाला। घोषणापत्र के नाम पर वोट देने की बात सिर्फ तीन फीसदी ने कही। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बचाने का चुनाव कहकर जब राहुल गांधी घोषणापत्र जारी करते हैं तो दस्तक देता सवाल है कि क्या सच ये भी है कि पार्टी की सियासत बचाने का चुनाव कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों के लिए बना हुआ है? चुनाव प्रचार की रैलियों और रोड शो में सारे दल एक से बढ़कर एक दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछले चार चरणों में मतदाता उदासीन दिखा। जमीन पर भी चुनावों में इस बार वैसी लहर या हवा नजर नहीं आ रही है जो 2014 और 2019 में साफ दिखाई देती थी और जिस पर सवार होकर भाजपा व नरेंद्र मोदी ने दो बार सरकार बनाई। जहां पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व की चाशनी में राष्ट्रवाद की घुट्टी और हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण जैसे राष्ट्रीय विमर्श और केंद्रीय मुद्दों का जोर रहा। उन दोनों चुनावों में मतदाताओं ने न जाति देखी न दल, सिर्फ देखा तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और भरोसा किया तो उनके वादों और इरादों पर, लेकिन इस बार का चुनाव किसी एक या दो राष्ट्रीय मुद्दों पर न होकर पूरी तरह विकेंद्रित हो गया है। हर राज्य हर लोकसभा क्षेत्र में अलग-अलग मुद्दे अलग-अलग समीकरण और परिस्थितियों का जोर है। कहीं सांसदों के खिलाफ गुस्सा है तो कहीं जातीय समीकरण भारी हैं।

गारंटी बनाम न्याय

लोकसभा चुनावों के तीन चरण पूरे हो चुके हैं और चुनाव अब अपने चौथे चरण की ओर है। तीन चरणों के मतदान को लेकर चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़े बदलने के बावजूद पिछले चुनावों से मतदान का प्रतिशत कम ही रहा है। जमीन पर भी चुनाव बेहद ठंडा और अनापेक्षित सा दिख रहा है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का बताने से लेकर आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर महिलाओं के मंगलसूत्र, संपत्ति और पिछड़ों, दलितों का आरक्षण छीनकर उसे मुसलमानों में बांट देने का आरोप लगाते हुए चुनाव को गर्माने की पूरी कोशिश की है और अब तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की चुनावी सभा में आरोप लगाया कि जो राहुल गांधी पिछले पांच साल से रोज अडानी-अंबानी के नाम की माला जपते थे, अब उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या उनके साथ कोई डील हो गई है और क्या बोरों में भरकर टेंपों में लादकर काला धन उनके पास आ गया है। इसी दिन प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के भारत की विवधता को लेकर रंग और चेहरों पर दिए गए एक बयान को निशाना बनाते हुए भी कांग्रेस पर हमला करते हुए देश को रंग और नस्ल के आधार पर बांटने का आरोप भी लगाया। अपने नेता के इस चुनावी राग में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी भाजपा नेताओं ने अपना स्वर शामिल करके इन मुद्दों को लगातार उठाया है। उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के जीतने पर संविधान बदलने, लोकतंत्र खत्म करने और पिछड़ों, दलितों, वंचितों और गरीब सवर्णों के अधिकार छीनकर सबकुछ चंद उद्योगपति मित्रों को देने का आरोप भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार लगा रहे हैं। भले ही मोदी ने राहुल पर अडानी-अंबानी का नाम लेने की बात कही हो, लेकिन राहुल न सिर्फ अडानी का नाम ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने मोदी के आरोप का जवाब देते हुए भी अडानी-अंबानी का नाम लेते हुए उनके यहां ईडी-सीबीआई भेजने की बात कही है।

डूब रहे अमेरिकी बैंक

मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की कारगर नीति नहीं

अमेरिका में बैकों के असफल होने की समस्या मुख्यतः मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में की गई वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई हैं। दरअसल, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्पादों की मांग को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने के स्थान पर बाजार में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इन उत्पादों की कीमत को कम रखा जा सके। प्राचीन भारत में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके कारण मुद्रा स्फीति की समस्या भारत में कभी रही ही नहीं है। बल्कि भारत में उत्पादों की प्रचुरता के चलते समय-समय पर उत्पादों की कीमतें कम होती रही हैं।

अमेरिका में वर्ष 2023 में 3 बैंक (सिलिकन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक) डूब गए थे एवं वर्ष 2024 में भी एक बैंक (रिपब्लिक फर्स्ट बैंक) डूब गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अमेरिकी केंद्रीय बैंक, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में की गई वृद्धि के चलते बैंकों के असफल होने की यह परेशानी बहुत बढ़ गई है। सिलिकन वैली बैंक ने कई तकनीकी स्टार्टअप एवं उद्यमी पूंजी फर्म को ऋण प्रदान किया था। इस बैंक के पास वर्ष 2022 के अंत में 20,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्तियां थीं और यह अमेरिका के बड़े आकार के बैंकों में गिना जाता था और हाल ही के समय में डूबने वाले बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक माना जा रहा है। इसी प्रकार, सिग्नेचर बैंक ने न्यूयॉर्क कानूनी फर्म एवं अचल संपत्ति कंपनियों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रखी थीं। इस बैंक के पास वर्ष 2022 के अंत में 11,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति थी और अमेरिका में हाल ही के समय में डूबने वाले बड़े बैंकों में चौथे स्थान पर आता है। 31 जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की कुल संपत्तियां 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं जमाराशि 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। न्यू जर्सी, पेनसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क में बैंक की 32 शाखाएं थीं जिन्हें अब फुल्टन बैंक की शाखाओं के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि फुल्टन बैंक ने इस बैंक की संपत्तियों एवं जमाराशि को खरीद लिया है।

पीयू रिसर्च संस्थान के अनुसार, चार शताब्दी पूर्व, वर्ष 1980 एवं वर्ष 1995 के बीच अमेरिका में 2,900 बैंक असफल हुए थे। इन बैंकों के पास संयुक्त रूप से 2.2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थी। इसी प्रकार, वर्ष 2007 से वर्ष 2014 के बीच अमेरिका में 500 बैंक, जिनकी कुल संपत्ति 95,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी, असफल हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अमेरिका में सामान्यत: बैंक असफल नहीं होते हैं। परंतु, इस संबंध में अमेरिकी रिकार्ड कुछ और ही कहानी कह रहा है। वर्ष 1941 से वर्ष 1979 के बीच, अमेरिका में औसतन 5.3 बैंक प्रतिवर्ष असफल हुए हैं। वर्ष 1996 से वर्ष 2006 के बीच औसतन 4.3 बैंक प्रतिवर्ष असफल हुए हैं एवं वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के बीच औसतन 3.6 बैंक प्रतिवर्ष असफल हुए हैं। वर्ष 2022 में अमेरिकी बैंकों को 62,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। इसके पूर्व, वर्ष 1921 से वर्ष 1929 के बीच अमेरिका में औसतन 635 बैंक प्रतिवर्ष असफल हुए हैं। यह अधिकतर छोटे आकार के बैंक एवं ग्रामीण बैंक थे और यह एक ही शाखा वाले बैंक थे। अमेरिका में आई भारी मंदी के दौरान वर्ष 1930 से वर्ष 1933 के बीच 9,000 से अधिक बैंक असफल हुए थे। इनमें कई बड़े आकार के शहरों में कार्यरत बैंक भी शामिल थे और उस समय इन बैंकों में जमाकर्ताओं की भारी भरकम राशि डूब गई थी। वर्ष 1934 से वर्ष 1940 के बीच अमेरिका में औसतन 50.7 बैंक प्रतिवर्ष बंद किए गए थे।

अमेरिका में इतनी भारी मात्रा में बैंकों के असफल होने के कारणों में मुख्य रूप से शामिल है कि वहां छोटे-छोटे बैंकों की संख्या बहुत अधिक होना है। बैकों के ग्राहक बहुत पढ़े-लिखे और समझदार हैं। बैंक में आई छोटी से छोटी परेशानी में भी वे बैंक से तुरंत अपनी जमाराशि को निकालने पहुंच जाते हैं, जबकि बैंक द्वारा इस राशि से खड़ी की गई संपत्ति को रोकड़ में परिवर्तित करने में कुछ समय लगता है। इस बीच बैंक यदि जमाकर्ता को जमाराशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार बैंक असफल हो जाता है। कई बार बैंकों द्वारा किए गए निवेश (संपत्ति) की बाजार में कीमत भी कम हो जाती है, इससे भी बैंकें अपने जमाकर्ताओं को जमाराशि का भुगतान करने में असफल हो जाते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोत्तरी की गई है, जिससे इन बैकों द्वारा अमेरिकी बॉन्ड में किए गए निवेश की बाजार में कीमत अत्यधिक कम हो गई है। अब इन बैंकों को बॉन्ड में निवेश की बाजार कीमत कम होने के स्तर तक प्रावधान करने को कहा गया है और यह राशि इन बैकों के पास उपलब्ध ही नहीं है, जिसके चलते भी यह बैंक असफल हो रहे हैं। एक सर्वे में यह बताया गया है कि आने वाले समय में अमेरिका में 190 अन्य बैंकों के असफल होने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ब्याज दरों के बढ़ने से ऋण की मांग बहुत कम हो गई है। विभिन्न कंपनियों ने अपने विस्तार की योजनाओं को रोक दिया है, इससे निर्माण की गतिविधियों में कमी आई है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का पूरा ध्यान केवल मुद्रा स्फीति को कम करने पर है एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विकास दर को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादों की मांग कम हो और मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में लाया जा सके। इसके चलते कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है एवं देश में युवा वर्ग बेरोजगार हो रहा है। पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक नीतियां अमेरिका में बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही हैं। अब तो अमेरिकी अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं कि आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में साम्यवाद के बाद पूंजीवाद भी असफल होता दिखाई दे रहा है एवं आज विश्व को एक नए आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है। इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट इशारा भारत की ओर है क्योंकि इस बीच भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित मॉडल भारत में आर्थिक समस्याओं को हल करने में सफल रहा है।

● **राकेश ग्रोवर**

इंडिया शाइनिंग बनाम 400 पार

मिशन-2024 में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है। पार्टी को पूरा विश्वास है कि इस बार वह 400 से अधिक सीटें जीत लेगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि उनके दावों की स्थिति इंडिया शाइनिंग जैसी ना हो जाए।

उत्साह हमेशा अच्छा होता है लेकिन अति उत्साह अक्सर काम बिगाड़ देता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ताकतवर मंत्री और तब की भाजपा के रणनीतिकार प्रमोद महाजन को यही अति उत्साह भारी पड़ा था। 2004 के आम चुनाव में उन्होंने अटल सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। चुनावी रणनीति के अनुसार देश के हर चौराहे, गली-मोहल्ले को इंडिया शाइनिंग के पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया था। इन पोस्टरों में अटल सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी उपलब्धियां गिनाई गई थीं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो सभी प्रकार से अच्छे काम करने के बावजूद भाजपा कांग्रेस सहित क्षेत्रीय पार्टियों के सामने धराशायी हो गई। उसे 138 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस को 145 सीटें। इसके अलावा सीपीआईएम, डीएमके, समाजवादी पार्टी तथा राजद क्षेत्रीय ताकतें बनकर उभरीं और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बना ली गई।

बाद में जब उस आम चुनाव का खुद भाजपा के लोगों ने विश्लेषण किया तो उन्हें समझ में आया कि प्रमोद महाजन का अति उत्साह भाजपा को भारी पड़ गया। इसके 10 साल बाद 2014 में ही भाजपा दोबारा सत्ता में लौट पाई जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उसने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि प्रचंड बहुमत के साथ अपना दो कार्यकाल पूरे कर चुके नरेंद्र मोदी ने भी 2024 में अति उत्साह में वही गलती तो नहीं कर दी है जो 2004 में प्रमोद महाजन ने की थी? इस सवाल के अपने कारण हैं। आम चुनाव की घोषणा होने के पहले से ही 2024 के चुनाव को लेकर जो नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, वह उसके पहले के दो आम चुनावों में नहीं दिखे थे। मसलन, इससे पहले नरेंद्र मोदी ने खुद कभी अपने मुंह से यह मांग या दावा नहीं किया था कि अगली बार वो सरकार बनाना चाहते हैं या सरकार बनाने जा रहे हैं। यहां तक कि 2014 के चुनाव में पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीट दिलाने वाले नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपना काम करते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते।

उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि वो कभी एक्जिट पोल की भी चिंता नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है। बकौल मोदी के वो तो परिणाम वाले दिन भी रिजल्ट में रूचि दिखाए बिना अपनी सामान्य दिनचर्या अनुसार काम करते हैं। किसी के भी द्वारा बोली जाने वाली यह भाषा उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है कि वह जो कर रहा है उसकी सफलता को लेकर उसे रंचमात्र भी संदेह नहीं है। 2002 से 2019 तक नरेंद्र मोदी का यही आत्मविश्वास दिखा और उन्हें लगातार जीत भी मिली है। भाजपा के लिए मोदी एक ऐसा खरा सिक्का बन गए कि चुनाव जीतने के लिए जिनका नाम ही काफी है। लेकिन इस बार मोदी के व्यवहार में बदलाव दिख रहा है। पहली बार मंचों से वो खुद न केवल जनता से अपने लिए तीसरा कार्यकाल मांग रहे हैं बल्कि लगभग हर मंच से कांग्रेस के सत्ता में लौटने का डर भी दिखा रहे हैं। 2014 से 2024 में फर्क यह आया है कि मोदी के लिए जो बातें उनके समर्थक, उनका प्रचारतंत्र और उनकी पार्टी बोलती थी इस बार वो सारी बातें मोदी खुद बोल रहे हैं। मसलन पहली बार का नारा अबकी बार मोदी सरकार हो या फिर दूसरी बार का नारा आएगा तो मोदी ही... को खुद मोदी ने कभी मंच से नहीं दोहराया था। यह काम जमीन पर उनके समर्थक कर रहे थे।

लेकिन अब तीसरे कार्यकाल के लिए जब वो चुनाव मैदान में हैं तब उनके समर्थकों में ही वह उत्साह नहीं दिख रहा है जो बीते दो चुनावों में दिखता था। मानों समर्थकों ने भी मान लिया है कि जब मोदी अपनी योजना से चार सौ पार जा रहे हैं तो फिर उसको सक्रिय होने की क्या जरूरत है? अभी तक उत्तर भारत की जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वहां मोदी चर्चा के केंद्र में नहीं दिखाई दिए हैं। चुनाव के मुद्दे और चर्चाएं या तो हैं नहीं और अगर हैं भी तो स्थानीय हैं।

2014 के मोदी के प्रचार अभियान से इस बार एक और अंतर दिख रहा है कि वो अभी तक अपना वह चुनावी एजेंडा सेट नहीं कर पाए हैं जिससे उनके समर्थकों और पार्टी वर्करों में जोश भर जाए। अबकी बार चार सौ पार... से उनके चुनावी अभियान की जो शुरुआत हुई वह मुस्लिम आरक्षण से होते हुए कांग्रेस, पाकिस्तान, चिट्ठी लिखकर हर बूथ पर कांग्रेस को हराने तक पहुंच गई है। मोदी जो भी बोल रहे हैं या जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो। बीते दो चुनाव उन्होंने इन्हीं शब्दों के सहारे लड़ा था लेकिन तीसरी बार फिर से उन्हीं शब्दों को दोहराने से न तो विरोधियों को कोई खास फर्क पड़ रहा है और न ही समर्थकों में कोई उत्साह नजर आ रहा है। इस बार एक बात और गौर करने लायक है कि राहुल गांधी जहां स्वतंत्र रूप से मुद्दे उठा रहे हैं, वहीं मोदी

इस बार चाय पर नहीं, मोदी की चिट्ठी पर चर्चा

लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देशवासियों को परिवारजन के संबोधन के साथ मतदान के लिए लिखी चिट्ठी के बाद अब तीसरे चरण के मतदान के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सहित एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नाम व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर कांग्रेस के मंसूबों के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने तथा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को सबक सिखाने की सलाह दी है। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम क्षणों में भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए अपने भरोसेमंद राजनीतिक साथी अमित शाह को लिखे पत्र में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए विपक्षी दलों पर आक्रामक होने का अनुरोध किया है। इसे लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिर माजरा क्या है? मालूम हो कि इंटरनेट, गूगल जैसी अनेक डिजिटल सुविधा आने के बाद चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के तौर तरीकों में काफी बदलाव आया है, लेकिन इसकी तासीर जस की तस है।

गुजरात में भाजपा आंतरिक संघर्ष से मजबूर

गुजरात जहां भाजपा से सिर्फ टिकट मिलना ही जीत की गारंटी माना जाता है, उस राज्य में साबरकांठा और बड़ोदरा से टिकट मिलने के बाद भी विरोध और विवाद के चलते पार्टी के घोषित उम्मीदवार को अपना टिकट लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। पार्टी को कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद दूसरे उम्मीदवार देने पड़े। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता भीकाजी ठाकोर को पहले साबरकांठा से भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनकी जगह साबरकांठा से भाजपा ने 2022 में कांग्रेस से भाजपा में आए महेंद्र सिंह बरैया की पत्नी शोभना बरैया को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बड़ोदरा से सांसद रहीं रंजना बेन भट्ट का टिकट भी पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बदलना पड़ा। उनके घर के सामने और भाजपा कार्यालय में जमकर प्रदर्शन हुए। पार्टी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि रंजना बेन ने कोई काम नहीं किया उसके बाद भी लगातार तीसरी बार उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? इसी तरह सुरेंद्रनगर सीट से भाजपा संगठन ने 2017 में कांग्रेस से भाजपा में आए चंदूभाई सेहोरा को उम्मीदवार बनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं को यह नागवार गुजरा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर कांग्रेस से आए चंदूभाई को टिकट दिया जाए। सुरेंद्रनगर सीट पर जमकर विरोध हो रहा है और हालत यह है कि भाजपा प्रत्याशी को भाजपा कार्यालय में ही बैठक लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध की यही स्थिति अमरेली में भी नजर आ रही है, जहां मौजूदा सांसद नारन कछाड़िया की जगह जिला पंचायत अध्यक्ष भरत सुतारिया को टिकट दिए जाने के विरोध में दोनों गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई। वलसाड एसटी सीट पर भी भाजपा कार्यकर्ता ध्रुव पटेल को बाहरी बताकर विरोध कर रहे हैं और टिकट वितरण में लेन-देन का आरोप लगा रहे हैं। जूनागढ़ और मोरबी सीट पर भी विरोध हो रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच आपस में तलवार खिंची हुई है।

या तो उन मुद्दों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पूरे चुनाव को राहुल बनाम मोदी करने का प्रयास करते दिख रहे हैं। राहुल गांधी इस बार ज्यादा मैच्योर तरीके से प्रचार अभियान में हैं और मजाक बनने से अब तक बचे हुए हैं। वो इस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं कि खुद मोदी को जवाब देना पड़ रहा है। यह राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल का ही असर है कि ऐन चुनाव के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंच गईं।

आखिरकार घूम फिरकर मोदी और भाजपा ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाने की बजाय 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस की नाकामियां गिनाना शुरू कर दिया है। वो कांग्रेस के सत्ता में लौटने का डर दिखा रहे हैं जिसकी फिलहाल 2024 में तो कांग्रेस को ही उम्मीद नहीं है। फिर भी 400 पार के जिस नारे से चुनाव अभियान की शुरुआत हुई थी वही भाजपा के गले की फांस बनता जा रहा है। अब अगर एनडीए को इससे कम सीटें आती हैं तो यही मोदी की हार घोषित हो जाएगी भले ही भाजपा-एनडीए को इतनी सीटें मिल जाएं कि वह सरकार बना ले। बहरहाल, भाजपा के इस समय मुख्य रणनीतिकार अमित शाह का उत्साह कायम है और वो आज भी यही दावा कर रहे हैं कि 4 जून को जब मतगणना शुरू होगी उस दिन दोपहर 12 बजे तक एनडीए चार सौ का आंकड़ा पार कर लेगा। अब देखना यह होगा कि 4 जून को भाजपा का इंडिया शाइनिंग वाला हाल होता है या सचमुच वह ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सभी रिकार्ड तोड़ देती है।

कांग्रेस अब यह मानकर चल रही है कि मोदी कोई अपराजेय नेता नहीं हैं। कांग्रेस की नजर में अब भारत जोड़ो यात्रा के दो चरणों के साथ राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वह उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ अपने अभियान में यह नारा गढ़ा है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। लेकिन मोदी भी मंजे हुए नेता हैं और इस खेल से पूरी तरह वाकिफ हैं। इसलिए अबकी बार 400 पार के नारे के साथ मोदी और अमित शाह की जोड़ी तीसरे कार्यकाल का दावा तो कर रही है, लेकिन एक अनजाने भय के कारण कांग्रेस के प्रति और कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रही है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी, ममता बनर्जी के अलग सुर के बाद नाममात्र के लिए बचे इंडिया गठबंधन के बीच अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद भाजपा को चिंता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी जब से हाथ में संविधान लेकर चुनावी रैलियां करने लगे हैं, भाजपा की चिंता बढ़ती जा रही है।

राहुल गांधी ने ट्विटर पर कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों और नेताओं से अनुरोध किया है कि वह जहां भी जाएं पवित्र संविधान को अपने साथ जरूर रखें और गांव-गांव, गली-गली ऐलान कर दें कि जब तक कांग्रेस है दुनिया की कोई ताकत भारत से उसका संविधान छीन नहीं सकती। हाल के दिनों में यह दिखा है कि कांग्रेस ने संविधान को आगे कर जब भी सरकार का विरोध किया है भाजपा बचाव की मुद्रा में आ जाती है। अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस के सत्याग्रह के दौरान संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से एक रैली में सफाई दी गई कि बाबा साहब के संविधान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी की लोकप्रियता चरम पर है और जहां-जहां भाजपा की सरकार है डबल इंजन के फायदे बताए जा रहे हैं। देश की ताकत घर में घुसकर मारने वाले नए भारत के रूप में पेश की जा रही है, इसके बाद भी दिक्कत आ रही है? मोदी की चिट्ठी में बूथ लेवल पर कांग्रेस को टारगेट करने की सलाह दी जा रही है, यानी कुछ ना कुछ आशंका जरूर है। लेकिन क्या? बीते दो चुनाव के नतीजे को देखें तो मालूम होता है कि देश में जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं, भाजपा के प्रदर्शन पर काफी असर पड़ता है। यानी 2024 में भी भाजपा का नंबर क्षेत्रीय दलों के चुनावी प्रदर्शन पर ही निर्भर करता है। पूरे देश में 243 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से सीधा मुकाबला है। कांग्रेस की तुलना में भाजपा के लिए क्षेत्रीय दलों से मुकाबला ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ मेहनत करने के बजाय क्षेत्रीय दलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। लेकिन पहले दौर के मतदान के बाद भाजपा के रणनीतिकारों का अत्यधिक चौकन्ना हो जाना तथा प्रमुख विपक्षी पार्टी के खिलाफ अतिआक्रामक रुख अपनाने की राय से लोगों के कान खड़े होना स्वाभाविक है।

● **विपिन कंधारी**

कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नामांकन जमा करने के समय जिस प्रकार से बड़े नेताओं का जमघट लगा, वह भले ही जनता में प्रभाव डालने के लिए किया हो, लेकिन इससे यह भी राजनीतिक संदेश सुनाई दे रहा है कि अब रायबरेली की सीट भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है।

विरासत के सहारे जीत की तलाश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उप्र की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ पाने की हिम्मत के बाद आखिर परंपरागत रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया। यह बात सही है कि राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के बाद कांग्रेस राजनीति में कोई ठोस संदेश देने में सफल नहीं हो रही थी, जिसके कारण कांग्रेस के कई नेता अमेठी के बारे में बोलने से किनारा करने लगे थे। अब राहुल गांधी अपने दादा फिरोज खान, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की विरासत को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। यहां सवाल यह नहीं हैं कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने रायबरेली को क्यों चुना, बल्कि सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों छोड़ा। क्या वास्तव में राहुल गांधी को फिर से अपनी पराजय का डर लगने लगा था? अगर यह सही है तो फिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी हर बार अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश क्यों करते हैं। उल्लेखनीय है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी में अपनी जमीन खिसकती दिखाई दी, तब उन्होंने एकदम सुरक्षित लगने वाली सीट केरल की वायनाड को चुना। वहां से चुनाव जीते जरूर, लेकिन अमेठी की हार कांग्रेस परिवार की हार थी, जिसे कांग्रेस आज तक भुला नहीं पाई है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाना खतरे से खाली नहीं था।

कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नामांकन जमा करने के समय जिस प्रकार से बड़े नेताओं का जमघट लगा, वह भले ही जनता में प्रभाव डालने के लिए किया हो, लेकिन इससे यह भी राजनीतिक संदेश सुनाई दे रहा है कि अब रायबरेली की सीट भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। यह इसलिए भी कहा जा सकता है कि वहां लगभग सभी बड़े नेता उपस्थित हुए। यहां तक कि प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कांग्रेस के विरासती राजनेता के तौर पर उपस्थित हुए। ऐसे में एक सवाल यह भी आता है कि एक ही परिवार के चार व्यक्तियों को कांग्रेस के बड़े नेताओं के रूप में प्रचारित करना निसंदेह कांग्रेस पर परिवारवादी होने को ही प्रमाणित करता है। जिस परिवारवाद के आरोप के कारण कांग्रेस असहज हो जाती है, आज कांग्रेस ने फिर से उसी रास्ते पर कदम बढ़ाने को अपनी नियति मान लिया है। हालांकि कांग्रेस ने आनन-फानन में राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाकर यह तो संदेश दिया ही है कि भारत में रायबरेली ही राहुल गांधी के लिए सबसे सुरक्षित लोकसभा सीट है। यहां कांग्रेस का परंपरागत मतदाता है, वहीं यह क्षेत्र नेहरू-गांधी परिवार की विरासत भी है। कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी विरासत को विस्मृत कर देता है, तो उसे नए सिरे से अपनी जमीन तैयार करनी पड़ती है। और अगर विरासत के आधार पर अपने कदम बढ़ाता है तो उसकी आधी राह आसान हो जाती है। राहुल गांधी के सामने तमाम सवाल होने के बाद भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी आधी बाधा को पार कर लिया है। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ इसलिए भी माना जाता है कि क्योंकि यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान दो बार सांसद रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी भी सांसद रहीं। अब पिछले पांच बार से सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव जीती हैं। मजेदार बात यह भी है कि वर्ष 1977 के आम चुनाव में जनता लहर में इंदिरा गांधी को भी पराजय का दंश भोगना पड़ा। उसके बाद एक बार भाजपा ने भी परचम लहराया है। इसलिए यह कहा जाना कि रायबरेली में कांग्रेस आसानी से विजय प्राप्त करेगी, कठिन ही है। आज कांग्रेस की स्थिति देखकर यह भी कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज की कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी जैसा नेता नहीं है। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती

भाजपा को संविधान विरोधी साबित करने का अभियान

राहुल गांधी आजकल भाजपा को संविधान विरोधी साबित करने में दिन-रात एक किए हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर आज आम नागरिक अपने संविधान को जान रहा है, पढ़ रहा है और उसके अनुरूप आचरण करना चाह रहा है तो उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास ही हैं, क्योंकि अब हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान को अब वेबसाइट पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। नए संसद भवन के उद्घाटन और सेंगोल स्थापना के अवसर पर सदन के सदस्यों को भी संविधान की मूल प्रति दी गई। कांग्रेस जो आज संविधान-संविधान का राग अलाप रही है, संविधान का सत्यानाश भी उसी कांग्रेस ने किया था। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान में मूलभूत परिवर्तन करके उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़कर उसकी आत्मा ही नष्ट कर दी। आपातकाल लगाकर अपनी विकृत तानाशाही मानसिकता का परिचय दिया और मनमर्जी से विपक्षी दलों की प्रदेश सरकारों को गिराया। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान एक परिवार का बंधक हो गया था व एक धर्मविशेष का तुष्टीकरण कर रहा था। इसी प्रकार कांग्रेस अयोध्या में प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि और उस पर बन रहे भव्य मंदिर के प्रति भी नकारात्मक रही है।

हैं, तब आज तो कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसा तो तब हुआ, जब उप्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए कांग्रेस उप्र में अच्छी खासी जीत हासिल करती थी। लेकिन अब उप्र का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। अब कांग्रेस के पास पहले जैसा वोटबैंक भी नहीं है, हालांकि इस चुनाव में सपा का समर्थन कांग्रेस के पास है, इसलिए चुनाव में सपा के कार्यकर्ता भी राहुल का प्रचार करेंगे। ऐसे में निश्चित ही कांग्रेस का वजूद बढ़ेगा ही, यह तय है, लेकिन कितना बढ़ेगा, यह कहने में जल्दबाजी ही होगी।

वर्तमान में कांग्रेस के लिए यह पेंचीदा सवाल ही था कि कांग्रेस की ओर से अमेठी और रायबरेली से किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए, क्योंकि इन दोनों सीटों पर प्रथम तो गांधी परिवार का पुख्ता दावा बनता था। इसलिए दोनों क्षेत्रों में से किसी एक से प्रियंका वाड्रा को चुनाव मैदान में उतारने की कवायद भी की जा रही थी, लेकिन प्रियंका को इस बार चुनाव लड़ने से दूर कर दिया। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस अमेठी के चुनाव को गंभीरता से लेगी, क्योंकि अब कांग्रेस का पूरा जोर राहुल गांधी को जिताने में लगेगा। राहुल गांधी को जिताना कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि अब राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। अगर कांग्रेस रायबरेली से चुनाव हारती है तो देश में कांग्रेस के बारे में गलत संदेश जाएगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आ रहा है कि राहुल गांधी पिछले चुनाव में भी दो स्थानों से चुनाव लड़े थे, जिसमें अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब वायनाड से उम्मीदवारी के बाद रायबरेली का रुख करके फिर से संदेह को जन्म दिया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार वायनाड का चुनाव बहुत ही टक्कर का माना जा रहा है। कुछ खबरें तो राहुल गांधी के हारने तक की बात कह रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए ही राहुल गांधी को फिर से दो स्थानों से चुनाव लड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी का उप्र से चुनाव लड़ना कोई नया नहीं है, वे अमेठी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए उनके नाम का जादू कोई नया प्रभाव छोड़ेगा, यह पूरी तरह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता।

स्वतंत्रता के बाद भारत में अभी तक जितने भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व में बना गठबंधन हर दृष्टि से कमजोर नजर आ रहा है। जबसे लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस व इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रचार आरंभ किया है तभी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी व उनके प्रवक्ता मीडिया एजेंसियों व टीवी चैनलों पर बैठकर केवल एक ही बहस कर रहे हैं कि अगर मोदी तीसरी बार 400 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर भाजपा संविधान को फाड़कर फेंक देगी, दोबारा चुनाव नहीं होंगे क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के एआई द्वारा बनाए गए डीप फेक वीडियो या फिर सम्पादित/डॉक्टर्ड वीडियो को आधार बनाकर झूठ फैला रहे हैं।

पिछले दिनों अमित शाह के ऐसे ही एक वीडियो के साथ आरक्षण के संबंध में दुष्प्रचार किया गया, हालांकि अब इस पर दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही आरंभ कर दी है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फर्जी वीडियो प्रकरण को अपने पक्ष में मोड़कर मुद्दा बनाने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। साथ ही वे संविधान और आरक्षण के नाम पर विगत 70 साल में पिछली सरकारों ने जो किया उसे भी बेनकाब कर रहे हैं।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आरक्षण विरोधी होने का दावा कर अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच गबठबंधन हुआ था तब इन दलों ने एक साक्षात्कार के आधार पर संघ के खिलाफ विषवमन किया था। बसपा नेत्री मायावती ने एक पुस्तिका प्रकाशित करवाकर घर-घर तक बंटवाई थी और बताया गया था कि संघ किस प्रकार से आरक्षण विरोधी है। अब समय बदल चुका है। यह 2024 की बदली हुई भाजपा और संघ है जो दुष्प्रचार के प्रति पूरी तरह सतर्क और सशक्त है। इस बार कांग्रेस नेताओं का यह दांव जमीनी धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ हमेशा संविधान सम्मत आरक्षण का पक्षधर रहा है। संघ का मानना है कि जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा या आरक्षण देने के कारण बने रहेंगे, तब तक आरक्षण जारी रहे। संघ प्रमुख ने कहा कि उन्होंने एक वीडियो के बारे में सुना है जिसमें कहा गया है कि संघ आरक्षण के खिलाफ है। संघ आरक्षण का कभी विरोधी नहीं रहा है, किंतु यह उसके खिलाफ विमर्श स्थापित किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि संघ व भाजपा को आरक्षण व संविधान विरोधी साबित कर वह चुनावी किला फतह कर सकती है।

आज की भाजपा अब 2014 के पहले वाली भाजपा नहीं रही कि उसे झूठे नैरेटिव चलाकर डराया, धमकाया या हराया जा सकता है। अब भाजपा नेता हर बात के लिए सतर्क रहते हैं। गुजरात के एक सांसद रूपाला के बयान के बाद नैरेटिव चलाया गया कि राजपूत और क्षत्रिय भाजपा से नाराज हो गए हैं किंतु गुजरात में मोदी व भाजपा नेताओं की जनसभाओं में जैसी भीड़ आ रही है, उससे लग रहा है कि राजपूत व क्षत्रियों की भाजपा से नाराजगी का नैरेटिव भी छिन्न-भिन्न हो चुका है।

● इन्द्र कुमार

ईवीएम पर संदेह

कांग्रेस और विपक्ष बार-बार ईवीएम पर ही संदेह पैदा कर रहा है, किंतु ईवीएम का यह दावा अब सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो चुका है। पहले दो चरणों में कम मतदान का हवाला देकर विरोधी दलों ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिया कि कम मतदान का मतलब है मोदीजी हार गए, हार गए। किंतु जब चार दिन बाद चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े सार्वजनिक किए तो विपक्ष एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर संदेह करने लग गया। विपक्षी दलों के नेता सोशल मीडिया पर आकर ईवीएम-ईवीएम करने लगे और कहा कि चुनाव आयेग ने खेल कर दिया-खेल कर दिया। इसी राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का अभियान प्रारंभ कर दिया। इस आभासी मुद्दे को टूलकिट के नए टूल के रूप में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर उठाया जा रहा है। कोविशील्ड के प्रकरण में जनहित याचिका दायर करने वाले दलाल भी सक्रिय हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कोविशील्ड से नुकसान बहुत ही कम हुआ है जबकि लाभ अधिक हुआ है।

बिना मुद्दे का चुनाव, सिर्फ मोदी फेस

छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर लोकसभा के लिए वोटिंग हो गई। पिछले चार चुनावों में छत्तीसगढ़ में एक बात सुकून देने वाली है कि वोटिंग का परसेंट हर बार एक-दो प्रतिशत बढ़ता रहा। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 71.06 प्रतिशत वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 78.78 फीसदी सरगुजा और 78.43 प्रतिशत रायगढ़ में मतदान हुआ है। वहीं, बिलासपुर में सबसे कम 63.95 प्रतिशत वोट पड़े हैं। इससे पहले तीन चुनावों में लगातार वोटिंग बढ़ी थी। 2009 में 55.3 फीसदी, 2014 में 69.5 प्रतिशत और 2019 में 73. 8 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। यानी पिछले 15 सालों में करीब 18 प्रतिशत वोटिंग बढ़ी है। सशक्त लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है।

पिछले चुनावों के विपरीत इस बार का चुनाव मुद्दा विहीन हो गया लगता है। 2009 और 2014 में यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा जबरदस्त उछला था। इस दौरान 2-जी स्पेक्ट्रम, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला समेत कई घोटालों की चर्चा होती थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो 2019 में पांच साल पूरे करने के बाद राफेल का मुद्दा पूरे देश में छाया। लेकिन पुलवामा की आतंकी घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उस पर कांग्रेस की बयानबाजियों ने चुनाव का रुख मोड़ दिया। 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव बना, जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ मोदी का चेहरा है और अगर मुद्दे हैं, तो कांग्रेस उसे अब तक लोगों के बीच पहुंचा नहीं पाई। कांग्रेस हर मंच से महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी, दलित, सांप्रदायिकता पर बात करती रही, लेकिन ये बातें घरों तक नहीं पहुंच पाईं। इन सबके जवाब में भाजपा मोदी का चेहरा सामने ले आई।

छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जो हाल देश के बाकी हिस्सों का है, कमोबेश वही हाल छत्तीसगढ़ का है। जब प्रत्याशियों की घोषणा की गई, तो कई चेहरे अप्रत्याशित थे। दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडेय को छोड़कर सभी नए चेहरे सामने लाए गए। ये ऐसे नाम थे, जो बहुत ज्यादा चर्चा में कभी नहीं रहे, जबकि इनके सामने कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा। यानी भाजपा को मोदी के चेहरे पर इतना भरोसा था कि टिकट मिलेगा, तो संगठन जिताकर ले आएगा। दिग्गजों को उतारने के बाद भी आखिरी तक कांग्रेस में इस आत्मविश्वास की कमी दिखती रही। चुनाव से पहले ये चर्चा काफी तेज थी कि, कांग्रेस के नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। इस फेहरिस्त में भूपेश बघेल का भी नाम था। हालांकि इन चर्चाओं को उस समय विराम लग गया, जब नामों की घोषणा हुई। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री समेत दिग्गज पूर्व मंत्री व पूर्व विधायकों को चुनावी समर में उतारा। कारण शायद ये हो सकता है कि चर्चित नामों को उतारने से पब्लिक के बीच में ज्यादा मेहनत की जरूरत न हो।

4 बड़े नक्सल एनकाउंटर

लोकसभा चुनाव के बीच 4 बड़े नक्सल एनकाउंटर हुए। 30 अप्रैल को नारायणपुर में अबूझमाड़ के टेकामेटा गांव में मुठभेड़ हुई थी। जिसमें 63 लाख के 10 नक्सली मारे गए थे। इनमें एक 25 लाख रुपए का ईनामी नक्सली जोगन्ना भी था। 16 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटे बेठिया के हापाटोला इलाके में मुठभेड़ हुई। यहां फोर्स ने 1 करोड़ 78 लाख रुपए के कुल 29 नक्सलियों को ढेर किया था। यह नक्सलियों के खिलाफ सबसे सफल ऑपरेशन था। 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़-तेलंगाना राज्य की सीमा पर मुठभेड़ हुई थी। इसमें 3 नक्सली मारे गए थे। 2 अप्रैल को बीजापुर के करचोली में मुठभेड़ हुई। यहां पुलिस ने 13 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर में 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक पुलिस ने कुल 91 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें नारायणपुर और कांकेर की मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों पर कुल 2 करोड़ 41 लाख रुपए का इनाम था।

पहले और दूसरे चरण तक तो हर तरफ मोदी-मोदी की गूंज थी, लेकिन तीसरे चरण में यह चमक थोड़ी फीकी हुई। राम मंदिर, धारा 370, हिंदू-मुस्लिम जैसे फैक्टर ज्यादा नहीं दिखे। ये कहा जा सकता है कि तीसरे चरण के आते-आते मोदी के नाम ने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के पास इस वैक्यूम का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वोटर्स के पास विकल्प मोदी का नाम हो सकता है। हालांकि यह फ्लक्चुएशन बहुत कम ही रहा होगा, लेकिन ये हुआ है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन मजबूती के साथ विकल्प दे पाता तो उनके लिए स्थिति थोड़ी ठीक हो पाती। फिर भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिन नतीजों की उम्मीद कर रही थी, वो आसानी से उन्हें हासिल नहीं होंगे। 2019 में 9 भाजपा और 2 कांग्रेस के आंकड़े रिपीट भी हो जाएं, तो संशय नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने तीसरे चरण के मतदान के बाद दावा किया कि जनता ने भाजपा को अभूतपूर्व जनसमर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद के बाद अब जनता ने दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा और सरगुजा में भी भाजपा के पक्ष में भारी संख्या में स्वस्फूर्त मतदान किया है। भाजपा को विश्वास है कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है।

तीनों चरणों के मतदान के रुझान से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्ण उत्साह और समर्पण के साथ ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर भाजपा प्रचंड मतों से विजयी होगी। नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, कांग्रेस के छलावों, झूठ और दंभपूर्ण अमर्यादित टिप्पणियों के दंश से लहूलुहान छत्तीसगढ़ की जनता ने अब छत्तीसगढ़ को कांग्रेसमुक्त राज्य बनाने के अभियान पर पक्की मुहर लगाई है। देव ने कहा कि बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं भूपेश सरकार के भ्रष्ट कारनामों ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा में जनाक्रोश बढ़ाने का काम किया। दूसरी तरफ, प्रदेश के गृहमंत्री और महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू की कार्यप्रणाली से न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता, अपितु साहू समाज में भी आक्रोश साफ नजर आया है। तीसरे चरण के मतदान के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते हुए अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को मतदान करके निभाया है।

● रायपुर से टीपी सिंह

मटका फोड़ राजनीति

राजनीति में यह कहना मुश्किल है कि किस पार्टी या नेता को किस चीज से फायदा होगा और उस पार्टी की जीत आसान होगी। सामने वाले उम्मीदवार को किसी वाक्य या घटना से अचानक सहानुभूति मिल जाती है और अंतिम समय में उसका पलड़ा भारी हो जाता है। राज्य के बड़े नेता शरद पवार के मामले में भी कुछ ऐसा है। इस समय पवार की सेहत को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, साथ ही उसे मटके फोड़ने से भी जोड़ा जा रहा है। पूरे मामले को देखें तो बीते चुनाव का जिक्र करना भी जरूरी है।

शरद पवार ने 2019 चुनाव में सतारा लोकसभा क्षेत्र से श्रीनिवास पाटिल को उम्मीदवार बनाया। जहां ऐसा माहौल था कि यहां छत्रपति उदयनराजे भोसले को चुना जाएगा, वहीं शरद पवार ने श्रीनिवास पाटिल के प्रचार के लिए बैठक की। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और शरद पवार ने बारिश में भीगते हुए बैठक जारी रखी। 80 साल के एक नेता ने बारिश में भी अपने उम्मीदवार के लिए सभा की, जिसका मतदाताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उस निर्वाचन क्षेत्र में श्रीनिवास पाटिल की जीत हुई। अब एनसीपी कांग्रेस में दो गुट हो गए हैं। इसलिए इस बार का चुनाव बेहद कड़ा होने वाला है। बारामती लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक अति उत्साही कार्यकर्ता ने प्रचार सभा में मटके फोड़ दिए। दरअसल किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आग लगाने से पहले मटका फोड़ा जाता है। इससे यह संदेश दूर-दूर तक फैल गया कि इन कार्यकर्ताओं द्वारा की गई उदासीनता किसी व्यक्ति की मृत्यु का इंतजार कर रही है। इससे जनमानस में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई।

वहीं, संयोग से शरद पवार बीमार पड़ गए हैं। महाराष्ट्र के सभी लोग जानते हैं कि शरद पवार कई सालों से एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन शरद पवार की इस बीमारी और उनके बारे में दिए गए बयानों से एक बार फिर महाराष्ट्र में शरद पवार के लिए सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है। किसी व्यक्ति के गलत काम या किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण उत्पन्न सहानुभूति की लहर उनकी पार्टी या उम्मीदवार की जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक विजय चोरमारे ने आशंका जताई है कि एक बार फिर शरद पवार की बीमारी से उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक विजय चोरमारे ने आशंका जताई है कि एक बार फिर शरद पवार की बीमारी से उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र में जहां शरद पवार बीमार हैं, वहीं अजित पवार का गुट उनके मामले को रफा-दफा कर रहा है। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में अगर कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराष्ट्र में शरद पवार के प्रति कई वर्षों से सहानुभूति रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी के सचिव दत्ताजीराव देसाई का कहना है कि पिछले 45 वर्षों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में शरद पवार द्वारा किए गए कार्यों के प्रति लोगों के मन में सम्मान है। अगर कोई शरद पवार के संबंध में इस तरह का व्यवहार करेगा तो इससे शरद पवार और एनसीपी को ही फायदा होगा। पिछले चुनाव में शरद पवार ने बारिश में भाषण दिया था, इसलिए वोटों में इसका अच्छा नतीजा मिला। अब संयोगवश जब शरद पवार बीमार हैं तो विपक्ष ने मटके फोड़कर लोगों में और असंतोष पैदा कर दिया है। देसाई ने यह भी दावा किया है कि इसका फायदा हमें यानी शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी को होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

इस संदर्भ में बोलते हुए एनसीपी के अजित पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अगर किसी ने इस तरह का व्यवहार किया है तो यह अनुचित है। हम न केवल शरद पवार बल्कि देश के सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यदि कोई प्रचार सभा में मटके फोड़ता है तो वह कृत्य अनुचित है। किसी एनसीपी कार्यकर्ता ने वह हरकत नहीं की होगी। जिसने भी ऐसा किया हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, अगर कोई सोचता है कि इससे सहानुभूति की लहर पैदा होगी, तो ऐसा नहीं होगा। चुनाव सहानुभूति पर नहीं विकास पर लड़ा जाता है। इसलिए, राज्य की जनता ऐसी सहानुभूति के आगे झुके बिना निश्चित रूप से विकास के लिए वोट करेगी। श्रीवास्तव ने दावा किया है कि बारामती में भी एनसीपी उम्मीदवार को अच्छे वोट मिलेंगे और जीत होगी।

महाराष्ट्र की राजनीति में गजब का तमाशा देखने को मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिन दोस्तों का चुनाव प्रचार किया करते थे इस चुनाव में वे दुश्मन बन गए हैं और जिन्हें अपना दुश्मन कहते थे वे इस चुनाव में दोस्त बनकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसी गजब की तस्वीर महाराष्ट्र में ही दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजित पवार, शरद पवार, अशोक चव्हाण जैसे तमाम नेता हैं। महाराष्ट्र में अब तक के लोकसभा चुनाव शिवसेना और भाजपा मिलकर लड़ते थे। इनके सामने कांग्रेस और एनसीपी थी। लेकिन पिछले पांच साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर हुए। भाजपा की सहयोगी शिवसेना और कांग्रेस की एनसीपी में बड़ी फूट पड़ गई। कांग्रेस फूटी नहीं, परंतु पार्टी के कई सारे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी।

● बिन्दु माथुर

नतीजों पर निर्भर है महायुति का भविष्य

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम राज्य में और अधिक उद्योग लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वेदांता-फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हुआ, तब मेरी सरकार को सिर्फ 2 महीने हुए थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। महाराष्ट्र उद्योग अनुकूल राज्य है और आने वाले समय में कई बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट यहां लगेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने राज्य में महायुति कितनी दमदार है, आम चुनाव में शिवसेना का प्रदर्शन कैसा रहेगा जैसे सवालों के जवाब दिए और अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं हमारी सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए काम से बहुत खुश हूं।

नेतापुत्रों का क्रिकेट प्रेम

राजस्थान की सियासत में अब काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजनीति के साथ अब नेता क्रिकेट की सियासत में भी काफी इंटरेस्टेड दिखाई देने लगे हैं। बीते आंकड़ों पर नजर डालें, तो राजस्थान के खेल जगत में भी कांग्रेस और भाजपा के नेताओं और उनके बेटों का हस्तक्षेप बढ़ा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसको लेकर भी बीते दिनों जमकर सियासत हुई। वहीं खेल से जुड़े हुए लोग राजनीति घुसने को सही नहीं मान रहें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति के कारण क्रिकेट प्रभावित हो सकता हैं।

राजस्थान की सियासत के साथ अब नेताओं का क्रिकेट जगत में भी दखल बढ़ता जा रहा हैं। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं के पुत्र अब खेल जगत में विभिन्न नियुक्तियों पर काबिज होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में यही देखने को मिला। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बने। इसके बाद से लगातार राजनीतिक गतिविधियां खेल जगत को प्रभावित करने लगी हैं। भजनलाल सरकार में भी मंत्री और भाजपा नेताओं के बेटे अब क्रिकेट एसोसिएशन में विभिन्न पदों पर नजर आ रहे हैं। राजस्थान में करीब चार महीने पहले भाजपा की सरकार बनने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन की सत्ता हासिल करने को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। भजनलाल शर्मा सरकार के दो मंत्रियों व एक वरिष्ठ भाजपा नेता के पुत्र जिला क्रिकेट संघों में पदाधिकारी बनने के साथ ही अब आरसीए का अध्यक्ष बनने को लेकर लॉबिंग में जुटे हैं। भाजपा के सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय सिंह नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने और अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुत्र पवन दिलावर बारां जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष बन गए हैं। प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता विधानसभा में पूर्व प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह चूरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन और जयपुर स्थित गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के पुत्र अभिषेक डूंगरपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं। इनके अतिरिक्त कई जिला क्रिकेट एसोसिएशनों में भाजपा नेता विभिन्न माध्यमों से अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। जिला क्रिकेट एसोसिएशनों में पदाधिकारी बनने के बाद अब मंत्रियों व नेताओं के पुत्रों में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है।

उल्लेखनीय है कि पिछली कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में क्रिकेट की राजनीति से जुड़े पदाधिकारियों ने वैभव के खिलाफ गुटबाजी पैदा कर दी। इस बीच, करीब चार महीने पहले प्रदेश में सरकार बदलने के बाद वैभव और कांग्रेस से जुड़े नेताओं व उनके स्वजनों को आरसीए और जिला एसोसिएशनों में गुटबाजी उत्पन्न करके हटा दिया गया। इसके बाद भाजपा सरकार के मंत्रियों के स्वजनों को जिला क्रिकेट एसोसिएशन में पदाधिकारी बनाया गया।

राजस्थान की राजनीति में कई दिग्गज नेता हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। अब वो अपनी विधानसभा सीट पर अपने बेटों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन सभी का खेल की दुनिया से भी गहरा नाता है। अशोक गहलोत ने अपने बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बनवाया और दो बार लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया है। इसी राह पर दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर, प्रमोद जैन भाया भी चल दिए हैं। इनके बेटों की जिले स्तर के खेल में एंट्री हो चुकी है। रोचक बात यह कि ये वो नेता हैं जो अपनी पार्टी में सबसे मजबूत स्थिति में हैं। कई बार के विधायक और सांसद रह चुके हैं। इतना ही नहीं ये सभी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अपनी बनी बनाई राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेटों को देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी से भाजपा के विधायक हैं। इनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। इनके बेटे पवन दिलावर बारां जिला क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। पवन युवा मोर्चा के कोटा संभाग संयोजक भी हैं। सूत्रों का कहना है कि मदन दिलावर रामगंज मंडी सीट से अपने बेटे को चुनाव में उतरने के गुर सिखा रहे हैं।

राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर लोहावट से भाजपा के विधायक हैं। इनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। इनके बेटे धनंजय सिंह खींवसर आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। गजेंद्र नागौर या लोहावट से धनंजय को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। इसलिए बेटे की एंट्री राजनीति से पहले खेल में करा दी गई है। अगले चुनाव में धनंजय राजनीति में दिख सकते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुरुं से कई बार विधायक रह चुके हैं। राजस्थान सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। राजेंद्र की उम्र 70 साल से अधिक है। इनके बेटे चुरुं जिले के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इसलिए अब सूत्र बता रहे हैं कि चुरुं विधानसभा सीट से पराक्रम चुनाव मैदान में देखे जा सकते हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

खेल में राजनीति के घुसने से पड़ सकता है प्रभाव

राजस्थान में पिछले दो दशक से क्रिकेट जगत में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं का हस्तक्षेप बढ़ गया है। वसुंधरा सरकार के दौरान उनके करीबी रहे अमीन पठान आरसीए के अध्यक्ष रहे, जबकि गहलोत सरकार के दौरान उनके बेटे वैभव ने आरसीए की कमान संभाली। अब भजनलाल सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ऐसे में क्रिकेट जगत में राजनीति के घुसने को सही नहीं माना जा रहा है। क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि राजनीति घुसने से न केवल अनावश्यक हस्तक्षेप होगा, बल्कि योग्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा या नहीं, इस पर संदेह हो सकता है। इधर, भजनलाल सरकार के मंत्री और भाजपा नेताओं के पुत्रों की भी क्रिकेट बोर्ड में भूमिका नजर आ रही है।

भाजपा और सपा की अग्नि परीक्षा

उप्र से बड़ी आस लगाए बैठी भारतीय जनता पार्टी के सामने तीसरे चरण के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए 2019 में जीती हुई सीटों को बचाए रखने की है। तीसरे चरण में यादव बहुल जिन 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान हुआ, वहां 2019 में भाजपा ने 8 सीटें जीती थीं। पहले के दो चरणों में 16 सीटों पर हुए मतदान में रालोद का साथ मिला जबकि तीसरे चरण के इन क्षेत्रों में भाजपा का कोई सहयोगी दल नहीं है। हालांकि सबसे बड़े यादव महासभा को अपने पाले में कर भाजपा यादव वोटों में सेंध लगाने का लगातार प्रयास करती रही है। मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव उप्र के पिछड़ों को पार्टी के पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अनुपस्थिति में पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरकर समाजवादी पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। सपा के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसा बन चुका है।

भाजपा ने उप्र की 80 सीटों में से 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2014 में भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, लेकिन 2019 में सीटों की संख्या घटकर 62 रह गई थी। दिल्ली की गद्दी पर तीसरी बार काबिज होने के लिए भाजपा ने उप्र और बिहार पर अच्छी खासी मेहनत की है और पुराने एनडीए के सहयोगियों को एक बार फिर से जोड़ा है। उप्र में परचम लहराने के लिए भाजपा ने अपना दल, ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद की पार्टी से गठबंधन किया है, वहीं पश्चिमी उप्र में जाट मतदाताओं को पाले में करने के लिए रालोद को वापस एनडीए में लाई है। तीसरे चरण में प्रदेश की जिन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। इनमें भाजपा ने 2014 में 10 में से 7 सीटें जीती जबकि 2019 में उप्र के बाकी क्षेत्रों से भाजपा की सीटें कम हुईं। लेकिन यादव बहुल इन क्षेत्रों में भाजपा ने अपनी साख मजबूत करते हुए 10 में से 8 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। समाजवादी पार्टी केवल दो सीटों संभल और मैनपुरी तक सिमटकर रह गई थी। संभल सीट पर 2014 में भाजपा को जीत मिली थी लेकिन मैनपुरी सीट 1996 से ही समाजवादी पार्टी के पास है। तीसरे चरण वाले क्षेत्र में ओबीसी का बोलबाला है, इनमें यादव, लोध, काछी, शाक्य, मुराव समुदाय के लोग शामिल हैं। इसके अलावा यहां मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में दखल रखते हैं। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूंऔर संभल जैसी लोकसभा सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक स्थिति में है। यहां मुस्लिम वोट मिलने पर सपा उम्मीदवार मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। संभल, बरेली, आंवला, बदायूं, फिरोजाबाद की सीट पर भी मुसलमान मतदाता अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हैं। एटा में लोध मतदाता निर्णायक हैं, जबकि काछी, शाक्य और मुरई समुदाय का एटा, बदायूं और मैनपुरी में प्रभाव है। समाजवादी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनावों में बिना मुलायम सिंह के चुनाव मैदान में है।

शायद इसलिए भी अखिलेश यादव के लिए यह कड़ी परीक्षा है। सपा के गठन के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए, उसमें मुलायम की बड़ी भूमिका रहती थी। उप्र में विपक्षी गठबंधन को अखिलेश लीड कर रहे हैं। पिछले दो लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में सपा कुछ खास नहीं कर पाई है। जमीन से जुड़े नेता होने के कारण ही मुलायम को धरतीपुत्र कहा जाता रहा है। वह पार्टी को यादवों की पार्टी बनाने के साथ ही पिछड़े वर्ग की पार्टी भी बनाए रख सके। यह इसलिए संभव हो सका कि पिछड़े वर्ग के नेताओं से उनका सामंजस्य बेहतर रहा। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज में यादव बहुल सीट पर मजबूत एमवाई समीकरण के कारण वह हमेशा मैदान में बाजी मारते रहे। यादव के आलवा दूसरी प्रभावशाली पिछड़ी जातियों पर पकड़ से वह हमेशा आगे रहे।

अखिलेश की राजनीति में कभी-कभी ऐसा लगता है कि पार्टी के कोर वोटर्स यादव और मुसलमान भी कहीं उनका साथ न छोड़ दें। आज अखिलेश के साथ आजम खान कितना हैं, ये भी समझ में नहीं आता। ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, दारा सिंह चौहान, केशव देव मौर्य आदि साथ छोड़ चुके हैं। अपना दल कमेरावादी से भी उनका संबंध खराब हो चुका है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी उसके साथ नहीं है। पिछली बार जब सपा ने बसपा और रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो इन दस में से दो सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि इस बार कांग्रेस के साथ समझौता हुआ है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मैदान में उतर आने के बाद लगभग सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। सपा ने इस बार परिवार के बाहर के यादवों को टिकट नहीं दिया है। यादव सपा के मुख्य समर्थक माने जाते हैं लेकिन केवल परिवारजनों को ही टिकट दिए जाने के कारण यादवों में भी रोष है। भाजपा और बसपा इस मसले को जोर-जोर से प्रचारित कर रहे हैं। मालूम हो कि सपा ने केवल पांच प्रत्याशी यादव बिरादरी के उतारे हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव, मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव, आजमगढ़ से चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

सीएम के साथ मंत्रियों की साख दांव पर

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उप्र की योगी सरकार तथा उसके 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। यह चुनाव इन मंत्रियों के साथ-साथ योगी सरकार में प्रतिष्ठा और जन विश्वास की कसौटी को भी परखने वाले हैं। भाजपा में भी अंदरखाने रण मची हुई है। कई सीटों पर भाजपा दो फाड़ है। आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा के ही विधायक चौधरी बाबूलाल भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के विरोध में खड़े हैं। राजकुमार चाहर के विरोध में उन्होंने अपने बेटे रामेश्वर चौधरी को निर्दलीय के रूप में मैदान में उतार दिया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए भाजपा के चाणक्य अमित शाह लगातार कई बार बड़े नेताओं के साथ बैठकें कर चुके हैं। बहरहाल सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र की इन 10 सीटों पर हैं, क्योंकि यहां जो बुनियाद रखी जाएगी। इसका असर खासकर पिछड़ी जातियों के बीच अगले चरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कोर वोटर के लिहाज से यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी का अपना इलाका है। मुलायम सिंह की अगुवाई में मुस्लिम और यादव बहुल इन सीटों पर ही काबिज होकर समाजवादी पार्टी ने अपना राजनीतिक झंडा बुलंद किया था। पिछले दो बार से मुंह की खा रही समाजवादी पार्टी अगर अबकी बार जीतने से चूक जाती है तो उसे हमेशा के लिए अपनी जमीन खोने का डर होना स्वाभाविक है।

फिर जागी जाति की राजनीति

> ## एनडीए को मोदी से ही उम्मीद
>
> नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। तीसरे के लिए मैदान में हैं। इस बीच जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, तीन तलाक का कानून खत्म करने, अयोध्या में राम मंदिर और भारत की वैश्विक साख-पहचान जैसे उनकी सरकार के कई उल्लेखनीय कामों के लोग मुरीद हुए तो खासा तादाद उनकी भी है, जो अपेक्षाओं पर खरा न पाकर मोदी के विरोधी बन गए हैं। फिर भी आज की तारीख में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता और एनडीए में शामिल उनके दलों को अगर नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है तो जनता का मिजाज भी इसी अनुरूप होना चाहिए। पर, जातीय भंवर में फिर से उलझ चुके बिहार के लोगों के मन की थाह पाना मुश्किल है। लोग उम्मीदवारों की जाति देख रहे हैं। दल के शीर्ष नेतृत्व की जाति निहार रहे हैं। नरेंद्र मोदी का काम भी देख रहे हैं। मसलन नतीजे के बारे में अनुमान लगाना अब आसान नहीं रह गया है।

बिहार में लोकसभा का चुनावी परिदृश्य पिछले दो चुनावों की तरह साफ नहीं है। पहली बार परिवर्तन के लिए लोगों ने मोदी पर भरोसा किया तो दूसरी बार मोदी ने लोगों का खुद विश्वास जीता। दोनों बार जातीय किलेबंदी वैसी असरदार नहीं रही, जैसी इस बार लालू यादव की मौजूदगी से विपक्षी गठबंधन ने कर दी है। बिहार के चुनावी रंग को समझना चुनावी-राजनीतिक विशेषज्ञों-विश्लेषकों के लिए इस बार कठिन लग रहा है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में ऐसी स्थिति नहीं थी। इसलिए कि कांग्रेस के लंबे राजकाज से ऊब चुके लोगों को नरेंद्र मोदी का नए चेहरे का आकर्षण था। उन्हें दूसरा कार्यकाल देने में भी किसी को हिचक नहीं थी। इसलिए कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की जो दिशा पहले कार्यकाल में तय की थी, लोगों को वह पसंद आया था। तीसरे कार्यकाल के लिए इस बार भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने मोदी के चेहरे पर ही भरोसा किया है। सच कहें तो पहले से कहीं अधिक भरोसा एनडीए को इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। और, यह भी सच है कि भाजपा समेत तमाम एनडीए नेताओं के पास मोदी नाम केवलम के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है।

नीतीश कुमार पर भी बिहार के लोगों को नरेंद्र मोदी जैसा ही कभी भरोसा था। वर्ष 2005 में भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली थी। उनके मुख्यमंत्री रहते 24 साल बीत गए। यानी अवधि के हिसाब से नीतीश कुमार का यह चौथा कार्यकाल है। यह अलग बात है कि कई बार खेमा बदलने के कारण इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जिस तरह 2005 से 2015 तक बिहार के लोगों ने नीतीश को आइडियल स्टेट्समैन के रूप में देखा था, उस पर 2020 में कोहरा छा गया। इसकी मूल वजह नीतीश कुमार का बार-बार पाला बदल की राजनीति रही। उम्र और औकात में नीतीश अब जनता की नजरों में खारिज होने लगे हैं। उनका प्रभाव अब वैसा नहीं दिखता, जैसा 2005 से 2015 के दौरान था। अगर बिहार की राजनीति का रंग समझने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं तो इसका बड़ा कारण यही है कि अब जनता के वोट खींचने में नीतीश कुमार मददगार नहीं रह गए हैं। सच तो यह है कि अब उनके सामने भी वोट के लिए नरेंद्र मोदी की ओर टकटकी लगाए रहने की नौबत है।

एनडीए के घटक दलों ने आंख मूंदकर नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है। इस भरोसे का एक ही उदाहरण काफी है। हर बार एनडीए के घटक दल अलग-अलग घोषणापत्र जारी करते थे। यह पहला मौका है, जब ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ भाजपा ने घोषणापत्र जारी किया। बाकी दलों को उसी घोषणापत्र को अपना मानने के लिए विवश होना पड़ा। यह गठबंधन धर्म और सांगठनिक एकता के लिहाज से अच्छा भी है। अलग-अलग राग अलापने से तो कई बार गठबंधन में बेमेल वादों की हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे समझने के लिए बिहार में एक उदाहरण काफी है। सीएए, एनआरसी और यूसीसी का नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहते भी कभी समर्थन नहीं किया। फर्ज कीजिए कि अगर जेडीयू का घोषणापत्र अलग होता तो नीतीश उसमें इन मुद्दों पर क्या कहते। वैसे भी नीतीश को इस बात का गुमान है कि भाजपा के साथ रहने के बावजूद उन्होंने मुसलमानों का अहित नहीं होने दिया। वे इस बात को आजकल अपनी हर चुनावी सभाओं में दोहराते हैं।

बिहार के राजनीतिक रंग में भंग डालने का काम इस बार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने कर दिया है। जातीय गोलबंदी के नाम पर बिहार में अस्तित्व में आया इंडी अलायंस का प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को भी भाजपा की तरह अपना कोर एजेंडा पता है। उसे अपने कोर वोटर की भी जानकारी है। भाजपा अगर हिंदुत्व, मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान जैसे कोर एजेंडे के सहारे दशक भर से लगातार कामयाबी हासिल करती रही है तो आरजेडी को भी अपने कोर वोटर और एजेंडे की अच्छी समझ है। उसे पता है कि 17 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम और 14 प्रतिशत से अधिक यादव (लगभग 32 प्रतिशत) वोटर तो कालांतर से उसके अपने ही हैं। अगर अन्य जातियों में भी उसने पांच-सात प्रतिशत वोटों का बंदोबस्त कर लिया तो उसे एनडीए को टक्कर देने में न सिर्फ आसानी होगी, बल्कि लगातार बिगड़ती गई अपनी हालत सुधारने में भी उसे सहूलियत होगी।

इसी रणनीति के तहत आरजेडी ने इस बार अपने कोटे की 26 सीटों में तीन सीटें तो निषाद समुदाय का नेतृत्व करने वाले मुकेश सहनी की वीआईपी को दे दीं। यादवों को 8 तो मुसलमानों को दो सीटें दी हैं। दो सवर्णों को भी आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। भूमिहार और कुशवाहा जाति पर पहली बार आरजेडी ने भरोसा किया है। हालांकि लालू को मात देने के लिए एनडीए ने भी इस बार आठ यादवों को मौका दिया है। दोनों गठबंधनों ने कोइरी जाति के 11 उम्मीदवार उतारे हैं। यानी बिहार में एनडीए और इंडिया ने सम्मिलित रूप से 16 यादवों और कोइरी जाति के 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आश्चर्य की कोइरी जाति की आबादी करीब पांच प्रतिशत ही बिहार में है। जातीय गोलबंदी दोनों गठबंधनों-एनडीए और इंडिया की ओर से जबरदस्त हुई है। रही बात चेहरे की तो बिहार में स्थानीय नेतृत्व को सिर्फ इंडिया के लोग ही देख रहे हैं। उनके सामने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का चेहरा है। राहुल के चेहरे की चमक बिहार में तेजस्वी के मुकाबले धुंधली है। एनडीए में लोग इस बार नीतीश के चेहरे पर भरोसा नहीं कर रहे। यहां तक कि भाजपा समर्थकों को भी अब नीतीश पर भरोसा नहीं है।

विश्वसनीयता का यह संकट खुद नीतीश कुमार ने खड़ा किया है। खैर, एनडीए के सभी दलों को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा है। इस भरोसे की बड़ी वजह यह है कि बिहार में पिछले दो लोकसभा चुनावों में एनडीए को जो कामयाबी मिली, उसके पीछे नरेंद्र मोदी का ही चेहरा था। तभी तो बिहार में 15 साल राज करने वाले आरजेडी की हालत 2004 के बाद लगातार बिगड़ती गई। वर्ष 2004 में आरजेडी ने लोकसभा की 22 सीटें जीती थीं। 2009 में आरजेडी धड़ाम होकर चार सीटों पर आ गई। 2019 में तो इसे शून्य पर आउट हो जाना पड़ा।

● **विनोद बक्सरी**

प्लास्टिक की पनाहगाह बना समुद्र तल

क्या आप जानते हैं कि अब तक 1,10,00,000 टन प्लास्टिक महासागरों की अथाह गहराइयों में जमा हो चुका है। यह पहला मौका है जब वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि समुद्र तल में अब तक कितना प्लास्टिक कचरा जमा हो चुका है। इस बारे में कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाईजेशन (सीएसआईआरओ) और टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नया अध्ययन किया है, जिसके नतीजे जर्नल ओशियोनोग्राफिक रिसर्च पेपर्स में प्रकाशित हुए हैं। बता दें कि कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाईजेशन ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी एजेंसी है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जिम्मेवार है।

रिसर्च के मुताबिक हर मिनट कचरे से भरे एक ट्रक के बराबर प्लास्टिक समुद्र में समा रहा है। जो पर्यावरण और जैवविविधता के लिए बेहद गंभीर संकट बन चुका है। वहीं आशंका जताई गई है कि 2040 तक प्लास्टिक का उपयोग बढ़कर दोगुना हो सकता है। ऐसे में समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नजरिए से यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि यह प्लास्टिक कैसे और कहां जाता है। इस बारे में सीएसआईआरओ के वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक डॉक्टर डेनिस हार्डेस्टी का कहना है कि यह पहला मौका है जब हमने समुद्र तल तक पहुंचने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा का अनुमान लगाया है। समुद्र तल पर पहुंचकर यह प्लास्टिक, छोटे टुकड़ों में टूटने और समुद्री तलछट के मिलने से पहले वहीं जमा हो जाते हैं। उनका आगे कहना है कि, हम यह तो जानते हैं कि हर साल लाखों टन प्लास्टिक महासागरों में प्रवेश करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि इसका कितना हिस्सा समुद्र तल पर जमा होता है। अपने इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक से जुड़े इन्हीं रहस्यों का खुलासा किया है।

एक अनुमान के मुताबिक 192 देशों से निकला करीब 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा हर साल समुद्रों में समा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शोधों से पता चला है कि समुद्रों में पहुंचने वाला करीब 80 फीसदी कचरा जमीन पर ठोस कचरे के कुप्रबंधन से जुड़ा है जो भूमि से जुड़े समुद्री मार्गों के जरिए समुद्र तल तक पहुंच रहा है। वहीं बाकी 20 फीसदी कचरा तटीय बस्तियों से समुद्रों में जा रहा है। उनके मुताबिक अधिकांश प्लास्टिक कचरे के लिए समुद्र तल एक विश्राम स्थल बन गया है, जहां एक करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक के जमा होने का अनुमान है। टोरंटो विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र और अध्ययन से जुड़ी शोधकर्ता एलिस झू ने जानकारी दी है कि समुद्र तल पर मौजूद प्लास्टिक कचरे की मात्रा समुद्र की सतह पर तैरते प्लास्टिक से 100 गुणा अधिक हो सकती है। उनके मुताबिक समुद्र की सतह प्लास्टिक का एक अस्थाई विश्राम स्थल है। ऐसे में इस बात की उम्मीद है कि यदि हम प्लास्टिक को समुद्रों में प्रवेश करने से रोक सकें तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। हालांकि रिसर्च से पता चला है कि यदि यह प्लास्टिक इसी तरह गहरे समुद्र में जाता रहा तो वो इस प्लास्टिक कचरे का एक स्थाई विश्राम स्थल बन जाएगा।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर साल औसतन 40 लाख से 2.3 करोड़ मीट्रिक टन के बीच प्लास्टिक समुद्रों में समा रहा है। इतना ही नहीं जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक उत्पादन बढ़ा है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या बन चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में वैश्विक स्तर पर सालाना होता प्लास्टिक उत्पादन बढ़कर 40 करोड़ टन से ज्यादा हो गया था, जो पिछले साल की तुलना में करीब 1.6 फीसदी अधिक है। इसमें से करीब 35 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे के रूप वापस आ रहा है। विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि 2050 तक हम 2,600 करोड़ मीट्रिक टन नए प्लास्टिक का उत्पादन कर लेंगे। अफसोस की बात है कि इस प्लास्टिक का करीब आधा कचरे का हिस्सा बन जाएगा। इस बारे में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक: पॉलिसी सिनेरियोज टू 2060 से पता चला है कि 2060 तक हर साल पैदा होने वाला यह प्लास्टिक कचरा अब से करीब तीन गुना बढ़ जाएगा। जो अगले 37 वर्षों में बढ़कर 101.4 करोड़ टन से ज्यादा होगा।

शोधकर्ताओं ने अपने इस अध्ययन में समुद्र तल पर जमा प्लास्टिक की मात्रा और उसके वितरण का पता लगाने के लिए रिमोट से चलने वाले वाहनों (आरओवी) से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया है। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक समुद्र तल पर 30 लाख से 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि आमतौर पर प्लास्टिक महाद्वीपों के आसपास इकट्ठा होता है। शोधकर्ताओं का यह भी अनुमान है कि समुद्र तल पर मौजूद प्लास्टिक के कुल वजन का करीब 46 फीसदी 200 मीटर की गहराई में जमा हो सकता है। वहीं इसका 54 फीसदी भाग समुद्र की गहराई में 200 से 11,000 मीटर की गहराई में होने का अंदेशा है। इससे जलीय जीवों के साथ ही मानव के जीवन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो घातक सिद्ध हो सकता है।

● अक्स ब्यूरो

समुद्री जीवन पर बढ़ा खतरा

शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि भले ही अंतर्देशीय और तटीय समुद्र, महासागरों की तुलना में बहुत कम क्षेत्र को कवर करते हैं, लेकिन उनमें समुद्र तल के बाकी हिस्से के बराबर प्लास्टिक जमा होने की आशंका है। बता दें कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 56 हिस्से पर महासागर काबिज हैं, जबकि 11 फीसदी हिस्से पर अंतर्देशीय और तटीय समुद्र मौजूद हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह निष्कर्ष हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं कि प्लास्टिक समुद्र में कैसे व्यवहार करता है। गहरे समुद्र में प्लास्टिक के प्रवाह और जमा होने के कारणों को समझने से इसके बढ़ते प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह समुद्री जीवन पर बढ़ते खतरों को भी सीमित करने में मददगार होगा।

मिडिल-ईस्ट संकट पर चीन चुप...

महान शक्तियों की पहचान संघर्षों में मध्यस्थता करने और अन्य देशों पर प्रभाव जमाने की उनकी क्षमता से होती है। फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों को इस मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चीन द्वारा 2023 में सऊदी अरब-ईरान समझौते में सफलतापूर्वक मध्यस्थता करने के बावजूद, चल रहे संघर्षों में इसकी प्रभावशीलता के बारे में संदेह बना हुआ है। इजरायल-हमास संघर्ष छह महीने से अधिक समय से जारी है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, और इस विवाद में अन्य देश भी शामिल हो रहे हैं। 13 अप्रैल 2024 को, इजरायल पर ईरान के जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले ने तनाव बढ़ा दिया और पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया।

अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं में से एक में, चीन ने सभी संबंधित पक्षों से आगे की स्थिति को रोकने के लिए संयम बरतने का आग्रह किया। अपने ईरानी समकक्ष होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर हमले की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। हालांकि, इस वाद-विवाद में यह बात नोट करने लायक थी कि इजरायल के लिए उसी तरह की सख्त भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। ईरान के लिए एक मजबूत डिक्लेरेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, जिसे क्षेत्रीय संप्रभुता के उल्लंघन के खिलाफ आत्मरक्षा के कार्य के रूप में तैयार किया गया था। चीन ने कहा कि दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला 1999 में बेलग्रेड में चीनी दूतावास पर नाटो द्वारा किए गए हमले की तरह था। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन सक्रिय भागीदारी से पीछे हट रहा है, जो संभावित रूप से गाजा युद्धविराम के लिए उसके समर्थन के कारण विवश है, जबकि इजरायल जोरदार पश्चिमी समर्थन प्राप्त कर रहा है। यह कहावत मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है... इस संदर्भ में पूरी तरह से ईरान पर लागू होती प्रतीत होती है, क्योंकि चीन इजरायल पर प्रभाव डालने के लिए संघर्ष कर रहा है।

ईरान-इजरायल संघर्ष पर चीन की प्रतिक्रिया पश्चिम के रुख से बिल्कुल विपरीत है, जो मुख्य रूप से इजरायल समर्थक है। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच चल रही प्रभुत्व को स्थापित करने की प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन का रणनीतिक झुकाव अमेरिका की खुले तौर पर आलोचना करने वाले देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है, जिससे ईरान की आलोचना करने में अनिच्छा पैदा होती है। चीन ने लगातार टू-स्टेट समाधान का समर्थन और वकालत की है और अक्सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2728 का संदर्भ दिया है, जो इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में तत्काल युद्धविराम की मांग करता है। जबकि चीन ने सक्रिय रूप से खुद को शांति के लिए मध्यस्थ के रूप में तैनात किया है, खासकर मध्य पूर्व में, जहां वह अमेरिकी प्रभाव को कम करना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि कभी-कभी इसे अपने घोषित लक्ष्यों से भटका देती हैं। ये बाधाएं चीन की अपनी साझेदारियों और हितों से उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से, चीन ईरानी तेल के शीर्ष आयातक के रूप में उभरा है, जिसने 2023 में देश के तेल निर्यात का 90 प्रतिशत हासिल किया है। इस प्रवृत्ति को अटलांटिक काउंसिल के एक लेख में स्पष्ट किया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है- चीन के रीजनल प्लेयर बने रहने की अधिक संभावना है, यह एक दशक से था, जो कि मध्य पूर्व में व्यापार और निर्माण के लिए आया है, न कि नेतृत्व करने के लिए।

मौजूदा शांति समझौतों के संरक्षण को प्राथमिकता देना उस क्षेत्र के भीतर जटिल वार्ता शुरू करने की तुलना में एक सतर्क दृष्टिकोण के रूप में उभरता है जहां चीन का प्रभाव कई हितधारकों के बीच सीमित है। 15 अप्रैल को, जिस दिन वांग और अब्दुल्लाहियन ने बात की, उसी दिन चीनी विदेश मंत्री ने अपने सऊदी समकक्ष, फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी संपर्क किया, और ईरान के अन्य क्षेत्रीय राज्यों के प्रति गैर-लक्षित कार्यों पर जोर दिया। पहले से मौजूद सौदों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, चीन उन कार्यों से बचना चाहता है जहां उसका प्रभाव सीमित है और संभावित बाधाएं सामने आती हैं, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर जोखिम कम हो जाता है। बहरहाल, चीन के सीमित प्रभाव और हस्तक्षेप करने में उसकी अनिच्छा के बारे में चीनी सोशल मीडिया यूजर्स के बीच अलग-अलग धारणाएं हैं। एक वीबो यूजर (2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ) ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की विडंबना पर प्रकाश डाला, जिसमें तनाव कम करने के लिए ईरान पर चीन द्वारा उसके प्रभाव का लाभ उठाने का आग्रह किया, जबकि वॉशिंगटन साथ ही साथ फिलीपींस और चीन के बीच तनाव पैदा करता है। ईरान और इराक के बीच ताजा मुकाबले की खासियत यह थी कि टक्कर दूर से ही ली जा रही थी। गोला-बारूद के मामले में अपनी-अपनी ताकत की आजमाइश हवा में या जमीन पर बनाए अड्डों से ड्रोन और मिसाइलों से हमलों के जरिए की जा रही थी। इस बार फर्क यह था कि दोनों देशों ने अपनी-अपनी फौजी ताकत दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर आजमाने की कोशिश की। टकराव का ताजा कारण दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एक अप्रैल को इजरायली हमला बना। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों के मुताबिक इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना।

● **कुमार विनोद**

चीन शांत क्यों है?

ईरान-सऊदी अरब समझौते के समापन के बाद से, संघर्षों में मध्यस्थता करने की चीन की क्षमता बाधित हो गई है। इसने रूस-यूक्रेन और इजराइल-फिलीस्तीन दोनों संघर्षों में कुछ हद तक स्पष्ट रुख अपनाया है। जबकि चीन संभावित स्पिलओवर प्रभावों के बारे में आशंकित है, वह वर्तमान में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक प्रतीत होता है। बीजिंग की रणनीति में इजरायल के साथ सीधे टकराव को दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अपने तालमेल को संतुलित करना शामिल है। प्राथमिक उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना और तेहरान-रियाद सौदे में किसी भी व्यवधान को रोकना है, साथ ही ईरान के साथ संबंधों को मजबूत करना भी है। इसके अतिरिक्त, चीन आर्थिक चुनौतियों और दक्षिण चीन सागर और ताइवान से जुड़ी जटिलताओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, मध्य पूर्व में सक्रिय भागीदारी हाल-फिलहाल में होती हुई नहीं दिखती है। यह रुख चीन के सतर्क दृष्टिकोण और अपने हितों को प्राथमिकता देने की बात को दिखाता है, जिसका अर्थ है कि विशेष रूप से मध्य पूर्व में एक जिम्मेदार शक्ति या यहां तक कि मध्यस्थ की भूमिका निभाना फिलहाल ठंडे बस्ते में है।

> जब से इंटरनेट का जमाना आया है, तब से सब एकल परिवारों में भी एकांत में रहना पसंद करने लगे हैं। रिश्ते-नाते बिखर रहे हैं। प्यार और स्नेह औपचारिकता के समान रह गए हैं। सब भावनाएं वाट्सएप और फेसबुक पर सिमटते जा रहे हैं। आज एकल परिवारों में सबसे ज्यादा उपेक्षा के शिकार बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं।

रिश्तों की डोर

एक समय था, जब भारत में परिवारों का आकार बड़ा होता था। घर के सभी सदस्यों का साथ रहना होता था। सबका खाना साथ बनता और सभी साथ में बैठकर खाना खाते थे। यहां संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएं और मूल्य श्रेष्ठ रहे हैं। ये सभी हमारे संयुक्त परिवार में बखूबी देखे जा सकते हैं। घर में पूरे दिन चहल-पहल रहती थी, जिससे पूरे दिन घर के अंदर खुशी का माहौल बना रहता था। कभी-कभार लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन घर के अंदर प्यार-मोहब्बत भी अथाह होती थी। खट्टे-मीठे अनुभव ऐसे ही चलते रहते थे। अनेक मौकों पर परिवार में खुशी का माहौल देखते ही बनता था। मगर आज बड़ी विडंबना है कि पुराने वक्त का संयुक्त परिवार अब ऐसे एकल परिवारों में परिवर्तित हो गया है, जहां रिश्तों की डोर टूट रही है।

सबसे ज्यादा गहरा संबंध माता-पिता का होता है। आज इसी रिश्ते की अनदेखी होती जा रही है। एकल परिवार होने के बाद ताऊ-ताई, चाचा-चाची और उनके बच्चे पीछे छूटते जा रहे हैं। सब लोग एकांत में रहना पसंद करने लगे हैं। बेटा-बेटी हो या फिर बेटे की बहू, सभी अपनी-अपनी जिंदगी जीना पंसद करने लगे हैं। रिश्तेदारियों में प्यार-मोहब्बत दूर की बात हो चली है। अब तो लोग आपस में बोलना भी छोड़ देते हैं। संयुक्त परिवारों में सब रिश्ते-नाते एक बंधन में बंधे होते थे, जो आज के एकल परिवारों में छिन्न-भिन्न हो चुके हैं। हम सब इन रिश्तों की मर्यादा को पीछे छोड़कर स्वार्थ की जिंदगी जीने लगे हैं और अपने-अपने स्वार्थ का हल खोजने में लगे हैं।

एक समय जब भी किसी बड़े-बुजुर्ग या बच्चों को कोई भी समस्या होती तो घर के अन्य सदस्यों द्वारा आपस में मिल-बैठकर समाधान किया जाता था। घर के मुखिया पर सबकी जिम्मेदारी होती थी। बुजुर्गों द्वारा आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ मिलकर रहने की सभ्यता का परिचय कराया जाता है। यह एक प्रकार से समाज की आवश्यकता है। इन परिवारों में अपनापन होता है। संयुक्त परिवार में एक अच्छे समाज की संरचना होती है। जबकि आज सब अपने-अपने स्वार्थ में जीने लगे हैं।

एक-दूसरे की भावनाओं को समझना और त्याग की भावना खत्म होती जा रही है। युवा पीढ़ी बुजुर्गों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। शायद इस भौतिकवादी युग में उन्हें धन ओर स्वयं की ही जिंदगी जीने की सबसे बड़ी चीज दिखती है। परिवार कुछ लोगों के साथ मिलकर रहने से नहीं बनता, बल्कि इसमें रिश्तों की मजबूत डोर के सहयोग के साथ अटूट रिश्तों का बंधन होता है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में परिवारों की मान्यताएं बदलती जा रही हैं। पिछले दो दशक से पारिवारिक पद्धति, खासकर संयुक्त परिवार के रूप में काफी बदलाव आया है। संयुक्त परिवारों में एक-दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है। एकल परिवार में व्यक्तिगत भावना उत्पन्न हो जाती है, जो रिश्तों पर हावी होने लगती है। जहां इस प्रकार की भावना होती है, वहां स्वार्थ आ जाना स्वाभाविक है। परिवार हमेशा मर्यादाओं से बनते हैं, जहां कर्तव्य और अनुशासन होते हैं। आज रिश्तों की डोर में गांठें पड़ने लगी हैं। अक्सर बुजुर्गों से सुना जा सकता है कि हमारे जमाने में बीस-पचीस लोग होने के बावजूद परिवार हंसी-खुशी से रहता था।

आज के एकल परिवार में वह सब कहां हैं। जिस परिवार में एकता होती है, वहां समृद्धि और शांति के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं, जिसमें आपसी प्यार, स्नेह, सौहार्द और परस्पर विश्वास है। उस समय के संयुक्त परिवारों में बच्चों को दादा-दादी ओर अन्य लोग शिक्षाप्रद कहानी सुनाकर उनका मनोरंजन करते थे। सब बच्चे अपने बुजुर्गों के सानिध्य में रहते थे। इतने बड़े परिवार में बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना यह हो चुकी है कि वसुधैव कुटुंबकम् वाली परंपरा समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है।

दरअसल, जबसे इंटरनेट का जमाना आया है, तब से सब एकल परिवारों में भी एकांत में रहना पसंद करने लगे हैं। रिश्ते-नाते बिखर रहे हैं। प्यार और स्नेह औपचारिकता के समान रह गए हैं। सब भावनाएं वाट्सएप और फेसबुक पर सिमटते जा रहे हैं। आज एकल परिवारों में सबसे ज्यादा उपेक्षा के शिकार बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। सब अपने-अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि रिश्ते तो दूर, लोग अपने बच्चों ओर माता-पिता को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। बुजुर्ग घर के एक कोने में पड़े दिन काटने पर मजबूर हैं।

किसी समय छुट्टियों में अपने नाना-नानी के घर जाने पर बच्चों के भीतर जो खुशी होती थी, वह एक अलग ही अहसास कराती थी। उस समय रिश्तों को बोझ नहीं समझा जाता था, बल्कि रिश्तों की जरूरत समझी जाती थी। अब यह सब आधुनिक जीवन में सिर्फ सपने रह गए हैं और परिवार के विचारों में भिन्नता आने लगी है। आज दिखावे की होड़ में पड़कर हम सिर्फ अपना स्वार्थ हल करने पर लगे हुए हैं। हमने अपने कर्तव्यों ओर मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। अपने दायित्वों को भूल चुके हैं।

आज शहरों-महानगरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, दड़बे की तरह बहुमंजिला इमारतों में हजारों लोग रहते हैं, मगर सब अलग-अलग। किसी के दुख-सुख से किसी को मतलब नहीं। कभी सामूहिक आयोजन होता दिखता भी है तो वह बस किसी तरह औपचारिकता निभाने की तरह होती है। संवेदनात्मक लगाव के तत्व अनुपस्थित रहते हैं। ऐसे में लोगों को तब परिवार की कमी खलती है जब किसी आपात स्थिति में किसी अपने की जरूरत महसूस होती है। कभी लगता है कि कोई पास होता, जिससे अपने दुख बांटे जा सकते या खुशी साझा की जा पाती।

● ज्योत्सना

हर समस्या का समाधान रामचरित मानस

रामचरितमानस जिसे तुलसीदास द्वारा रचा गया है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। रामचरितमानस में दी गई दोहे और चौपाइयों से मानव मात्र को प्रेरणा मिल सकती है। इस पवित्र ग्रंथ में मनुष्य की हर समस्या का हल मिल सकता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जो लोग रोजाना रामचरितमानस के पाठ करते हैं, उनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहती है। मनुष्य का जीवन तीन भाव से बना है, पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, शोक यानी की दु:ख और भय मतलब डर। अक्सर सफलता के रास्ते में डर रुकावट पैदा करता है। आमतौर पर इस डर को कम करने के लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती हैं।

हम सभी के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार रास्ते नजर नहीं आते। तुलसीदास द्वारा लिखी गई श्रीरामचरितमानस की चौपाइयों में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। माना जाता है कि इसका पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति, भय, रोग आदि सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन जीने को लेकर नई प्रेरणा की भी प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उन चमत्कारी चौपाइयों व उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से।

हरि अनंत हरि कथा अनंता।
कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता॥
रामचंद्र के चरित सुहाए।
कलप कोटि लगि जाहिं न गाए॥

इसका अर्थ है कि हरि अनंत हैं उनका कोई पार नहीं पा सकता है। उनकी कथा भी अनंत ही है। सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते-सुनते हैं। साथ ही ये पक्तिंया कहती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई बखान नहीं कर सकता क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते।

जा पर कृपा राम की होई।
ता पर कृपा करहिं सब कोई॥
जिनके कपट, दम्भ नहिं माया।
तिनके हृदय बसहु रघुराया॥

इसका अर्थ है जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दु:ख छू नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर तो सभी की कृपा बनी ही रहती हैं। जिसके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति राम बसते हैं। साथ ही उनके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव होती है।

अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर,
भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर।
काम क्रोध मद गज पंचानन,
बसहु निरंतर जन मन कानन।।

इसका अर्थ है कि हे गुणों के मंदिर! आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम, क्रोध, मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। आप हमेशा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हैं।

कहु तात अस मोर प्रनामा।
सब प्रकार प्रभु पूरनकामा॥
दीन दयाल बिरिदु संभारी।
हरहु नाथ मम संकट भारी॥

इस चौपाई का अर्थ है कि हे भगवान श्री राम! आपको मेरा प्रणाम और मेरा आपसे ये निवेदन है कि- हे प्रभु! अगर आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं अर्थात् आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन-दुखियों पर दया करना आपकी प्रकृति है, अत: हे नाथ! आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए।

होइहि सोइ जो राम रचि राखा।
को करि तर्क बढ़ावै साखा॥
अस कहि लगे जपन हरिनामा।
गईं सती जहं प्रभु सुखधामा॥

अर्थ है कि जो कुछ भी संसार में राम ने रच रखा है, वही होगा। इसलिए इस विषय में तर्क करने का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु राम थे।

तुलसी काया खेत है,
मनसा भयो किसान।
पाप-पुन्य दोउ बीज हैं,
बुवै सो लुनै निदान।।

इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक खेत की तरह है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है। ठीक इसी तरह कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को पाप या पुण्य का फल मिलता है।

आवत हिय हरषै नहीं,
नैनन नहीं सनेह।
तुलसी तहां न जाइए,
कंचन बरसे मेह।।

इस दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि कैसे व्यक्ति के घर कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी के अनुसार, जिस घर में जाने पर घर के लोग आपको देखकर प्रसन्न न हों और जिनकी आंखों में बिलकुल भी स्नेह न हो, ऐसे लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां आपका कितना भी लाभ छिपा हो।

जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं।
सुख संपति नाना बिधि पावहिं॥
सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं।
अंतकाल रघुपति पुर जाहीं॥

यानी जो मनुष्य सकामभाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत् में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथजी के परमधाम को जाते हैं॥2॥

प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई।
हारहिं सकल सलभ समुदाई॥
खल कामादि निकट नहिं जाहीं।
बसइ भगति जाके उर माहीं॥

यानी अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मंदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में प्रभु राम की भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि नकारात्मक चीजें तो उसके पास भी नहीं जाते।

● ओम

मत का प्रयोग

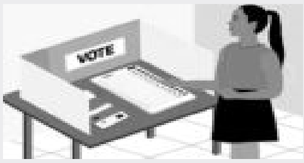

भारत मां की लाज बचाने,
हर इक पहरेदार बनो
चोरों को देकर मत अपना,
तुम भी ना गद्दार बनो।
दीमक गर लग जाए तो,
पूरी लकड़ी सड़ जाती है
अमरबेल लदकर पेड़ों की,
हरियाली हर जाती है
त्याग के अपने मतलब सारे,
थोड़े तो खुद्दार बनो
चोरों को देकर मत अपना,
तुम भी ना गद्दार बनो।
याद रखो उनको जो सरहद पर,
कट मर जाते हैं
मात-पिता, घर-द्वार छोड़कर,
माटी में मिल जाते हैं
सौंप के सत्ता जालिमों को,
ना अपयश हकदार बनो
चोरों को देकर मत अपना,
तुम भी ना गद्दार बनो।।
सीमा पर लड़ना बैरी से,
शायद है आसान बहुत
लेकिन छिपे हुए दुश्मन से,
हम-तुम हैं अनजान बहुत
संसद की रक्षा करने को,
अब तो जिम्मेदार बनो
चोरों को देकर मत अपना,
तुम भी ना गद्दार बनो।।
कारा की दीवारें भी जब,
बेबस और लाचार हुईं
तब वोटों की ताकत ही,
केवल इक उपचार हुई
मसि पर धार लगाई मैंने,
अब तुम भी तलवार बनो
चोरों को देकर मत अपना,
तुम भी ना गद्दार बनो।।
भारत की पंचायत को अब,
नागों से भयमुक्त करो
आस्तीन में सांप ना पालो,
बांबी सारी नष्ट करो
कुचलो फन सारे विषधर के,
राम-कृष्ण अवतार बनो
चोरों को देकर मत अपना,
तुम भी ना गद्दार बनो।।

- शरद सुनेरी

निर्णय

नाम करेगा रोशन मेरा नन्हा राज दुलारा... गाना गुनगुनाती हुई नीलम जल्दी-जल्दी घर के काम निपटा रही थी। नहाने के बाद चाय लेकर रिशु के कमरे में आ बैठी थी। सामने दीवार पर ट्राफी लिए हुए अनूप कुमार की तस्वीर देखकर ख्यालों में खो गई थी कि सब्जी वाले की आवाज गूंजी- सब्जी ले लो, तोरई, गाजर, मटर, आलू ले लोओओ...!

भैया रुको, मैं आती हूं! भागती हुई आकर बालकनी से बोली।

बेटा रिशु! चल साथ में। ज्यादा सब्जी लेनी है न, तू उठा ले आना।

जी मम्मा, आप चलिए मैं आता हूं। बस थापर सर द्वारा दी गई कामयाबी के टिप्स लिख लूं!

जल्दी आना!

हां मम्मा, आपके खरीद चुकने से पहले आपके पास होऊंगा।

टमाटर कैसे दिए भैया।

चालीस रुपये में दीदी जी।

इतने महंगे! न, न, तीस रुपए में दो तो बोलो, हमें तीन चार किलो लेना है। राष्ट्रीय कबड्डी टीम में मेरे बेटे के सेलेक्शन होने की खुशी में कल पार्टी है न।

अरे वाह दीदी जी, फिर तो आप मेरी तरफ से फ्री में ले लीजिए। सब्जी वाला खुश होकर बोला।

अचानक सर-सर कहते सुन ठेल से नजर उठाते ही नीलम ने रिशु को सब्जी वाले के कदमों में झुका हुआ देखा।

रिशु...? नीलम हतप्रभ हो बोली।

मम्मा तुम नहीं जानती इन्हें? यही तो हैं मेरे अदृश्य गुरु! गोल्ड मेडिलिस्ट, जिनकी मैं दिन रात पूजा करता हूं। आज ये मुझे मिल गए, अब साक्षात इनसे ही सीखूंगा मैं।

बोलिये न थापर सर, आप सिखाएंगे न मुझे कबड्डी में कामयाबी के ट्रिक?

नीलम की खुशी अब काफूर हो गई थी। उसके सामने तराजू का पलड़ा नहीं बल्कि बेटे का वर्तमान और भविष्य ऊपर-नीचे हो रहा था।

अचानक नीलम के माथे पर बल पड़ गए। सब्जी वाले से बोली- भैया! टमाटर बस आधा केजी ही देना।

- सविता मिश्रा 'अक्षजा'

करवा चौथ

आज पुनिया पूरे सज-धज के काम पर आई थी। ऐसे तो रोज अस्त-व्यस्त सी आ जाती थी।

मैंने उससे पूछा, क्यों री पुनिया, आज तो तू बड़ी सजी-धजी है क्या बात है?

उसने मुस्कुराते हुए कहा- दीदी, आज करवाचौथ है न।

अच्छा, पर ये बता तेरा घरवाला तो दूसरी औरत के पास रहता है। तेरे पास तो कभी आता भी नहीं है फिर भी तू उसके लिए करवाचौथ का व्रत रखती है?

उसने शरमाते हुए कहा- तो क्या हुआ मेम साहब, किसी के पास रहे पर सलामत रहे। उनको मेरी उमर लग जाए। वो है तो मेरा सुहाग है। हर स्त्री चाहती है कि उसका सुहाग अमर रहे। बस वो सुखी रहे। मैं यही कामना करती हूं।

यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई।

- डॉ. शैल चन्द्रा

आईपीएल में उभरी नई प्रतिभाएं

आईपीएल के घमासान के बीच एक जून से शुरू होने वाले फटाफट क्रिकेट का महाकुंभ यानी टी-20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खेलती दिखेगी। वहीं, हार्दिक पांड्या उपकप्तानी करते दिखेंगे। टीम में दो विकेटकीपर शामिल किए गए हैं। इनमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन शामिल हैं। वहीं, केएल राहुल को टीम से बाहर कर दिया है। टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज शामिल हैं। वहीं शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रखा गया है।

इस बार आईपीएल में जिस तरह नए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कई खिलाड़ी इस टीम के दावेदार थे। भले ही उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने अपने खेल का लोहा मनवा दिया है। माना जा रहा था कि टीम चयन की बैठक के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी तवज्जो दी जाएगी। टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने जोर देकर कहा था कि आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर ही वर्ल्डकप के लिए टीम चुनी जाएगी। द्रविड़ ने माना था कि भारतीय खिलाड़ियों को आगामी टी-20 विश्व कप के लिए तैयारियों का मौका नहीं मिल पाया है। यानी आईपीएल का रोल काफी अहम होगा। ऐसी स्थिति में शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों ने धुआंधार बल्लेबाजी कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, वहीं 38 साल के दिनेश कार्तिक ने भी तूफानी बैटिंग करके दावेदारी पेश की। लेकिन इन तमाम दावेदारों में से शिवम दुबे को ही मौका मिला है। भारतीय टीम से तीन बड़े चेहरों को बाहर किया गया है, जो हाल फिलहाल में टीम इंडिया का हिस्सा थे। इनमें केएल राहुल के अलावा रिंकू सिंह और शुभमन गिल शामिल हैं। हालांकि, बीसीसीआई ने रिंकू और शुभमन को ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है। रिंकू पर शिवम दुबे को तरजीह दी गई है। काफी पहले से इस बात की चर्चा हो रही थी कि अगर हार्दिक को चुना जाता है तो शिवम-रिंकू में से किसी एक को ही मौका मिलेगा। वहीं, यशस्वी और शुभमन में से किसी एक को मौका देना था। चयनकर्ताओं ने यशस्वी को शुभमन पर तरजीह दी है। इस सीजन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे शिवम दुबे विश्वकप में अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्हें इस बार मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है और वह पारी को संभालने से लेकर मैच फिनिशर तक का रोल बखूबी निभा रहे हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 163.51 का है। उनके इस खेल की तारीफ साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी की है। भारत को 2007 टी20 विश्वकप और 2011 वनडे विश्वकप जिताने वाले पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी शिवम दुबे को शामिल करने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि शिवम लंबे-लंबे छक्के लगा रहे हैं और वह अंतर पैदा कर सकते हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला खूब बरस रहा है। खासकर इस बल्लेबाज ने अपनी हिटिंग पावर से खासा प्रभावित किया है। अभिषेक शर्मा तो 215.96 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग लगातार रन बना रहे हैं। इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरल का भी नाम उन तमाम खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक ने आईपीएल 2024 के अपने पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। शशांक की भी स्ट्राइक रेट लगभग 180 रही है, वहीं अभिषेक पोरेल ने 162.63 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। दिनेश कार्तिक की भी स्ट्राइक रेट लगभग 196 रही है। वहीं युवा गेंदबाजों ने भी अपनी धाक जमाई है। लखनऊ सुपर जाएंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मयंक ने खासकर अपनी स्पीड से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने अपनी गेंदबाजी से क्रिकेट प्रेमियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ध्यान खींचा है। शानदार लाइन और लेंथ के कारण वैभव अरोड़ा की गेंदों पर रन बनाने के लिए बल्लेबाज जूझते रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी वैरिएशन से सबका ध्यान खींचा है।

पंजाब किंग्स परंपरागत रूप से ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं रही है जो लंबे समय तक खिलाड़ियों में निवेश करना चाहती है। जब आईपीएल नीलामी में रोमांचक प्रतिभाओं को शामिल करने की बात आती है तो वे खूब पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रदर्शन खराब होने के बाद वे लंबे समय तक उसी प्रतिभा का समर्थन नहीं करते हैं। फ्रेंचाइजी के पास एक समय केएल राहुल, डेविड मिलर, पीयूष चावला और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन फॉर्म में गिरावट के बाद पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया। हालांकि, ऐसा लगता है कि परंपरा बदलने लगी है और उनके ड्रेसिंग रूम में हरप्रीत बराड़ की मौजूदगी इसका प्रमाण है। पंजाब ने आईपीएल 2019 की नीलामी में 20 लाख रुपए का भुगतान करने के बाद हरप्रीत बराड़ की सेवाएं हासिल कीं। फिर उन्होंने 3.80 करोड़ रुपए का भुगतान करके आईपीएल 2022 से पहले उन्हें बरकरार रखा, एक ऐसा कदम जो बाएं हाथ के रूढ़िवादी गेंदबाज में उनके विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। 28 वर्षीय बराड़ ने अपने पहले सीजन (आईपीएल 2019) में केवल दो गेम खेले और 2020 में एक अकेला गेम खेला। वह दोनों सीजन में एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अधिक अवसरों के लिए बेताब थे। आईपीएल 2024 में भी बरार बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में काफी प्रभावशाली रहे हैं। ऐसे सीजन में जहां पहले की तरह गेंद पर बल्ला हावी रहा है, बरार उन बहुत कम गेंदबाजों में से एक हैं जिन्होंने प्रति ओवर आठ से कम रन दिए हैं। उन्होंने मौजूदा आईपीएल सीजन में पंजाब के लिए 11 मैचों में 7.56 की शानदार इकोनॉमी रेट से छह विकेट हासिल किए हैं। जबकि पंजाब पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुका है, अगर वे सीजन पर विचार करते हैं और सकारात्मकता की तलाश करते हैं, तो हरप्रीत का उत्कृष्ट प्रदर्शन निश्चित रूप से पेकिंग ऑर्डर पर उच्च होगा।

● आशीष नेमा

धर्मेंद्र की वो फिल्म, जिसका दुनियाभर में बजा था डंका...

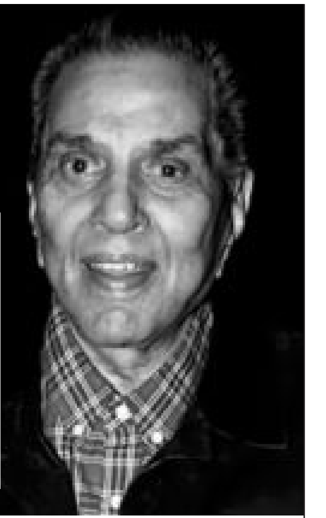

1977 में 50 हफ्ते तक सिनेमाघरों में किया राज

साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आज भी किसी न किसी फिल्मों में नजर आ ही जाते हैं। हाल ही में उन्हें शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था।

वहीं, पिछले साल आई रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी धर्मेंद्र नजर आए थे। मतलब, कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्मेंद्र पिछले 6 दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और उनकी कुछ फिल्में तो आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। आज हम धर्मेंद्र की उस फिल्म की बात करने जा रहे हैं, जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में रिलीज के साथ छा गई थी। 6 सितंबर 1977 में आई धर्मेंद्र की फिल्म धरम वीर ने बॉक्स ऑफिस पर खूब हंगामा मचाया था और कमाई के मामले में तो यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। धरम वीर एक एक्शन-ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था, और निर्माण महबूब स्टूडियो और आरके स्टूडियो बैनर के तहत सुभाष देसाई ने किया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जीतेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह और प्राण भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल कुछ समय के लिए अपने पिता के बचपन के किरदार को निभाते हुए दिखाई दिए थे। यह एक जुड़वां भाइयों धरम और वीर की कहानी पर बेस्ड है, जो जन्म के समय अलग हो जाते हैं, और बाद में जो बचपन में सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, यह नहीं जानते हुए कि वे असली भाई थे, बाद में खलनायकों की साजिशों के कारण वे एक-दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और अंत में फिर से एकजुट हो जाते हैं।

रिलीज से पहले ही बन गई थी ब्लॉकबस्टर... थिएटर में रिलीज होने पर यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई थी। विकिपीडिया के अनुसार, भारत में फिल्म 13 करोड़ की कमाई करने में सफल रही थी। विदेशों में यूनाइटेड किंगडम के 5 शहरों में फिल्म के 23 शो हुए थे। मोहम्मद रफी के गानों की सफलता से प्रेरित होकर, फिल्म ने यूके में 4 लाख 38 हजार की कमाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म सिनेमाघरों से उतरने का नाम नहीं ले रही थी और लगभग 50 हफ्ते तक यह थिएटर्स में चली थी। दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी और आज भी यह फिल्म लोगों के बीच काफी मशहूर है।

मिथुन चक्रवर्ती को प्लेन में देख फूट-फूटकर रोई थी एक्स गर्लफ्रेंड, मानी अपनी गलती

मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन सफलता पाने के लिए उन्हें संघर्ष भी बहुत करना पड़ा था। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पुराने दिनों का किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें स्ट्रगल के दिनों में छोड़कर चली गई थी और जब दोबारा मुलाकात हुई थी तो वे उनके सामने फूट-फूटकर रोई थी।

सारेगामापा शो में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं इश्क में पागल हो गया था। फिर वही हुआ, लड़की छोड़कर चली गई। फिर समय बदला। मैं स्टार से सुपरस्टार बन गया। एक दिन मैं प्लेन में सफर कर रहा था। वो लड़की भी सफर कर रही थी, लेकिन वो मुझसे नजर चुरा रही थी। मुझे लगा कि वह गिल्ट में है, तो उसे शांत करने के लिए मैंने कहा कि उस समय तुमने जो किया वह सही था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस इंसान के पास खाने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है उसके साथ कोई क्या फ्यूचर बनाएगा। मैंने उस लड़की को कहा कि तुमने सही फैसला किया था। ये सुनकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने गलती की है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने बोला कि अगर तुम ये नहीं करती, तो मैं शायद लेजेंड नहीं बन पाता।

एलएसडी से नहीं, दूसरी फिल्म से बॉलीवुड में हुई थी राजकुमार राव की एंट्री

राजकुमार राव इन दिनों फिल्म श्रीकांत को मिल रही सराहना को एन्जॉय कर रहे हैं। फिल्म में उनकी अदाकारी की ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक, सब तारीफें कर रहे हैं। राजकुमार ने साल 2010 में लव सेक्स और धोखा बॉलीवुड में कदम रखा था। लेकिन एलएसडी से करियर की शुरुआत करने से पहले राजकुमार राव को फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म रण में देखा गया था। फिल्म में उनका सिर्फ एक लाइन का डायलॉग था। वह एक न्यूजरीडर के छोटे से

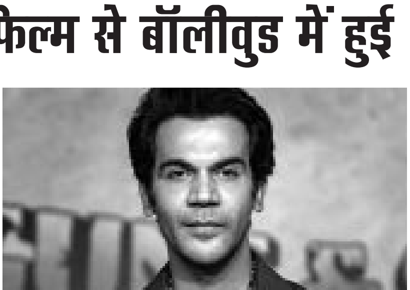

रोल में थे। राजकुमार ने पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि उन्हें वह रोल कैसे मिला।

राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में बताया, मुझे एक लाइन मिली थी। रामू की फिल्म रण में मेरी एक लाइन थी। हम सभी काम की तलाश में थे, और हमें पता चला कि राम गोपाल वर्मा रण नाम की फिल्म बना रहे हैं और वहां ऑडिशन चल रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं था कि ऑडिशन होता क्या है। राजकुमार राव ने कहा, तो, हम बस वहां गए और किसी ने मुझसे दो लाइन्स पढ़ने के लिए कहा, और मैंने पढ़ा। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, आपका हो गया है।

दाल गल रही है

दाल गलना एक मुहावरा है। दाल न गलना यानि काम न होना। लेकिन जिस तरह आजकल महंगाई बढ़ रही है उसे देखकर कहना पढ़ता है कि महंगाई की दाल खूब गल रही है। अरहर की दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। यही दाल है जो भारतीय परिवारों में रोज खाई जाती है। दाल अरहर की है पर इसे बांटने में दिल्ली सरकार की जो खिचड़ी बन रही है, वो बीरबल की खिचड़ी की याद दिला रही है। दाल ऐसा शेयर बन चुकी है जिसकी कीमत गिरती नहीं है और काबू में नहीं आ रही है। हाल ये है कि कीमतें बढ़ने की बजाय तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही हैं और वो भी आम आदमी की जेब दर जेब, आंख दर आंख और कंधा दर कंधा मिलाकर बिल्कुल अंधा करती हुई।

अगर तकनीक का उपयोग अथवा दुरुपयोग करके दाल की फोटोप्रतियां करवा कर प्रयोग में लाई जा सकतीं तो वैसी फोटोकापियर मशीनों का भविष्य दाल से अधिक अरहरा (सुनहरा की तर्ज पर) हो गया होता। दालों पर बने मुहावरे ये मुंह और मसूर की दाल की जगह अब यह मुंह और अरहर की दाल लेने ही वाले हैं। दाल की इस ऐतिहासिक तेज छलांग ने मुर्गियों की कीमतों को इस तरह धराशायी कर दिया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरा भी अपना अर्थ खो चुका है। दाल के दाम मुर्गी के दाम को छू रहे हैं। लगता है जल्दी ही ये उससे भी आगे निकल जाएंगे।

सब्जियों की कीमतें उछलती कूदती रहती हैं। पर उनका फुदकना बचपन के फुदकने जैसा है। दाल का फुदकना वयस्क बात है। यह तो राहत बांटने के साथ ही आहत करती चलती हैं। सब्जियों का उछलने-कूदने का जज्बा उन्हें सदा सुर्खियों में बनाए रखता है, पर दाल की तो यह तानाशाही है। उसके दाम जो एक बार बढ़ते हैं तो फिर बढ़ते ही हैं, उनमें गिरावट का कोई अंश नजर नहीं आता जबकि बढ़ते दाम का दंश देश के आम-खास हर वंश को आतंकित कर रहा है। सब बिलबिला रहे हैं पर कर इतना भी नहीं पा रहे हैं कि इससे मुक्ति का कोई शाश्वत उपाय हासिल कर सकें।

पहले दे दाल में पानी वाला मुहावरा काफी प्रचलन में रहा है पर आज यह मुहावरा कम जरूरत ज्यादा बन गया है। जूतियों में दाल बंटना ने दाल को दलित श्रेणी में शुमार कर दिया था परंतु अब बाजी पलट गई है। दालों का दाना-दाना दमदार हो गया है। किसी की क्या मजाल कि जो इनकी शान में, इनके टूटे दाने के बारे में भी हल्की सी भी बयानबाजी कर सके। दालों के दाम अपने आप बढ़ना स्वयंभूत ऐसी प्रक्रिया है जो दाल खाने के आदी लोगों को जीते जी भूत बना रही है। जबकि ये सब जानते हैं कि भूत न दाल खाते हैं न भात पर जो अपने जीवन में दाल भात न खा पाएं वे अवश्य भूत बनते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं।

दालों का धुली होना एक अलग श्रेणी है पर धुली अरहर का ध बदस्तूर कीमतों को जिस प्रकार धक्का दिए जा रहा है, वो अनुभूत है पर दुखद है। न जाने यह सत्ता से और घर से किस-किस को धकेल कर मानेगा। वैसे एक सच्चाई जान लें कि एक व्यक्ति जो पहले एक मुट्ठी दाल खाता था, दाम बढ़ने के बाद उसका पूरा परिवार अब एक मुट्ठी दाल मुश्किल से खा पाता है। आजकल पानी भी खुलकर नहीं मिल रहा है, नहीं तो दाल में पानी दे देकर काफी अतिथियों को निबटाया जाता रहा है। आपने सुना ही होगा तीन बुलाए तेरह आए- दे दाल में पानी। पर लगता है पानी भी हड़ताल पर है। जहां होना चाहिए वहां नहीं होता और जहां नहीं होना चाहिए वहां भरपूर होता है। दाल और पानी में यही भेद है। आप चाहें तो दाल को अधिक दाम देकर अपना बना सकते हैं, गोदामों में बसा सकते हैं पर अगर आपने पानी के साथ ऐसा किया तो वो जरूर आपको डुबा ही देगा, या कह सकते हैं कि डुबाकर भी मान जाए तो खैर मनाइएगा।

खैर सलाह सिर्फ यह है कि दाल को दिल पर न लें। इससे दिल खतरे में पड़ सकता है। महंगी हो जाने के बाद जल्द ही डॉक्टरों द्वारा दाल खाने की सलाह दी जाने लगेगी। दालें डॉक्टरों के लिए भी कमाई का एक नया जरिया बन जाएंगी। वे दाल बेचने वालों से कमीशन लेकर पर्चे पर लिखेंगे- पांच दाने मूंग की दाल का दिन में एक बार सेवन करें अथवा दिन में तीन बार अरहर की 100 ग्राम कच्ची दाल का दर्शन करें।

अभी तो अरहर में ही अरहरापन आया है। जल्दी ही और दालें इस रोग से संक्रमित हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो चने की दाल में चनापन (कड़ापन) आएगा और, मसूर की दाल (कसूरवार) बन जाएगी। अवाम को इनसे न उलझने की चेतावनी दी जाती है। कोई आश्चर्य नहीं दाल की मौजूदगी किराना दुकानों से हटकर दवाई की दुकानों में कब्जा जमा ले। ऐसा भी हो सकता है कि ब्यूटी पार्लरों में इसके शेल्फ लग जाएं जहां रूप गर्विताओं को सलाह दी जाएगी कि उबले चावलों के ऊपर दस दाने अरहर के सजाने से जो अरहरापन आ जाता है, वो सोने के हार में रत्नों के पचास नग सजाने में भी नहीं आता। इसलिए दाल अब दलित नहीं रही। गरीबों की दाल अब अमीरता के अमरत्व को प्राप्त कर चुकी है। सोने की कीमतों से मुकाबला करती दाल अब सोने को मात दे रही है। जल्द ही बाजारों में दालजड़ित आभूषण और परिधान अपनी पैठ जमाएंगे।

आढ़तियों के कब्जे से निकल फैशन के मंचों पर लहराती दाल इतराने लगे तो दाल का दोष नहीं। दोष दाल को दाल न रहने देने वालों का है, इससे राजनीति करने वालों का है। रूप रंग देखें तो स्वर्णता ही दाल की अमरता है और भूखे को तृप्त करने में ही इसकी सार्थकता है। ऐसा न हो कि एक ओर लोग भूखे मरें और दूसरी ओर लोग इसे गहनों में जड़वाएं। इसका निवास तो भोजन के महल में तृप्ति के सिंहासन पर ही है। इसे इसके इस अनमोल सिंहासन से उतारना किसी के बूते की बात नहीं और यही अरहरापन लुभा गया है मुझको।

● **अविनाश वाचस्पति**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
प्लस
चैम्पियन
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

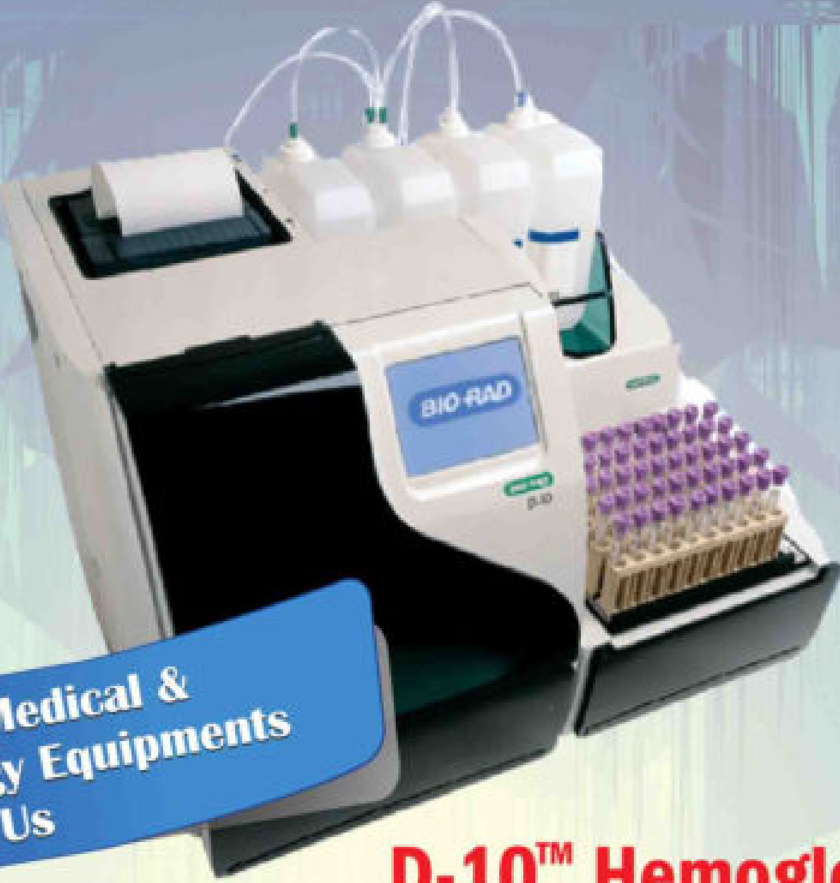

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress- and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687